

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15



राष्ट्रीय अपदा प्रबंधन संस्थान
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

5-बी, आईआईपीए कैम्पस, आईपी इस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110002

टेलीफोन कैक्स - 011-2370 2432, 2370 5583, 2376 6146

टेली फैक्स - 011-23702442, 23702446

वेबसाइट : www.nidm.gov.in

एनआईडीएम का वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15

© एनआईडीएम, नई दिल्ली

संस्करण : तृतीय, 2015

प्रकाशन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली— 110 002

दस्तावेज <http://www.nidm.gov.in/books> से डाउनलोड किया जा सकता है।

लक्ष्य

एनआईडीएम का लक्ष्य भारत में आपदा के जोखिम को कम करना और उसके प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए प्रमुख एवं उत्कृष्ट संस्थान बनाना है और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाना है। सभी स्तरों पर रोकथाम और तत्परता जैसी संस्कृति का विकास कर तथा इसे बढ़ावा देकर आपदा रहित भारत का सृजन करना है।

निदेशक की कलम से

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली की वर्ष 2014-15 की वार्षिक प्रतिवेदन मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) का गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा इस क्षेत्र में सामर्थ्य विकास के लिए एक मुख्य संस्था की भूमिका निभाने के लिए की गई थी। आपदा प्रबंधन का प्रतिमान 'प्रतिक्रिया और राहत' से परिवर्तित होकर रोकथाम, बचाव और तैयारी तक केन्द्रित हो गया है और आगे का जारी दूसरा प्रतिमान 'जोखिम-सुभेद्यता और पर्यावरण' केन्द्रित पहुँच की ओर है, जिसे विकास और धारणीयता के विविध क्षेत्रों में आपदा जोखिम लघुकरण (डीआरआर) को मुख्य धारा में लाने का गंभीर प्रयास माना जाता है। जोखिम लघुकरण पर बढ़ता हुआ जागरूकता जिसने 2004 का भारतीय समुद्री सुनामी तथा एक साल बाद ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्सन (एह एफ ए) को स्वीकार किया है, ने कई एशियाई देशों में डी आर आर के लिए विचारणीय प्रेरणा उपलब्ध कराया है और कार्यान्वयन के लिए सांस्थानिक संरचना को मजबूती प्रदान किया है।

एनआईडीएम ने आपदा जोखिम प्रबंधन के विषय में जानकारी फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। सामर्थ्य निर्माण और मानव संसाधन विकास के केन्द्रीय संस्थान के रूप में, एनआईडीएम राज्य सरकारों और उनसे संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं, अन्य अकादमिक और व्यवसायी इकाइयों के सहयोग से कार्य कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि अधिनियम द्वारा आदेश दिया गया है, प्रशिक्षण प्रोग्राम, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और अन्य आउटरिच क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी का विकास कर रहा है।

हमारा लक्ष्य आपदा निवारण और तत्परता के सभी स्तरों पर सामर्थ्य निर्माण द्वारा आपदा मुक्त भारत का सृजन करना है। राष्ट्रीय केन्द्र और राष्ट्रीय संस्थान, दोनों रूपों में, एनआईडीएम आपदा जोखिम लघुकरण को राष्ट्रीय एजेंडा में सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वस्तुतः, इन सब उपलब्धियों के साथ-साथ, दायित्वों को प्राप्त करने की बड़ी चुनौती और एनआईडीएम ने इस देश के नागरिकों को बेहतर डी आर आर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए नई विस्तार और सपना दिखाया है। एनआईडीएम जोखिम लघुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का दायित्व नये तरीके से लेने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर सभी पाठकों को सुखी और उन्नत नव वर्ष 2016 की शुभकामनाएँ देता हूँ।

(कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम)

विषय सूची

1. परिचय	1-4
1.1. संस्थान के बारे में	2
1.1.1. मिशन और उद्देश्य	2
1.1.2. आदेश	2
1.1.3. कार्य	3
2. प्रशिक्षण	5-13
2.1. उद्देश्य	6
2.2. प्रतिभागियों की प्रोफाइल	6
2.3. प्रशिक्षण की विधियाँ	6
2.4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार	6
2.5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण	9
2.6. प्रशिक्षुता	13
3. परियोजनाएँ	14-29
3.1. परियोजनाओं के प्रकार	15
3.2. उपकरण और तकनीकें	15
3.3. जारी/समाप्त परियोजनाएँ	15
4. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	30-35
4.1. भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	31
4.2. भारत आपदा जानकारी नेटवर्क (आईडीकेएन)	33
4.3. एनआईडीएम वेबसाइट का नया रूप	34
4.4. एनआईडीएम ऑन-लाइन पाठ्यक्रम	34
4.5. एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस	35

- 4.6. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के आपदा प्रबंधन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत काल्पनिक गैर सरकारी नेटवर्किंग 35

5. प्रलेखन और प्रकाशन 36-54

- 5.1. उपलब्ध सूचना स्रोत 37
- 5.2. सूचना प्रसारण 37
- 5.3. सूचना शिक्षा और संचार (आईइसी) सामग्रियाँ 43
- 5.4. योजनाओं हेतु निवेश 47
- 5.5. क्षेत्र दौरे और प्रलेखन 48

6. मुख्य घटनाएँ /कार्यशालाएँ/ सम्मेलन/ सेमिनार और अन्य आउटरिच क्रियाकलाप 55-95

- 6.1. आउटरिच क्रियाकलाप 56
- 6.2. सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएँ 58
- 6.3. अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एनआईडीएम 74
- 6.4. सम्मेलन/प्रतिनिधिमंडल 78
- 6.5. क्षेत्रीय सहयोग 85
- 6.6. अन्य क्रियाकलाप 85

7. प्रशासन 96-100

- 7.1. सामान्य निकाय और संचालित निकाय की बैठक 98
- 7.2. सांस्थानिक संरचना 98
- 7.3. एनआईडीएम संकाय 99
- 7.4. सामान्य प्रशासन 100
- 7.5. हिंदी का प्रगामी प्रयोग 100

8. वित्त और लेखा 101-102

अनुलग्नक

- अनुलग्नक 1. एनआईडीएम द्वारा संपन्न कराये गये फेस-टु-फेस (प्रत्यक्ष) ट्रेनिंग की सूची 2014-15 104
- अनुलग्नक 2. राज्य प्रशासनिक इकाइयों की सूची 109
- अनुलग्नक 3. संस्थान के सामान्य निकाय बैठक के सदस्यों की सूची 113
- अनुलग्नक 4. वित्त और लेखा 115

शब्द संक्षेप

एडीआरसी	:	एशियन आपदा रिडक्सन केन्द्र
एडीपीसी	:	एशियन आपदा तैयारी केन्द्र
एटीची	:	वार्षिक ट्रेनिंग सम्मेलन
एटीआई	:	प्रशासनिक ट्रेनिंग संस्था
बीएमपीटीसी	:	बिल्डिंग सामग्री तथा प्रमोसन काउंसिल
सीसीए	:	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
सीडीएसी	:	अग्रिम कंप्यूटिंग विकास केन्द्र
सीडब्ल्यूसी	:	केन्द्रीय जल आयोग
डीएसटी	:	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
डीएमसी	:	आपदा प्रबंधन केन्द्र
डीआरआर	:	आपदा जोखिम रिडक्सन
इकेडीआरएम	:	आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु पर्यावरणीय जानकारी
जीएफडीआरआर	:	आपदा रिडक्सन तथा रिकवरी के लिए वैश्विक सुविधा
जीआईजेड	:	डच जेसेलशापट फोर इंटेनेशनल जुसामेनारबेट
जीएसआई	:	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे
आईसीआईएमओडी	:	समेकित पर्वत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र
आईसीएसएसआर	:	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए भारतीय काउंसिल
आईआईपीए	:	भारतीय लोक प्रशासन संस्था
आईआईएसआर	:	भारतीय रिमोट सेन्सिंग संस्था
आईएमडी	:	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग
आईजीइपी	:	भारत-जर्मन पर्यावरण प्रोग्राम
जेआईचीए	:	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी
एमओइएफ	:	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एनडीएमए	:	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

एनइसी	:	भारतीय कार्यकारी समिति
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
एनआईआरडी	:	राष्ट्रीय ग्राम्य विकास संस्था
पीडीएनए	:	आपदा पश्च अपरिहार्य मूल्यांकन
पीएसयू	:	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एसडीएमसी	:	एसएएआरसी आपदा प्रबंधन केन्द्र
टीओटी	:	प्रशिक्षकों का ट्रेनिंग
टीओएस	:	हितधारकों का ट्रेनिंग
यूएनडिपी	:	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनइपी	:	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएन एसपीआईडीइआर	:	आपदा प्रबंधन और अपातकाल प्रतिक्रिया हेतु स्पेस आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र प्लेटफार्म
यूएसएआईडी	:	अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी
डब्ल्यू बी	:	विश्व बैंक

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1. संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति नियोजन सहित मानव संसाधन विकास तथा सामर्थ्य निर्माण का केन्द्रीय दायित्व सौंपा गया है। दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के नेशनल आपदा प्रबंधन केन्द्र से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में समुन्नत एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदाओं की रोकथाम और पूर्व-तैयारी की संस्कृति के विकास और प्रोत्साहन के माध्यम से आपदा रहित भारत बनाने के लिए स्थायी रूप से अपने मिशन को पुरा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है और उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में सामने आया है। केन्द्रीय गृहमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं, और इसके अधिशासित निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

1.1.1. मिशन और उद्देश्य

एनआईडीएम का मिशन सभी स्तरों पर आपदा रोकथाम और तैयारी की संस्कृति का विकास एवं प्रोत्साहन के माध्यम से आपदा रहित भारत बनाने, नीति-निर्माण में सहायता करने तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम से आपदा के प्रभाव में कमी लाने की दिशा में सतत् प्रयास करते रहना है:

- प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण सेवाओं के साथ-साथ रणनीति की जानकारी की योजना बनाना और उसे प्रोत्साहन देना।
- राष्ट्रीय स्तर के सूचना आधार का अनुसंधान, प्रलेखन और विकास
- प्रभावी आपदा पूर्व तैयारी और न्यूनीकरण के लिए पद्धति विकास तथा विशेषज्ञता प्रोन्नयन।
- सभी हितधारकों में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उनकी जानकारी और कौशलों को बढ़ाना।

- सभी हितधारकों के प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण के लिए संस्थागत रचना-तंत्र को सुदृढ़ करना।
- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य प्रमुख संस्थानों से सहयोग स्थापित कर केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र बनाना।

1.1.2. आदेश

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, अनुसंधान और प्रलेखन की व्यवस्था करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक मानव संसाधन विकास योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन करना।
- राष्ट्रीय स्तर के नीति-निर्माण में सहायता उपलब्ध कराना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करना
- राज्य सरकारों और राज्यों की प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य स्तर पर नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढाँचा और सामर्थ्य निर्माण में सहायता प्रदान करना
- आपदा प्रबंधन के लिए अकादमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना।
- कॉलेज/स्कूल के अध्यापकों और छात्रों, तकनीकी कार्मिकों तथा बहु-जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी और अनुक्रिया उपायों से जुड़े अन्य व्यक्तियों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना।
- आपदा प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में तथा देश के बाहर अध्ययन पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यायनों, सेमिनारों का दायित्व

लेना, आयोजित करना तथा आयोजन में सहायता प्रदान करना।

- पत्रिकाओं, अनुसंधान लेखों और पुस्तकों के प्रकाशन की जिम्मेदारी लेना और इस कार्य में सहयोग प्रदान करना। पुस्तकालयों इत्यादि की स्थापना करना और उसका अनुरक्षण करना।
- उन सभी वैध कार्यों को करें जो उपर्युक्त चीजों के लिए व्यवहारिक या प्रासंगिक हो।
- किसी अन्य कार्यों की भी जिम्मेदारी लें जो कि इसे केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है।

1.1.3. कार्य

संस्थान में सुयोग्य विशेषज्ञों सहित चार अकादमिक विभाग हैं जिसमें नीति नियोजन, पूर्व-तैयारी एवं न्यूनीकरण, अनुक्रिया एवं पुनर्वास जैसे आपदा प्रबंधन संबंधी पहलुओं पर निम्नलिखित कार्य किया जाता है:

- ◆ **ट्रेनिंग** : एनआईडीएम निम्नलिखित प्रकार के कोर्स को डिजाइन करने और उसका कार्यान्वयन करने में संलग्न है:

(क) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संचालित)

(i) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)

(ii) हितधारकों का प्रशिक्षण (टीओएस)

(ख) वेब आधारित/ऑनलाइन प्रशिक्षण

(ग) सम्मिश्रित अधिगम

(घ) सेटलाइट (एडुसेट) आधारित प्रशिक्षण

(ड) स्वतः अध्ययन पाठ्यक्रम

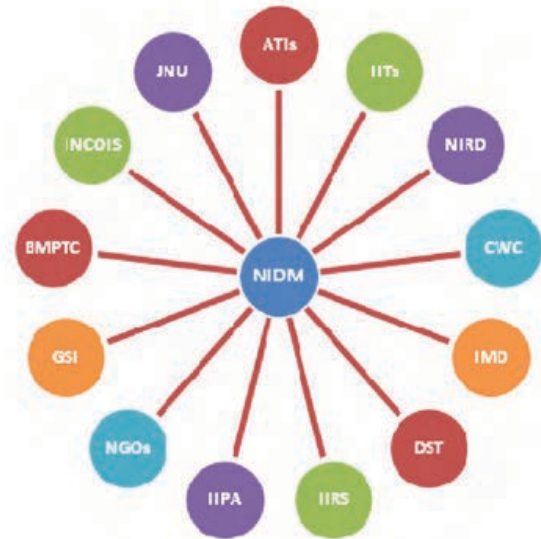
- ◆ **नीति अध्ययन** : संस्थान ने आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय अधिनियम, 2005 के अनुसार) हेतु

राष्ट्रीय पॉलिसी प्रतिपादन के लिए, दसवीं तथा ग्यारहवीं योजनाओं के प्रलेखों में आपदा प्रबंधन पर अध्याय, आपदा प्रबंधन तथा इसके अनुमोदनों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट और तेरहवीं वित्त आयोग में आपदा प्रबंधन को वित्त प्रदान करने के लिए एक अध्ययन में सारगर्भित इनपुट उपलब्ध कराया है। संस्था आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना और राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास और सामर्थ्य निर्माण योजना का विकास कर रही है और इस प्रकार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति(एनइसी)को आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय योजना के विकास में सहायता कर रही है। अशक्तता पर विशिष्ट दिशा-निर्देश एन डी एम ए के साथ संपर्क स्थापित कर निर्मित किया गया था। राज्य सरकारों को उनके डी आर आर के सूत्रपातों में भी मदद करती है।

- ◆ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : एनआईडीएम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी), आपदा प्रबंधन और अपातकाल प्रतिक्रिया हेतु अंतरिक्ष आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच (यूएन- स्पाइडर), समेकित पर्वत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र(आई सी आई एम ओ डी), डच जेसेलशाफ्ट फोर इंटेनेशनल जुसामेनारबेट(जीआईजी), अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (यू एस ए आई डी), विश्व बैंक(डब्ल्यू बी) और कई अन्य एजेंसी के नजदीकी सहयोग से कार्यान्वयन करने, प्रशिक्षण देने, अनुसांधान और नीति की योजना से संबंधित टास्क के लिए कार्य कर रही है (चित्र 1.1)



अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग



राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

चित्र 1.1: एनआईडीएम का अलग-अलग हितधारकों से सहयोग को दिखाते हुए चित्र

❖ **शिक्षा और अनुसंधान:** एनआईडीएम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ कॉलेज/युनिवर्सिटी शिक्षा में आपदा प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए यू जी स्तर पर वैकल्पिक कोर्स के रूप में लाने और उच्चतर शिक्षा के सभी मुख्य धारा में डी आर आर को मुख्य धारा में लाने के लिए एक योजना बना रही है(चित्र 1.1)। एनआईडीएम ने आई सी एस एस आर, आई एस इ टी, यू एन डी पी, एम ओ इ एफ, आई सि आई एम ओ डी, जी आई जेड-आई जी इ पी, इत्यादि के सहायता तथा सहयोग से शहरी खाद्य अध्ययनों, बुंदेलखंड अकाल असुरक्षा, जलवायु प्रतिस्पर्धी विकास तथा अनुकूलन, गोरखपुर बाढ़, पर्वतों में जल जोखिम सुधार के लिए स्थानीय नीति इत्यादि के अनुसंधान तथा घटना अध्ययन का दायित्व लिया है।

❖ **प्रलेखन और प्रकाशन:** एनआईडीएम ने कमियों,

उत्तम प्रयासों तथा भविष्य के लिए सीखे गये पाठों को पहचानने के लिए भारत के सभी मुख्य आपदाओं का प्रलेखन प्रारंभ कर दिया है। एनआईडीएम द्वारा प्रथम “भारत आपदा रिपोर्ट” 2012 में प्रकाशित की गई थी। एनआईडीएम अर्ध-वार्षिक पत्रिका “डिजेस्टर एण्ड डेवलपमेंट”, त्रैमासिक समाचारपत्र “टाइडिंग्स” और “मासिक अपडेट्स” भी प्रकाशित करता है। एनआईडीएम के द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों/पत्रिकाओं/दस्तावेजों को उसकी वेबसाइट (www.nidm.gov.in) के ड्रॉप डाउन मेनु, जिसे पब्लिकेशन का नाम दिया गया है, के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है।

एनआईडीएम राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन केन्द्र (डी एमसी) जो अधिकांशतः राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक ट्रेनिंग संस्था(एटीआई) में उपलब्ध होते हैं, के माध्यम से तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है। वर्तमान में एनआईडीएम ऐसे तीस केन्द्रों को सहायता कर रहा है।

अध्याय



प्रशिक्षण

आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य निर्माण पर बल देना संस्था के मुख्य प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के भाग के रूप में, प्रमुखतः आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में विभिन्न सामर्थ्य निर्माण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

वित्त वर्ष 2014-15, के दौरान कुल 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे, इनमें से 77 प्रत्यक्ष (आमने-सामने) और 18 ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कुल 2909 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया था। यह वर्ष ऑनलाइन प्रोग्राम(18) की संख्या में तथा पहले वित्त वर्ष की तुलना में प्रशिक्षण में भागीदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी का गवाह है।

2.1. उद्देश्य

आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों, जो आपदा और विकास गतिविधियों के क्षेत्र में लगे हुए हैं, को प्रदान किये जा रहे उपयुक्त प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ डिजाइन किया गया है:

- प्रभावी प्रोग्राम की योजना बनाने तथा उसका कार्यान्वयन करने के लिए विकास कार्यकर्ताओं में जागरूकता पैदा करना, उनके कौशल में सुधार लाना और उनके ज्ञान को बढ़ाना;
- केन्द्र तथा राज्यों के विकास विभाग के वरिष्ठ कार्यपालकों को सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर आपदा प्रबंधन की उभरती जरूरतों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा परामर्शों के माध्यम से सुग्राही बनाना;
- प्रभावित क्षेत्र के दौरों, सफल घटनाओं तथा विकासात्मक हस्तक्षेपों के प्रलेखन के माध्यम से विकास कार्मिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।

2.2. प्रतिभागियों की प्रोफाइल

चूंकि एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा प्रबंधन में संलग्न विभिन्न उपभोक्ता समूहों के मध्य प्रचार करते हैं, अतः प्रशिक्षुओं के प्रोफाइल निम्नलिखित श्रेणियों के भागीदारों तक विस्तृत है:

- सरकारी अधिकारियों (केन्द्र, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों);
- नागरिक सामाजिक के संगठनों (आपदा प्रबंधन पेशेवरों);
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू);
- अकादमिक के शिक्षाविदों (अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, स्कूल के शिक्षकों और युनिवर्सिटी के प्रोफेसरों);
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों।

2.3. प्रशिक्षण की विधियाँ

प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की विभिन्न प्रकृति और प्रोग्राम में भाग लेने वाले भागीदारों के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण की कई विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। ट्रेनिंग के विधियों में शामिल है:

- व्याख्यान-सह-विवेचन
- घटना-अध्ययन प्रस्तुतीकरण
- प्रतिभागिता विधियाँ
- सामुहिक चर्चा
- अभ्यास/हैण्ड-ऑन(परख) सत्र
- क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययन दौरा
- पैनल चर्चा
- अनुकरण क्रीड़ा
- प्रशिक्षण परख
- टेबल टॉप अभ्यास

2.4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार

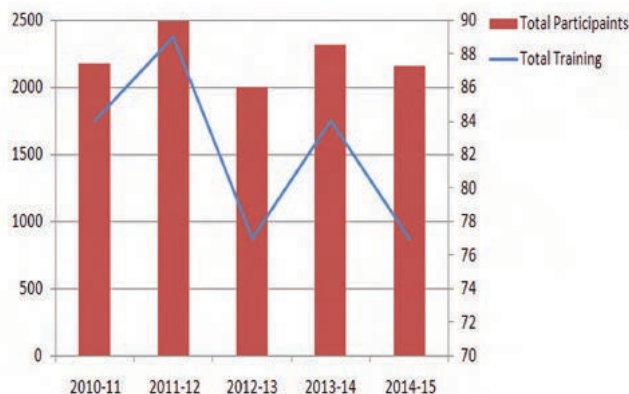
एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदायगी के माध्यमों, लक्ष्य समूह तथा विषय-वस्तु के आधार पर किया

जाता है। प्रदायगी के माध्यम पर आधारित कार्यक्रमों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है:

- 1) प्रत्यक्ष (आमने-सामने) प्रशिक्षण
- 2) सम्मिश्रित अधिगम
- 3) ऑन-लाइन प्रशिक्षण
- 4) स्व- अधिगम
- 5) सेटेलाइट आधारित अधिगम

2.4.1. प्रत्यक्ष (आमने-सामने) प्रशिक्षण कार्यक्रम

आमने-सामने प्रशिक्षण एनआईडीएम का प्रमुख(प्लैगशिप) कार्यक्रम है। संस्थान आमने-सामने या प्रत्यक्ष प्रशिक्षण विधि द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से एनआईडीएम पर या राज्य ए टी आई के आपदा प्रबंधन केन्द्रों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आंकड़े का पिछले पाँच वर्षों का तुलनात्मक विश्लेषण चित्र 2.1 में दिखाया गया है।

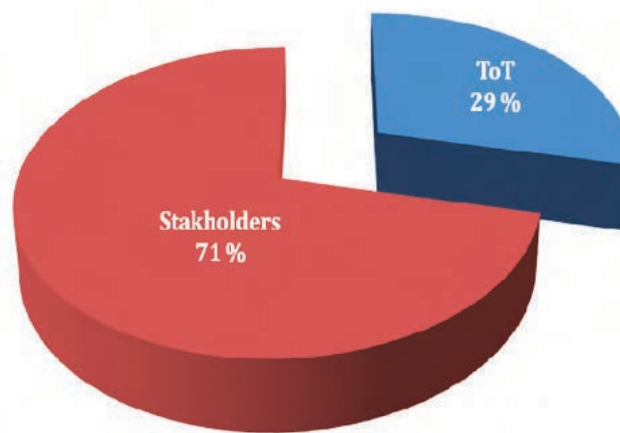


चित्र 2.1: पिछले पाँच वर्षों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षकों की संख्या की तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हुए दण्ड आरेख

लक्ष्य समूह के आधार पर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो भेद हैं: हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए एनआईडीएम 2011 से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दे रही है।

एनआईडीएम द्वारा वर्ष 2014-15 में भारत के विभिन्न स्थानों पर कुल 77 प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षित किये गये 2160 प्रशिक्षकों में, 618 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण(टी ओ टी) के अंतर्गत और 1542 विभिन्न क्षेत्रों तथा विभागों के आपदा प्रबंधन से जुड़े हितधारकों को प्रशिक्षण दिया गया (सारणी 2.1)। इस प्रकार कुल प्रत्यक्ष प्रशिक्षणों का 29 प्रतिशत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) था और 71 प्रतिशत प्रशिक्षण अन्य हितधारकों को दिया गया (चित्र 2.2)।



चित्र 2.2: वर्ष 2014-15 में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण व्योरा		प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी)		अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण	
कुल प्रशिक्षणों की संख्या	कुल भागीदारों की संख्या	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल भागीदारों की संख्या	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल भागीदारों की संख्या
77	2160	31	618	46	1542

2.4.2. ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा विश्व बैंक (जी एफ डी आर आर) वार्शिंगटन की साझेदारी से आपदा जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग कार्यक्रम की एक शृंखला प्रस्तुत की गई है (चित्र 2.3)। ये पाठ्यक्रम सुदूरवर्ती प्रतिभागियों को पेशेवर मार्गदर्शन के अंतर्गत आपदा जोखिमों के प्रबंधन तथा इसके न्यूनीकरण के बारे में सीखने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। सी डी के रूप में प्रशिक्षण सामग्रियाँ डाक द्वारा भेजी जाती हैं तथा कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद किसी भी समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। पंजीकृत भागीदारों द्वारा सभी मापदंडों तक ऑन-लाइन पाठ्यक्रम मंच के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण और श्रव्य, विचार-विमर्श मंच, प्रश्न, स्पष्टीकरण, गृह-कार्य और पाठ्यक्रम समाप्ति परियोजना शामिल होते हैं जिसका मूल्यांकन अनुभवी पाठ्यक्रम संचालकों द्वारा किया जाता है। सफल उम्मीदवारों को



चित्र 2.3: आपदा जोखिम प्रबंधन पर एनआईडीएम अधिगम कार्यक्रमों का होम पेज

एनआईडीएम तथा विश्व बैंक (जी एफ डी आर आर) द्वारा संयुक्त रूप से जारी प्रमाण-पत्र दिया जाता है। वर्ष 2014-15 की अवधि में कुल 18 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 749 भागीदारों को ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया (सारणी 2.2)।

सारणी 2.2: वर्ष 2014-15 के लिए ऑन-लाइन पाठ्यक्रमों की स्थिति

क्रम सं	पाठ्यक्रम का नाम और बैच	तिथि	टास्क प्रबंधक	भागीदारों की संख्या
विस्तृत आपदा जोखिम प्रबंधन (सीडीआरएमएफ)				
1	बैच-1	1 अप्रैल से 10 मई 2014	डॉ. सूर्य प्रकाश	63
2	बैच -2	2 जून 11 जुलाई 2014	डॉ. रितु राज शर्मा	45
3	बैच -3	1 अगस्त से 9 सितंबर 2014	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	46
4	बैच -4	1 अक्टूबर से 9 नवंबर 2014	सुश्री श्रीजा नायर	35
5	बैच -5	1 दिसंबर 2014 से 9 जनवरी 2015	श्री शेखर चतुर्वेदी	31
6	बैच -6	2 फरवरी से 13 मार्च 2015	डॉ. सूर्य प्रकाश	34
7	बैच -7	16 फरवरी 26 मार्च 2015	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	37
समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (सीबीडीआरएम)				
8	बैच -1	15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2014	सुश्री चंद्राणी बी नियोगी	54
9	बैच -2	15 जनवरी 2015 से 9 फरवरी 2015	डॉ. सुषमा गुलेरिया	35
भूकंप जोखिम न्यूनीकरण (इ आर पी)				
10	बैच -1	14 अगस्त से 8 सितंबर 2014	डॉ. रितु राज शर्मा	38
11	बैच -2	14 नवंबर से 9 दिसंबर 2014	डॉ. सूर्य प्रकाश	27
क्षति और पुनर्निर्माण आवश्यक मूल्यांकन				
12	बैच -1	15 जुलाई से 9 अगस्त 2014	डॉ. सूर्य प्रकाश	38
जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना				
13	बैच -1	16 जून जव 11 जुलाई 2014	प्रो. चंदन घोश	32
सुरक्षित नगर				
14	बैच -1	15 अक्टूबर से 9 नवंबर 2014	सुश्री चंद्राणी बी नियोगी	40

जलवायु परिवर्तन तथा आपदा जोखिम				
15	बैच -1	15 दिसंबर 2014 से 9 जनवरी 2015	प्रो. एन. विनोद चंद्र मेनन	61
जोखिम के आर्थिक प्रभाव के लिए वित्तीय रणनीतियाँ (एफएस)				
16	बैच -1	16 फरवरी 2015 से 26 मार्च 2015	कर्नल पी. के. पाठक	50
सुदूर वापसी तथा पुनर्निर्माण के लिंग पहलू (जीएडीआरआर)				
17	बैच -1	20 फरवरी से 17 मार्च 2015	सुश्री चंद्राणी बी नियोगी	40
जोखिम पहचान, मूल्यांकन विश्लेषण				
18	बैच -1	15 मई से 9 जून 2014	श्री अशोक कुमार शर्मा	43

2.4.3. स्व-अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम सामान्य जनता के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों जिनकी भूमिका और दायित्व आपदाओं के प्रबंधन में है, को स्व अध्ययन पाठ्यक्रम प्रदान करती है (चित्र 2.4)। कार्यक्रम के अंतर्गत के पाठ्यक्रमों को किसी भी व्यक्ति द्वारा देश के किसी भी भाग से अपनी सुविधा के अनुसार मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य आपदा प्रबंधन में रुचि लाना तथा जानकारी, कौशल तथा जागरुकता के स्तर को बढ़ाना है।

URL: <http://www.nidmssp.in>



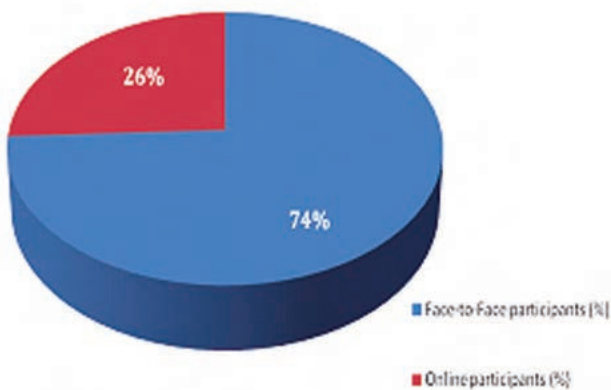
चित्र 2.4: एनआईडीएम स्व अध्ययन पाठ्यक्रम का होम पेज

2.5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण

2014-15 के दौरान एनआईडीएम ने कुल 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिसमें 77 प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम (31 टी ओ टी और 46 टी ओ एस) भी शामिल है। प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के अलावा 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑन-लाइन माध्यम से प्रदान किये गये थे। विभिन्न पेशों से जुड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त एनआईडीएम का स्व-अध्ययन कार्यक्रम छात्रों तथा आम जनता के लिए भी उपलब्ध है।

2.5.1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार

एनआईडीएम तीन सामान्य संवर्गों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करती है: 1) प्रत्यक्ष, 2) ऑन-लाइन और 3) उपग्रह आधारित प्रशिक्षण। इस वर्ष एनआईडीएम द्वारा कोई उपग्रह आधारित पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। लगभग 74 प्रतिशत प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और 26 प्रतिशत प्रतिभागियों को विभिन्न ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया (चित्र 2.5)। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण नीचे सारणी 2.3 में दिया गया है।



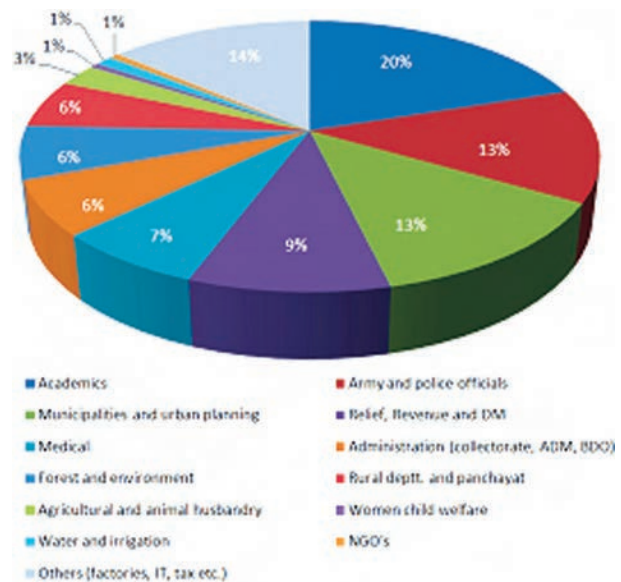
चित्र 2.5: 2014-15 में प्रत्यक्ष तथा ऑन-लाइन प्रशिक्षित प्रतिभागियों के प्रतिशत को दर्शाता वृत्त-चार्ट

सारणी 2.3: 2014-15 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार

क्रम सं.	कार्यक्रमों के प्रकार	प्रशिक्षणों की कुल संख्या	कुल प्रतिभागी
1	प्रत्यक्ष प्रशिक्षण	77	2160
2	ऑन-लाइन प्रशिक्षण	18	749
	कुल	95	2909

2.5.2. प्रतिभागियों के प्रोफाइल

एनआईडीएम द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की ओर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागी आकर्षित हुए थे। इनमें अधिकांश प्रतिभागी केन्द्र और राज्य सरकारों के थे। अधिकतम प्रतिभागियों में अकादमिक क्षेत्र से (20 प्रतिशत), इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ आर्मी और पुलिस के कर्मचारी (13 प्रतिशत), विभिन्न नगरपालिकाओं तथा शहरी योजना के कर्मचारी (13 प्रतिशत), बचाव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी (9 प्रतिशत), चिकित्सा क्षेत्र के कार्मिक (7 प्रतिशत) शामिल थे। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किये गये प्रतिभागियों का प्रोफाइल चित्र 2.6 में दिया गया है।



चित्र 2.6: 2014-15 के दौरान प्रशिक्षित किये गये प्रतिभागियों का प्रोफाइल

2.5.3. क्षेत्र के अनुसार प्रतिभागी

अधिकांश प्रतिभागी उत्तरी भारत (जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड), इसके बाद पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा), उत्तर-पूर्व भारत (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा), दक्षिण भारत (तमिलनाडु, केरल, आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी), पश्चिमी भारत (गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोआ, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली), मध्य भारत (मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़) और भारत के दो छोटे द्वीप-समूहों (लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार) से थे। सारणी 2.4 और चित्र 2.7 देश के विभिन्न भागों के प्रतिभागियों की संख्या को उपलब्ध कराता है।

सारणी 2.4: भारत के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों की संख्या

क्र सं.	राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	प्रशिक्ष
1.	अंडमान निकोबार द्वीप-समूह	161
2.	आंध्र प्रदेश	52
3.	अरुणाचल प्रदेश	20
4.	असम	16
5.	बिहार	80
6.	चंडीगढ़	2
7.	छत्तीसगढ़	15

8.	दादरा और नगर हवेली	2
9.	दिल्ली	310
10.	गोआ	9
11.	गुजरात	11
12.	हरियाणा	32
13.	हिमांचल प्रदेश	62
14.	जम्मू और काश्मीर	39
15.	झारखंड	77
16.	कर्नाटक	50
17.	केरल	59
18.	लक्षद्वीप	22
19.	मध्य प्रदेश	23
20.	महाराष्ट्र	196
21.	मणिपुर	1
22.	मेघालय	32
23.	मिजोरम	21
24.	नागालैण्ड	49
25.	उड़ीसा	123
26.	अन्य	1
27.	पुडुचेरी	6
28.	पंजाब	118
29.	राजस्थान	91
30.	सिक्किम	11
31.	तमिलनाडु	69
32.	तेलांगना	3
33.	त्रिपुरा	22
34.	उत्तर प्रदेश	172
35.	उत्तराखंड	108
36.	पश्चिम बंगाल	95

2.5.4. 2014-15 के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत क्षेत्र

एनआईडीएम आरंभ काल से ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करता रहा है। 2014-15 के दौरान एनआईडीएम द्वारा निष्पादित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मोटे तौर पर पांच शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) बुनियादी आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम (ii) जोखिम विशिष्ट पाठ्यक्रम (iii) परस्पर संबद्ध मुद्दे (iv) अपातकालीन

प्रतिक्रिया (v) तकनीकी (इंजिनियरिंग, चिकित्सा और भू-सूचना विज्ञान)।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

1) बुनियादी आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम

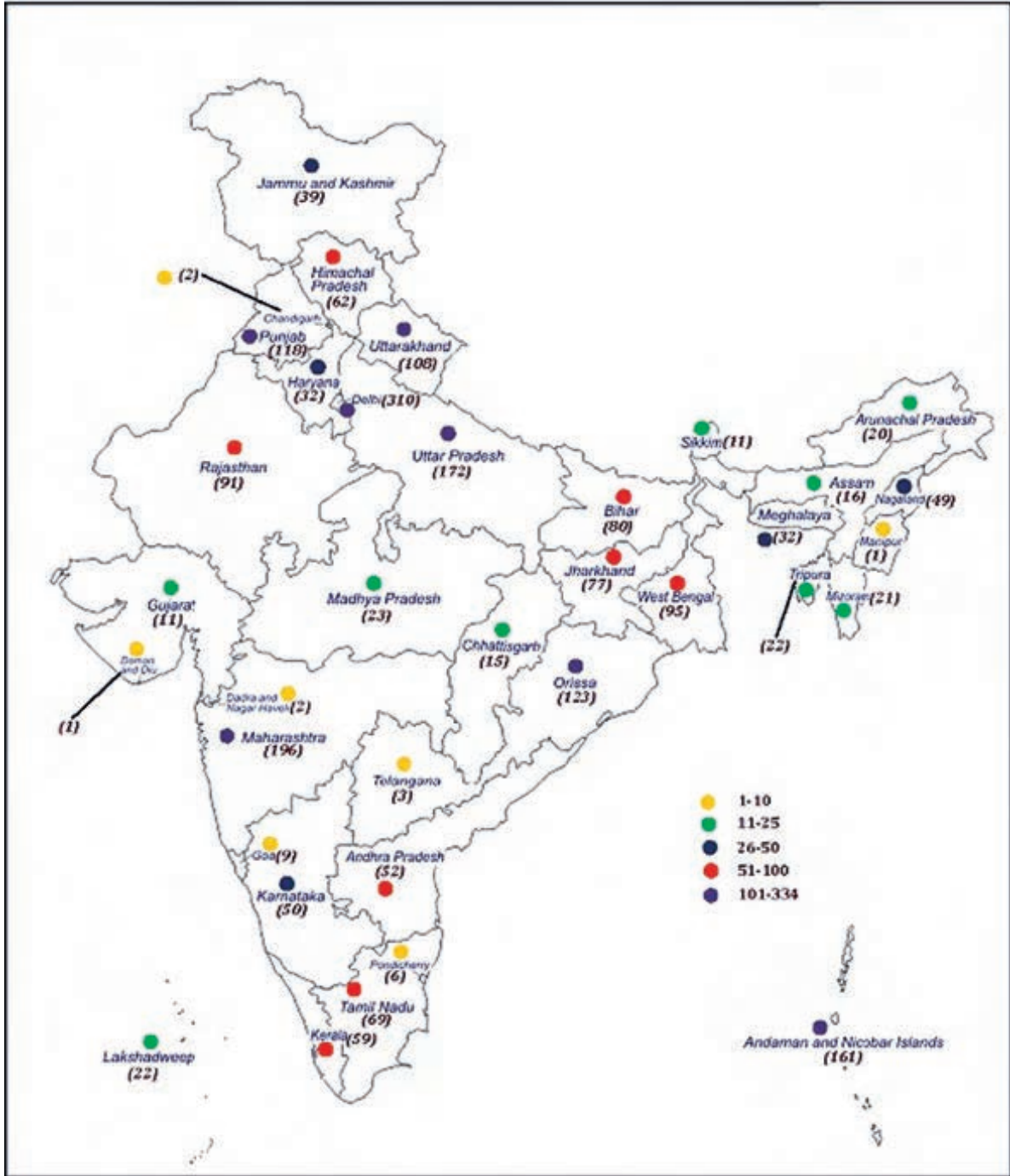
- विभिन्न लक्ष्य समूहों (सिविल रक्षा, एन डी आर एफ, अध्यापक आदि) के लिए बुनियादी आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम

2) जोखिम विशिष्ट पाठ्यक्रम

- रसायन (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन
- चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण
- सूखा न्यूनीकरण तथा प्रबंधन
- भूकंप जोखिम प्रबंधन
- बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन
- दावानल प्रबंधन
- भू-स्खलन जोखिम संकट प्रबंधन
- लू तथा शीत लहर प्रबंधन
- सड़क दुर्घटना प्रबंधन

3) परस्पर संबद्ध मुद्दे

- जलवायु प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन का अनुकूलन
- समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
- अशक्तता और आपदा प्रबंधन
- आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन
- आपदा सुरक्षित पर्वतीय क्षेत्र विकास
- आपदा जोखिम अवमंदन हेतु परिणाली दृष्टिकोण
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का विकास
- लिंग और आपदा प्रबंधन
- आपदा प्रबंधन हेतु विधिक संरचना
- स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम
- आपदा में बच्चों की जरूरतें।
- आपदा के बाद क्षति और आवश्यकता का आकलन



चित्र 2.7: 2014-15 के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता मानचित्र

- आपदा प्रबंधन में पुनर् उत्पादकीय स्वास्थ्य, लिंग और मनो सामाजिक सहायता
 - आपदा प्रबंधन में वानिकी क्षेत्र की भूमिका
 - आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका
 - आपदा प्रतिक्रियावादियों के तनाव प्रबंधन
 - शहरी जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन
- 4) अपातकालीन प्रतिक्रिया**
- अपातकालीन प्रचालन केन्द्रों पर प्रशिक्षण
 - घटना प्रतिक्रिया प्रणाली तथा एकीकृत योजना पर पाठ्यक्रम

- रासायनिक आपदा स्थितियों के लिए ऑन-साइट तथा ऑफ-साइट आपदा तैयारी

5) तकनीकी (इंजिनियरिंग, मेडिकल तथा भू-सूचना विज्ञान)

- आपदा सुरक्षित निर्माण पर्यावरण के लिए भवन संहिता और डिजाइन
- आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा
- भू-सूचना विज्ञान का आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोग
- भूकम्प सूक्ष्म जोनकरण और जोखिम मानचित्रण
- द्रुत दृश्य जाँच द्वारा भवनों की भूकम्प-सुरक्षा आकलन
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

2.5.5. फिडबैक

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, प्रशिक्षण का डिजाइन, प्रशिक्षण विधियाँ, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ता की प्रभावोत्पादकता, आवास एवं भोजन की सुविधा, पुस्तकालय सुविधा इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के डिजाइन, विषय-वस्तु तथा प्रभावोत्पादकता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

2.6. प्रशिक्षुता

प्रत्येक वर्ष एन आई डी एम, शैक्षिक/ अनुसंधान/ प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों/अनुसंधानकर्ताओं से ग्रीष्म ऋतु के दौरान विशेषतः प्रशिक्षुता के लिए अनुरोध मिलते रहे हैं। ऐसे अनुरोध पर वैयक्तिक आधार पर विचार किया जाता है। प्रशिक्षुता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- इच्छुक तथा पात्र अव स्नातक तथा स्नातक से संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर कर रहे छात्रों को समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली तथा इसके विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना।
- आपदा प्रबंधन प्रक्रिया, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में प्रथम दृष्टया अनुभव प्राप्त करने में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को मदद करना।
- छात्रों को उनके कौशल परीक्षण में नवीनता लाने और नये विचार तथा तकनीकों को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यावसायिक संस्थानों को औपचारिक साधनों के साथ-साथ अनौपचारिक साधनों द्वारा एनआईडीएम तथा इन संस्थानों की गतिविधियों के बारे में समुचित सूचना उपलब्ध कराना।

इस वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षुता के लिए 20 छात्रों के नाम दर्ज किये गये। इन छात्रों का चयन उनकी योग्यता और प्रस्तावों पर आधारित था जिसका विकास उन्होंने प्रशिक्षुता के लिए किया था।

अध्याय



परियोजनाएँ

एनआईडीएम द्वारा दूसरे मंत्रालयों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलकर आपदा और विकास के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान, परामर्श और सहयोग परियोजनाओं का निष्पादन किया गया। इन परियोजनाओं का परिणाम जोखिम परिस्थितियों को समझने के लिए, योजनाओं और नीति दस्तावेजों के विकास और क्षेत्र से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित मुख्य इनपुट के लिए भी किया जाता है। एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा घटना अध्ययन मॉड्यूलों के विकास में अनुसंधान के इन परिणामों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है।

3.1 परियोजनाओं के प्रकार

आयोजित परियोजनाओं को निम्नलिखित प्रकार से किये गये:

- सामर्थ्य निर्माण परियोजनाएँ इसमें प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विश्लेषण, प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास, क्षेत्र अनुभवों पर आधारित प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का विकास एवं कार्यान्वयन इत्यादि शामिल है (जैसे— विश्व बैंक, चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना, भारत—जर्मन सहयोग, इको डी आर एस आर, आर वी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम, ललिता पार्क भवन विखंडन का न्यायिक अन्वेषण इत्यादि)। घटना अध्ययन पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल इको डी आर एम परियोजना के अंतर्गत तैयार किये गये हैं।
- आपदा पश्चात जाँच तथा प्रलेखन परियोजनाएँ (उदाहरणार्थ ललिता पार्क भवन विखंडन का न्यायिक अन्वेषण)।
- जोखिम मापचित्रण, अतिसंवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन, सामर्थ्य विश्लेषण, न्यूनीकरण विश्लेषण इत्यादि। (आई सी एस एस आर फंड का बुंदेलखंड सूखा परियोजना, एम सी डी परियोजना के अंतर्गत भवनों का

आर बी एस इत्यादि)

- डी आर आर प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण के लिए उपकरण तैयार करना (जैसे— विश्व बैंक, चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना, इको डी आर एम के तहत विकसित मिश्रित शिक्षार्जन मंच इत्यादि के अंतर्गत भारत में आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन की समय प्रणाली को नया रूप देने हेतु भारत के लिए प्रासंगिक मानकीकृत पी डी एन ए साधन विकसित करना)
- नेटवर्किंग और ज्ञान सहयोगिता परियोजनाएँ: ऐसे परियोजनाओं का उद्देश्य आपदा निवारण तथा न्यूनीकरण में तकनीकी ज्ञान एवं सूचना का आदान-प्रदान, कार्यशालाओं का आयोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा डी आर एम हेतु क्षेत्र भ्रमण तथा पारस्परिक हितों के संबंध में पुस्तकों, पत्रिकाओं, पर्चों इत्यादि का प्रकाशन (भारत जापान सहयोग— इ के डी आर एस इत्यादि)।

3.2 उपकरण और तकनीकें

इन योजनाओं के लिए अपनाये गये अनुसंधान उपकरणों और तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विश्लेषण, वैज्ञानिक विधियाँ जैसे— जी आई एस तथा सुदूर संवेदन पर आधारित विश्लेषण इंजिनियरिंग विधियाँ यथा— आर वी एस सांख्यिकीय विधियाँ, सामाजिक विज्ञान विधियाँ जैसे कि नमूना सर्वेक्षण, संरचनात्मक साक्षात्कार, घटना अध्ययन, प्रतिभागिता शिक्षार्जन दृष्टिकोण इत्यादि शामिल हैं।

3.3 जारी/ समाप्त परियोजनाएँ

एनआईडीएम ने स्थापना के बाद अनेक परामर्श तथा अनुसंधान संबंधी परियोजनाओं की शुरुवात की है। इसके द्वारा प्रारंभ की गई कुछ परियोजनाओं की विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

सारणी 3.1: एनआईडीएम द्वारा विगत में प्रारंभ परियोजनाएँ

क्र सं	परियोजना का नाम
1.	बढ़ी हुई तैयारियों और तीव्र प्रतिक्रिया की दिशा में प्रशासनिक सुधार
2.	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु सामर्थ्य विकास— एम ओ इ एफ जी एफ भारत में जलवायु परिवर्तन परियोजना
3.	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एम ओ इ एफ, टी इ आर आई, यू एन डी पी सामाजिक तथा पर्यावरण परिवर्तन संस्थान के साथ संयुक्त पहल)।
4.	वृहत्तर हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक तथा अति न्यून जल के संबंध में स्थानीय प्रतिक्रिया (आई सी आई एम ओ डी के साथ)।
5.	ग्रेटर नोएडा टिवन टाउनशीप आपदा योजना
6.	नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए आपदा प्रबंधन योजना (सी आई डी सी ओ के सहयोग से)
7.	शहरी बाढ़ घटना अध्ययन परियोजना
8.	मार्गदर्शनों, मॉड्यूलों तथा क्रियाविधियों का विकास।
9.	आकस्मिक क्रिया प्रणाली (आई आर एस) मॉड्यूल (यु एस ए आई डी के साथ पारंपरीकरण)
10.	मुख्य धारा से संबंधित उत्पादक स्वास्थ्य (आर एच), लिंग आधारित तीव्रता सहित लिंग (जी बी बी) तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मनोसामाजिक सहायता (पी एस एस) कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए संयुक्त सामर्थ्य निर्माण हस्तक्षेप।
11.	ललिता पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली का न्यायिक अन्वेषण, तीव्रगामी दृश्य समिति द्वारा दिल्ली में भुक्पीय सुरक्षा आकलन।
12.	बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सूखा असुरक्षा तथा न्यूनीकरण विश्लेषण (आई सी एस एस आर परियोजना)

13.	आपदा जोखिम प्रबंधन (इ के डी आर एम) का पर्यावरणीय जानकारी।
14.	सी सी ए और डी आर आर को जिला स्तरीय विकास योजना की मुख्य धारा में लाना (जी इ ए जी और आई एस इ टी के साथ संयुक्त रूप से सी डी के एन परियोजना)।

वर्ष 2014–15 की अवधि में संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर किये गये अनुसंधान अध्ययन की मुख्य बिंदु इस प्रकार है:

3.3.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) देश में चक्रवात के जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक मापमंडों की खोज करती है। एनसीआरएमपी का परियोजना विकास उद्देश्य चक्रवातों तथा अन्य हाइड्रो मौसम विज्ञान संबंधी जोखिमों से तटीय समुदाय की असुरक्षा को इन विधियों द्वारा कम करना है:

1. बेहतर शीघ्र बिखराव चेतावनी प्रणाली
2. आपदा के प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय समुदायों के बृहत्तर सामर्थ्य।
3. उच्च जोखिम क्षेत्रों में हवा, आँधी, बाढ़ तथा तूफान के प्रकोप से बचने के लिए अपालकालीन आश्रय, खाली जगह का बेहतर प्रबंध।
4. जोखिम न्यूनीकरण मापदंडों को संयुक्त विकास एजेंडा के मुख्य धारा में लाने के लिए केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर डी आर एम क्षमता को मजबूत बनाना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर परियोजना को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है: (क) शीघ्र चेतावनी प्रणाली; (ख) चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण आधारीक संरचना; (ग) आपदा जोखिम प्रबंधन पर सामर्थ्य निर्माण के लिए तकनीकी सहायता; तथा (घ) परियोजना प्रबंधन और संचालन।

एन सी आर एम पी के घटक 'सी' का विशिष्ट उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को मुख्य धारा में लाने के लिए केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा जोखिम प्रबंधन (डी आर एम) को मजबूत बनाकर उन्हें समग्र विकास की कार्य सूची में शामिल करना है। इस घटक के तहत एनआईडीएम द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं: क) भारत में डी आर एम के लिए 'दीर्घकालीन प्रशिक्षण तथा सामर्थ्य निर्माण रणनीति' पर अध्ययन; और ख) भारत में आपदा पश्चात् क्षति तथा हानि और आवश्यक मूल्यांकन पर अध्ययन।

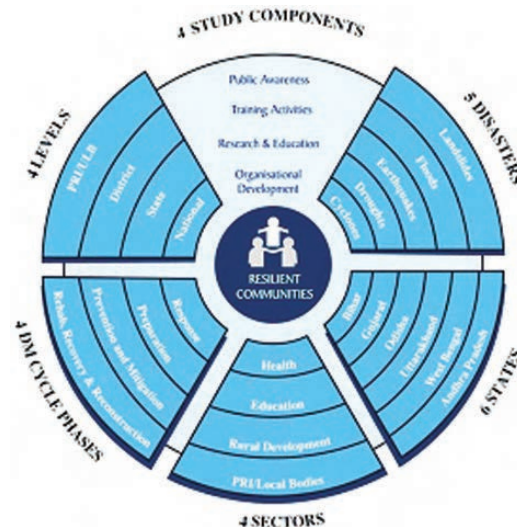
एनआईडीएम द्वारा किये गये दो अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है:

अध्ययन 1: भारत में आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए लंबी अवधि की प्रशिक्षण तथा सामर्थ्य निर्माण रणनीति तैयार करना

अध्ययन का उद्देश्य है, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रारूप की रणनीति बनाना तथा उसे गुणवत्ता के ऊपर केन्द्रित करने के लिए सुझाव देना; प्रत्यायन विधि; अनुसंधान और शिक्षा की शुरुवात; संगठन और संस्थान को मजबूत बनाना और आगे रणनीतिक जन जागरूकता सूत्रपात को बढ़ावा देना।

यह अध्ययन अपने आप में भेद तथा स्केल की दृष्टि से प्रथम है। अध्ययन संघटकों द्वारा संलग्न अध्ययन में देश में आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। यह क्षेत्र की गहराई में जाकर छः प्रतिनिधि नमूने राज्यों यथा— आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बहु-जोखिम पहुँच के साथ देशव्यापी अध्ययन था (चित्र 3.1 तथा 3.2)। यह सामर्थ्य विकास संरचना को वितरित करने के लिए लक्ष्यबद्ध है, जिसमें शामिल हैं: सभी बड़े आपदा में, जैसे— भूकंपों, भू-स्खलनों, चक्रवातों, बाढ़ों, सूखा इत्यादि में प्रशिक्षण तथा सामर्थ्य निर्माण करना; कुछ मुख्य क्षेत्रों में जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया, ग्रामीण विकास, पी आर आई/स्थानीय इकाईयों; और पंचायत स्तर से जिला स्तर तक तथा

राज्य स्तर से केन्द्र स्तर तक, भी शामिल है।



चित्र 3.1: अध्ययन ढाँचा

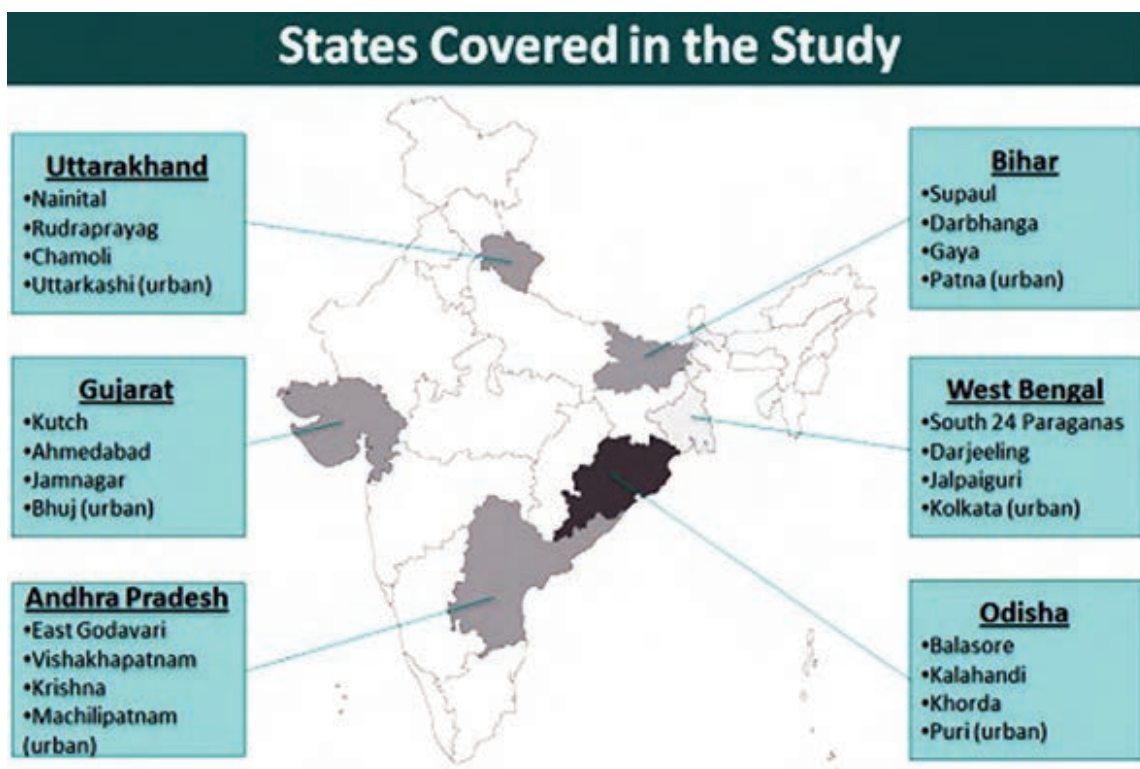
इस अध्ययन के द्वारा विकसित सामर्थ्य निर्माण पर विस्तृत तथा सारगर्भित रणनीति को निम्नलिखित चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क) प्रशिक्षण क्रियाकलाप: रणनीति के इस भाग में प्रशिक्षण अंतराल तथा आवश्यकता का विश्लेषण, जो भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रशिक्षण के कार्यान्वयन कर रणनीति संरचना के विकास का नेतृत्व करती है, शामिल है। यह सरकार के विचार के लिए मसौदा प्रशिक्षण रणनीति के विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, पंचायती राज संस्थान (पी आर आई) / शहरी स्थानीय निकायों, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए माड्यूल के सेट की माँग भी करती है।

ख) अनुसंधान और शिक्षा: अध्ययन का भाग 'बी' आपदा प्रबंधन से संबंधित शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत बनाने पर केन्द्रित था। इसमें वर्तमान सुविधाओं का एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण शामिल था। इस क्षेत्र में प्रत्यायन मानदंडों के अभाव को देखकर, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान

कार्यक्रमों और स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों तक औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए

प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, प्रत्यायन और गुणवत्ता प्रबंधन का विकास अध्ययन के इस भाग में किया गया।



चित्र 3.2: अध्ययन के दौरान देश के प्रतिनिधि के रूप में शामिल राज्य और जिले

ग) **जन जागरण** : मीडिया की मुख्य भूमिका तथा नागरिक जागरूकता को स्वीकार करते हुए, भाग 'सी' आपदा रिपोर्ट को मजबूत बनाने तथा सामान्य जनता को आपदा संबंधित सूचना प्रभावी रूप से देने पर केन्द्रित रहा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय मीडिया अभियान के लिए एक रणनीति बनाई गई। वरिष्ठ पत्रकार, पी आई ओ तथा पी आर ओ; और प्रवेश स्तर के पत्रकारों, दोनों के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया। आपदा रिपोर्ट के सिद्धांत पर एक हस्त-पुस्तिका और दिशा-निर्देश भी बनाया गया ताकि यह इस योजना के अंतर्गत संगत हितधारकों के लिए हस्त गाइड के रूप में प्रयोग हो सके।

घ) **सांगठनिक तथा सांस्थानिक विकास**: अध्ययन के भाग 'डी' में विधिक तथा सांस्थानिक अंतराल के पहचान तथा राज्य और राष्ट्रीय अधिनियमों और नीतियों के कार्यान्वयन के कारण अंशछादन (ओवरलैप) संबंधी मुद्दे को संबोधित किया गया। इस भाग में राष्ट्रीय स्तर पर नीति तथा पिछले आपदा प्रबंधन में संरचनाओं और विधिक, सांस्थानिक तथा सांगठनिक प्रबंध को जगह पर सहयोगिता तथा पर्याप्तता को विश्लेषित किया गया। इसके बाद इसे जरूरतों को पहचानने तथा भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश का विकास करने के लिए उपयोग किया गया। भारत के

लिए सामर्थ्य निर्माण तथा डी आर आर में प्रशिक्षण के लिए एक श्वेत पत्र का विकास भी किया गया।

मुख्य खोज

परियोजना की मुख्य खोज इस प्रकार है:

- विभिन्न स्तरों पर सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं को देश में आपदा प्रबंधन मुद्दों को संबोधित करने के लिए मुलभूत निम्नतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने हेतु प्रथम स्तर में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- भारत में डी आर आर के प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण के लिए तत्काल प्रभाव से एक राष्ट्रीय नीति कार्यान्वयन का आधार होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निचले स्तर तक पहुँच रही है।
- विषय से संबंधित कुल 52 क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है जिसमें 12 की प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।
- आपदा क्षेत्र के सभी चरणों में मीडिया मुख्य भूमिका निभाती है। पत्रकारों, पी आई ओ और पी आर ओ का प्रशिक्षण आपदा रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान के साथ मिलकर, इससे सुरक्षा की संस्कृति निर्माण होने में मदद मिल सकती है।
- बचे हुए खोज को स्थिर बनाने के लिए तथा जोखिम के लिए स्थिरांकों के रूप में सेवा करने के लिए क्षेत्रीय तथा भू-जलवायु विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता केन्द्रों का स्थापना होना चाहिए (वर्तमान और नये संस्थानों, दोनों के लिए)।
- राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक के सांस्थानिक तथा सांगठनिक स्थापना नवीनीकरण

की तथा इसपर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

आगे का कार्य

आपदा प्रतिस्कंदित समाज में नियत सामर्थ्य विकास को आगे ले जाने के लिए तथा इसे कार्यान्वयन योग्य अनुमोदन के विकास में लाने के लिए रिपोर्ट, माड्युल और कार्यशालाओं के रूप में इसमें कई मुद्दे हैं, जो इस प्रकार हैं:

- क) प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण को संपादित करने के लिए रणनीति एनआईडीएम के विचार बिंदु को मुख्य धारा में लाने का एक कार्य नीति है तथा प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण रणनीति पर एक श्वेत पत्र है।
- ख) एक विस्तृत ज्ञान प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान देने हेतु आपदा प्रबंधन शिक्षा के लिए एक रोडमैप का अनुमोदन किया गया है जो आपदा प्रबंधन अनुसंधान और शिक्षा को प्रबल बनाता है।
 - आपदा प्रबंधन अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक सरकारी मान्यता इकाई।
- ग) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता अभियान।
- घ) उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना
- ङ) राज्य स्तरीय मानव संसाधन तथा सामर्थ्य विकास योजनाओं का विकास।
- च) अध्ययन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और पहले से विकसित माँड्युल पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सुझाव दिये गये बचे हुए माँड्युल का विकास।
- छ) विस्तृत उपयोग के लिए पहले से विकसित माँड्युल का ऑन-लाइन रूप में परिवर्तन।

भारत में डी आर आर के प्रशिक्षण का निष्पादन तथा सामर्थ्य निर्माण रणनीति की प्रचालनात्मक योजना में उपर्युक्त बताये गये अनुमोदन को शामिल किया गया है तथा इसे एन सी आर एम पी, पी एम यू, एन डी एम ए को सुपुर्द किया गया है।

अध्ययन 2- भारत के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताएँ (15 जनवरी 2014 से 30 दिसंबर 2015)

अध्ययन का उद्देश्य था, भारत के लिए उपयुक्त मानकीकृत पीडीएनए साधन विकसित करना, नये पी डी एन ए साधनों को मौजूदा प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने के लिए अनुशंसाएँ उपलब्ध कराना, संगत हितधारकों के सामर्थ्य/सहायता को पहचानना तथा उसे प्रबल बनाना तथा भविष्य में विकसित किये जाने वाले नये पी डी एन ए साधनों के उपयोग द्वारा अनुवर्ती आकलन के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना जिसका विकास यथार्थ समय पर किया जाएगा।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के लिए वैज्ञानिक और वस्तुपरक दृष्टिकोण पर आधारित मानकीकृत उपकरणों का विकास करना है। इसे निम्नलिखित दस प्रतिनिधि राज्यों के लिए विकसित किया जाएगा— तमिलनाडु, आंध्र-प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र। इस अध्ययन से ऐसे उपकरणों को विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत में प्रचलित वर्तमान पीडीएनए प्रणाली में मौजूद कमियों को भरा जा सकेगा। इससे एक मजबूत आपदा पश्चात नुकसान और आवश्यकता मूल्यांकन तंत्र प्राप्त होगा।

संपूर्ण उद्देश्यों को चार मुख्य क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त किया जाएगा:

- भारत के लिए पी डी एन ए उपकरणों का विकास।
- उपकरणों और प्रशिक्षण का फैलाव।
- पी डी एन ए उपकरणों का पायलट जाँच।
- निजी क्षेत्र के नुकसानों के लेखा के लिए पर श्वेत पत्र।

प्रगति

एनआईडीएम इस अध्ययन को एशियन आपदा तैयारी केन्द्र, थाइलैंड के सहयोग से कार्यान्वित कर रही है। चूँकि, आपदा पश्चात आवश्यक मूल्यांकन में राज्य

प्रमुख हितधारकों में होते हैं, इसीलिए एनआईडीएम ने अध्ययन के एकदम प्रारंभ से ही राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है।

वर्तमान समय में उपलब्ध आपदा पश्चात आवश्यक मूल्यांकन पर— उसके आपदा पश्चात आवश्यकता के सुधार और पुनर्निर्माण के आकलन के विस्तार और अनुकूलता के लिए— भारत के दस चुने हुए आपदा प्रभावित राज्यों का, विश्व के अन्य क्षेत्रों में समान स्थिति वाले अभ्यास के साथ तुलना पर एक विश्लेषण किया गया।

आपदा प्रभाव के हाल ही के कई घटना अध्ययन के विश्लेषण और आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें अधिकांश में भारत के पी डी एन ए परियोजना दल के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में शामिल थे, विश्व के अन्य विकासशील देशों के उद्देश्य से किये गये वर्तमान अभ्यासों की एक जाँच की गई। इसी प्रकार भारत में वर्तमान मूल्यांकन अभ्यास पर रिपोर्ट बनाई गई, जिसके लिए भारत में पी डी एन ए परियोजना में शामिल किये गये आपदा वाले राज्यों का दौरा किया गया। मजबूती-कमजोरी-मौका-डर (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण के आधार पर भारत तथा विश्व के अन्य भागों के बीच का इन वर्तमान अभ्यास पर तुलना (किया गया) बनाया गया है, जो भारत के वर्तमान प्रणाली में सुधार का आधार उपलब्ध कराएगी।

किये गये विश्लेषण में भारत के आपदा पश्चात मूल्यांकन के वर्तमान प्रणाली के विस्तार और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में कई महत्वपूर्ण अंतराल दिखाता है जिसे निम्नलिखित चरणों में संक्षेप में बताया गया है:

- भारत में आपदा पश्चात मूल्यांकन के वर्तमान प्रणाली को पूर्ण रूप से केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आपदा राहत प्रतिक्रिया के आकलन के आधार पर और पुनर्वास के सिर्फ अल्प आवश्यकता के आधार पर डिजाइन किया गया है।
- प्रतिक्रिया सहायता का मूल्य का डिजाइन आपदा के कारण क्षति और हानि के कुल

मूल्य के रूप में किया गया है, और इस प्रकार इसका परिणाम आपदा के प्रभाव का पूरी तरह से निम्न आकलन होता है।

- वर्तमान मूल्यांकन से, भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को आपदा का कुल मूल्य उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
- वर्तमान पद्धति का मूल्यांकन कुल प्रभावित जनसंख्या के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलाप के सभी प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। उदाहरण के रूप में, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय, पर्यटन और खनन क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है; और खेती के अंतर्गत सिर्फ खाद्य पौधे को ही शामिल किया गया है, जो चाय और अन्य व्यावसायिक फसलों के उत्पादन और निर्यात के संभावित हानि को शामिल नहीं करता है। कुछ स्थिति में आपदा प्रभावित लोगों के मनो-सामाजिक सहायता के लिए कोई आकलन नहीं किया जाता है।
- सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था स्तर पर आपदा के प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी उत्पादित क्षेत्रों में उत्पादन हानि प्रणाली के आधार पर आकलित नहीं की जाती है।
- वैयक्तिक और घर के आधार पर आपदा के प्रभाव का सिर्फ आंशिक आकलन ही किया जाता है— जो वास्तव में, व्यक्तिगत और पारिवारिक आमदनी के पतन के आकलन को रोकता है, तथा रहन-सहन के मूल्य को बढ़ाता है। और इसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म-सामाजिक प्रभाव तथा उपयुक्त विकास लक्ष्य (एम डी जी) को पाने में हुए बिलम्ब के लिए कोई आकलन नहीं किया जाता है
- वर्तमान प्रणाली उत्पादन, व्यक्तिगत आमदनी,

लोगों के लिए मुलभूत सेवाओं की आपूर्ति में वापसी के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन नहीं करती है और इसका वर्तमान प्रमाण यह होता है कि प्रभावित व्यक्ति या तो आपदा से वापसी नहीं कर पाते हैं या वापसी में उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

- घर पुनर्निर्माण और मरम्मत में सहायता के लिए वर्तमान अनुमान, घर के मालिक की आवश्यकता राशी का कुछ अंश ही उपलब्ध कराती है; वचत या अन्य वित्तीय सहायता की अनुपस्थिति में, परिवारों को उप-मानक सामग्रियों के अनुसार ही अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए बाध्य किया जाता है, जिसका परिणाम आपदा से पहले के खतरों से अधिक आपदा जोखिम का डर होता है।
- इससे भी आगे, इसका प्रमाण है कि कम से कम कुछ मामलों में सड़कों का पुनर्निर्माण आपदा जोखिम न्यूनीकरण मापदंड का अनुसरण नहीं करता है, इसका परिणाम भविष्य के लिए और अधिक जोखिम होता है।
- यह सच्चाई है कि सड़कों और सार्वजनिक संपत्ति के पुनर्संरचना के प्रचालन का मूल्य नियमित राज्य बजट से दिया जाता है, इसके परिणामस्वरूप अनुरक्षण के लिए निधि के कम मात्रा में उपलब्ध होना होता है, जो वास्तव में वर्तमान अवसंरचना के वास्तविक जीवन को कम करता है, और गाड़ियों के संचालन में अधिक कीमत का भार देता है।

यदि सरकार आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव को संबोधित के लिए उत्साहित है तो इस मामले में तत्काल ध्यान दें तथा इसके समाधान की आवश्यकता है।

यह अनुमोदित की जाती है कि आपदा पश्च मूल्यांकन की वर्तमान पद्धतियाँ जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, भारत के विशिष्ट लक्षणों वाली

आपदा में अपनायी जाए, जिससे कि सरकार इसके आकस्मिक स्वीकार्य पर विचार कर सके।

अनुमानित परिणाम

देश में आपदा पश्च आवश्यकता मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने के अतिरिक्त, जो मूल्यांकन के पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके को सुनिश्चित करता है, यह वर्तमान में उपस्थित अंतराल को भी संबोधित करता है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर पीडीएनए के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधनों का समुच्चय उपलब्ध कराएगा। परियोजना का अंतिम परिणाम निम्नलिखित होगा:

- भारत में पीडीएनए की वर्तमान पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तथा प्रलेखन।
- दीर्घकालीन पुनर्प्राप्ति संरचना सहित भारत में पीडीएनए हेतु मानकीकृत उपकरणों तथा तकनीकों का समुच्चय
- पीडीएनए के लिए मानक प्रपत्र का समुच्चय।
- भारत के लिए पीडीएनए के ऊपर मैनुवल और उपयोगकर्ता हस्त पुस्तिका।
- भारत में पीडीएनए के मानकीकरण पर परामर्शी कार्यशाला।
- पीडीएनए प्रशिक्षण पैकेज।
- पीडीएनए पेशेवरों का पैनल बनाने हेतु राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पीडीएनए प्रशिक्षण।
- भारत में पीडीएनए के लिए वेब पोर्टल।
- आपदाओं में निजी हानियों हेतु लेखा पर श्वेत पत्र।
- अंतिम रिपोर्ट

इस परियोजना से राज्य सरकारों को और अधिक ठीक और पारदर्शी तरीके से आपदा के दौरान हुए नुकसान का अनुमान लगाने में अंततः सहायता मिलेगी तथा प्रभावित क्षेत्रों में मानक तरीके पर

आधारित आवश्यकताओं की स्थापना उसके द्वारा की जा सकेगी।

3.3.2 पूर्व एशिया सम्मेलन भूकंप जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (इएस-इआरआर)

इएस “भारत कार्यशाला 2012: भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय संरचना का निर्माण” के परिणामों के अनुसरण के रूप में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में पूर्व एशिया सम्मेलन भूकंप न्यूनीकरण की स्थापना की है।

उद्देश्य

इएस-इआरआर का उद्देश्य है:

- आपदा अनुक्रिया के दौरान इएसएस क्षेत्र से बाहर के सभी देशों तथा इसके सदस्य देशों को सीमा पार सहायता स्थापना के लिए लाना;
- प्रभावित राष्ट्रों में सीमापार अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना और प्रभावित देशों हेतु जीवन रक्षक दवाइयों, तलाशी कुत्तों इत्यादि सहित तलाशी और बचाव दलों का प्रवेश जैसी अपातकालीन सहायता के परिवर्तन के पहलुओं हेतु अपातकालीन संरचना तथा विकसित हो रहे एस ओ पी को विकसित करना;
- ऐसे आपदा के बहुपार्श्विक अनुक्रिया के विभिन्न पहलुओं, जिससे बहुल देशों पर प्रभाव पड़ता है, से निपटना; और
- आपदा के विरुद्ध बहुल दिशात्मक उपायों के समन्वयन के लिए मार्गचित्र उपलब्ध कराना।

प्राकृतिक आपदा जोखिम मूल्यांकन, न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया पर आधारित जानकारी तथा उत्कृष्ट अभ्यास को साझा करने के लिए भारत सरकार द्वारा वेब पर आधारित यंत्र के रूप में एक काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वीकेपी) तथा संपर्क बिंदु (पीओसी-इएसी देशों) की स्थापना का प्रावधान भी रखा गया। इसके अतिरिक्त और इ एस देशों में भूकंप तथा अन्य प्राकृतिक आपदा के बाद बहुपक्षीय सहायता प्रदान करने के

लिए वेब सेवा प्रदान करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। पोर्टल का विकास तथा आतिथ्य इ ए एस-इ आर आर केन्द्र द्वारा किया गया। यह अपेक्षा की जाती है कि पोर्टल मुख्य प्राकृतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय आपदाओं के तत्काल घटित होने पर अंतर्ष्तीय प्रतिक्रियावादियों के सहयोग में सुधार लाएगा। 24x7 पी ओ सी और वी के पी का नेटवर्क एक दूसरे के पूरक होंगे। इएएस-इआरआर काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वीकेपी) यू आर एल <http://eas-india.org/> पर उपलब्ध है (चित्र 3.3)। वी के पी में भारत के विभिन्न प्रकार के संसाधनों को सूचीबद्ध किया गया है। अन्य सदस्य देशों से भी समान सूचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाता है। इ ए एस-इ आर आर केन्द्र वी के पी का आतिथ्य करता है और सदस्य देशों को उनके अपने समाप्ति पर टेक्स्ट, प्रतिबिंबों और पी डी एफ इत्यादि के रूप में सूचना अपलोड कर इसे क्रियाशील बनाने का इरादा रखता है।



चित्र 3.3: इएएस-इआरआर काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वी के पी) होम पेज

इएएस-इआरआर “केन्द्र इएएस देशों के एएसइएम के बीच आपदा बचाव प्रयासों पर तकनीकियों का नवीकरण और काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वीकेपी) का उदघाटन तथा 24 x 7 संपर्क बिंदु (पीओसी) पर

बैठक” पर 4-5 दिसंबर 2014 को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के सहयोग से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दो दिवसीय राउण्ड टेबल बैठकों का आयोजन किया है। गोलमेज सम्मेलन में 26 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 360 से अधिक प्रतिनिधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे इ यू और एसियन ने भाग लिया।

इएएस-इआरआर केन्द्र ने निकट भविष्य में एमएचए और एमइए के सहयोग से निम्नलिखित कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए प्रस्तावित किया है:

- भूकंप सुरक्षित हाउसिंग तकनीक-नवीकरण और अभ्यास
- भूकंप आपदा प्रतिक्रिया- अनुभव और सूत्रपात

3.3.3 सूखा प्रबंधन और राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन योजना के लिए मैनुवल का संशोधन

यह परियोजना डी एम अधिनियम, 2005 के आधार पर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के लिए सूखा प्रबंधन और राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन योजना के विकास के मैनुवल के संशोधन के लिए है। कृषि मंत्रालय के लिए ‘सूखा प्रबंधन पर मैनुवल’ एनआईडीएम द्वारा 2009 में तैयार किया गया था, ऐसे प्रलेख बनाने में बहुत प्रयास किये जाने तथा इस मैनुवल की आवश्यकता देश में राज्य स्तर पर किये जाने के कारण मंत्रालय द्वारा इसका प्रशंसा किया गया।

उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य सूखा प्रबंधन के लिए मैनुवल को संशोधित करना तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन योजना विकसित करना है। मैनुवल को अद्यतन करने तथा अलग राष्ट्रीय डीएम योजना तैयार की तथा दोनों को एक साथ नहीं करने की आवश्यकता के लिए सर्व-सहमति है, क्योंकि दोनों में कुछ समान मुद्दे होने के बावजूद भी ये अलग-अलग उद्देश्यों के लिए है।

प्रगति

25 मार्च, 2015 को परियोजना के बारे में विचार-विमर्श के लिए एनआईडीएम में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक का आयोजन किया गया (चित्र 3.4)। इसमें कृषि मंत्रालय, एनआरएससी, सीएजेडआरआई, आईएआरआई, एनआरएए, राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, एनआईडीएम तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा सूखा मैनुवल के संशोधन में विभिन्न प्रस्ताव भी दिया।



चित्र 3.4: ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक में वार्ता करते हुए प्रतिभागी

सूखा मैनुवल के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त सचिव, एमओए के अंतर्गत तथा सहायक सचिव एन आई डी एम, सदस्य सचिव के रूप में एक समिति तथा एक कोर समूह गठित करने का निर्णय भी लिया गया। आगे यह समिति/समूह समय पर उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए परियोजना के रूप में इन कार्यों का संपादन करेगा।

उपलब्धियाँ

सभी प्रतिभागी मैनुवल के अद्यतन के पक्ष में थे जिसके मुद्दों में आवर्ती असुरक्षा मूल्यांकन, अग्रिम तकनीक और सही मूल्यांकन तथा प्रबंधन की पहुँच, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डीआरआर तथा डीएस आर जैसे संदर्भ का सम्मिलन, जल संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सूखा प्रतिरोधक फसल किस्मों, सरलीकृत फसल वीमा प्रणाली, सामर्थ्य निर्माण तथा सांस्थानिक क्षमता का मजबूतीकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया

निधि(एसडीआरएफ), आर के वाइ योजना, राज्य सूखा मैनुवल की तैयारी, इत्यादि शामिल थे।

इसके अतिरिक्त, जून-जुलाई 2015 के दौरान एनआईडीएमके हाइड्रो-मेट शाखा द्वारा कृषि मंत्रालय में क्रमशः दो कोर समिति के गठन को प्रस्तावित किया गया; पहला संशोधन सूखा मैनुवल का था और दूसरा राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन मैनुवल की तैयारी के लिए था, जिसे बाद में मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई।

आगे, उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए अगला कार्य सूखा मैनुवल को संशोधित करने की विधि को प्रारंभ करना तथा राष्ट्रीय सूखा प्रबंधन मैनुवल को तैयार करना है।

3.3.4 बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा के लिए घातकता तथा न्यूनीकरण विश्लेषण (आईसीएसएसआर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजना)

“बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा के लिए घातकता मूल्यांकन तथा न्यूनीकरण विश्लेषण” के ऊपर अनुसंधान को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा वित्त पोषित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्यम स्तर से गंभीर सूखा की स्थिति के प्रभाव की स्थिति का आकलन करना निर्धारित किया गया ताकि सूखे की रोकथाम के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार की जा सकें। इस परियोजना के तहत सांख्यिकीय तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के सूखों जैसे कि जलवायु विज्ञान संबंधी, जल विज्ञान संबंधी तथा कृषि संबंधी सूखा और आकाशीय तथा स्थलीय पद्धतियों का अध्ययन किया जाएगा। तीन जिलों जैसे ललितपुर (उत्तर प्रदेश), टीकमगढ़(मध्य प्रदेश) तथा दतिया के विस्तृत विश्लेषण के तौर पर सरकार के विभिन्न हस्तक्षेपों को समझने के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा समुदायों द्वारा सूखे के प्रभाव को कम करने का भी विश्लेषण किया गया है।

इस कार्य में सूखे की स्थिति का आकलन करने तथा संबंधित आंकड़े को संग्रहित करने के लिए क्षेत्र का दौरा, संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और

सूखा जोखिम के संदर्भ में घातकता और न्यूनीकरण संकेतों के संबंध में आंकड़ा संग्रहण प्रारूपों (जिला और उप-जिला स्तर पर) का विकास सम्मिलित है। यह परियोजना लोगों के कार्यों, विशेष रूप से जल और कृषि प्रबंधन प्रकृति की अनुकूलता के अतिरिक्त सूखा प्रभावों के अल्पावधि तथा दीर्घावधि न्यूनीकरण से संबंधित स्थल विशिष्ट हस्तक्षेप का महत्त्व समझने में लाभप्रद पाई गई है। इसके अलावा इसके द्वारा आपदा की स्थिति में पारिस्थितिकीय प्रणाली की अनुकूलता और लोगों की मनोवृत्ति की भूमिका का संकेत भी दिया गया है। इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या से नीति निर्माता विषय को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे तथा क्षेत्र में सूखा न्यूनीकरण विश्लेषण अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

उद्देश्य

- क) जिला स्तर पर बुधदेलखंड के सभी 13 जिलों में तीनों प्रकार के सभी सूखे के लिए सूखा संकट घातकता तथा आवृत्ति का विश्लेषण करना।
- ख) जिला स्तर पर सूखे के प्रभाव का विशिष्ट तथा संयुक्त घातकता का मूल्यांकन करना।
- ग) बुधदेलखंड के लिए जिला स्तर पर संभावित सूखा संकट क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना।
- घ) सूखे के संकटों के विरुद्ध विद्यमान लघुकरण उपायों का विश्लेषण करना।

अध्ययन एक दूसरे से संबंधित निम्नलिखित तीन चरणों में किया गया:

चरण 1: भाषा पर्यवेक्षण और आंकड़ा संग्रह।

वर्तमान अध्ययन के संदर्भ में सूखे से संकट तथा असुरक्षा का अध्ययन तथा उसकी प्रासंगिकता के लिए उसका विश्लेषण प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन से किया गया है। इसके अतिरिक्त बुधदेलखंड में सूखे से संबंधित जोखिमों को समझने के लिए वर्तमान साहित्य का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। जन सांख्यिकीय भौगोलिक तथा आर्थिक पार्श्विका सहित सामान्य पार्श्विका जनगणना 2011 तथा सामाजिक आर्थिक जनगणना और केन्द्रीय

भूमि जल बोर्ड तथा अन्य वेब स्रोतों द्वारा विकसित जिला पार्श्विकों का उपयोग कर सभी जिलों के लिए भी आंकड़ा संकलित की गई। सभी तीन प्रकार के सूखों अर्थात् मौसम विज्ञानी, जन विज्ञानी तथा कृषि संकेतकों के लिए आंकड़ों का संग्रहण, प्रोसेसिंग तथा आकलन इस अध्ययन के इस चरण द्वारा की गई।

चरण 2: सूखा जोखिम तथा असुरक्षा विश्लेषण

तीनों प्रकार के सभी सूखों के लिए अंतिम 12 वर्षों तक का आवृत्ति तथा गहनता संगणनाएं, संकट तथा घातकता मानचित्रों के निर्माण के लिए आवृत्ति और गहनता को जोड़कर आंकड़े का विश्लेषण तैयार किया गया था, इसके बाद सूखा घटना के कालक्रम की पहचान की गई थी। वैयक्तिक जोखिम तथा असुरक्षा मानचित्रों की तैयारी कर लेने के बाद जिला स्तर पर पूरे क्षेत्र के लिए 'संयुक्त सूखा जोखिम मानचित्र' की प्राप्ति के लिए प्रत्येक श्रेणी को उपयुक्त रैंक का महत्ता प्रदान किया जाता है।

चरण 3: सूखा जोखिम न्यूनीकरण विश्लेषण

कृषि तथा जल विज्ञान से संबंधित सूखा को कम करने में मदद करने वाले विभिन्न संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक उपायों अर्थात् कृषि और जीवन निर्वाह सहित जल अभाव और प्राकृतिक संसाधनों पर मौसम वैज्ञानिक प्रभाव तथा जो सूखने की स्थिति से जूझने में सहायक होते हैं, का अध्ययन इस चरण में किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इस क्षेत्र में सूखा के प्रमाण के लिए संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक उपायों को कार्यान्वित किया, जिसका अध्ययन विस्तार से किया गया।

विस्तृत न्यूनीकरण विश्लेषण अध्ययन के लिए तीन जिलों, ललितपुर (उत्तर प्रदेश), दतिया (मध्य प्रदेश) और टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) का चयन किया गया। विकास कार्यक्रमों में से अधिकांश जैसे- चालू तथा हाल ही में पूरा हुए कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लिया गया तथा सूखा न्यूनीकरण में उनके महत्त्व को समझने के लिए इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा इनके घटकों का विश्लेषण किया गया। 'बुधदेलखंड पैकेज' तथा पैकेज

के अंतर्गत के गतिविधियों को विशेष महत्व दिया गया है, चूँकि बुंदेलखंड पैकेज के अंदर अनेक हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सूखा प्रमाण प्रयोजनों का समर्थन करना था। संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक, दोनों उपायों का विश्लेषण किया गया। जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श के अतिरिक्त संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठन भी इस विस्तृत असुरक्षा और न्यूनीकरण विश्लेषण के अध्ययन के भागीदार थे। इस विश्लेषण को सूखा न्यूनीकरण उपायों के लिए प्रभावकारी मानने की दिशा में सहायक समझा गया (चित्र 3.5)। दिसंबर 2013 में अनुसंधान अध्ययन की रिपोर्ट आई सी एस एस आर को प्रस्तुत की गई थी। स्थानीय स्तर पर सरकार के आपदा न्यूनीकरण मूल्य को समझने के लिए तथा हस्तक्षेप के लिए एक नया उपकरण जिसका नाम “न्यूनीकरण विश्लेषण” है, को रणनीति विश्लेषण के लिए परिकल्पित तथा विकसित किया गया किया गया।



चित्र 3.5: चोपड़ा गाँव, दतिया में संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय (रूकावट बाँध)

3.3.5 आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय जानकारी (इकेडीआरएम इंडो-जर्मन कार्यक्रम)

सामरिक महत्व वाले उपकरण जैसे— इ आई ए, नियमों और विनियमों, घटना अध्ययनों, के अतिरिक्त सूचना, डाटा, मानचित्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जी आई एस प्रयोग के संबंध में ज्ञान तंत्र का प्रबंधन आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी आई जेड जर्मनी के साथ एक संयुक्त सहयोग परियोजना

का कार्यान्वयन भारत जर्मन पर्यावरण कार्यक्रम (आई जी इ पी) के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए (2010–13) आपदा संबंधी जोखिम विश्लेषण निर्णय सहायता प्रणाली, न्यूनीकरण तथा आपदा अनुक्रिया में पर्यावरण, सूचना तथा साधनों की भूमिका पर केन्द्रित एम ओ इ एफ सहयोग के एक घटक के रूप में किया गया है। “आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण तथा जानकारी प्रबंधन” को पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन के उभरते हुए मुद्दे को संबोधित करने तथा देश की स्थिति के अनुसार उपयुक्त उपकरणों तथा तकनीकों को विकसित करने के लिए परिकल्पित किया गया था, और इसका मार्ग डॉ अनिल कुमार गुप्ता (परियोजना निदेशक) और सुश्री श्रीजा एस नायर(कार्यक्रम निदेशक) द्वारा दिखाया गया था। परियोजना घटना अध्ययन, प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास और मिश्रित अधिगम पहुँच के प्रोन्नयन पर पाँच प्रासंगिक क्षेत्रों के साथ आधारित अनुसंधान पर केन्द्रित था, जैसे— क) डी आर एम के लिए पर्यावरणीय सांख्यिकी और डी आर एम; ख) डी आर आर में पर्यावरणीय विधान की भूमिका; ग) रासायनिक आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय योजना तथा भू उपयोग; घ) डी आर एम में पर्यावरणीय सेवाओं तथा इ आई ए की भूमिका; तथा ङ) डी आर आर के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन— जलवायु परिवर्तन अनुकूलन।

उद्देश्य

‘आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण तथा ज्ञान प्रबंधन’ (इ के डी आर एम) कार्यक्रम का लक्ष्य आपदा जोखिम प्रबंधन पर सामर्थ्य निर्माण पहलुओं को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मजबूत करना था:

- मूल्यांकन, योजना और घटना-अध्ययनों के लिए सांख्यिकीय/निर्णय सहायता प्रणाली के प्रयोग से आपदा जोखिम प्रबंधन के पर्यावरणीय पहलुओं पर बल देना।
- इ-लर्निंग, परामर्श तथा कार्यशालाओं सहित उदगामी/नवीकरण विधियों से प्रभावी नेटवर्क और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण प्रबंधन के

लिए वेब-समर्थित प्रणाली के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।

- जिला तथा गाँव स्तर पर जलवायु प्रतिस्कंदन आपदा प्रबंधन योजना का विकास करना।
- स्थानीय स्तर पर योजना बनाने के लिए सी सी ए तथा डी आर आर दृष्टिकोणों के एकीकरण पर तकनीकी प्रलेख तैयार करना।
- पर्यावरण और ज्ञान प्रबंधन के पहलुओं पर डी आर एम के लिए विचारों, विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, तथा अनुभव को साझा करना।

प्रगति और मुख्य उपलब्धियाँ

परियोजना की उपलब्धि रणनीतिक और नीति विधेय, घटना अध्ययन और प्रक्रिया प्रलेखों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय मंच और आदान-प्रदान कार्यक्रमों का संगठन, त्वरित वैज्ञानिक और जन जागरूकता का संचालन, तकनीकी उपयोग नवीकरणों, पुस्तकों और प्रशिक्षण मॉड्यूलों के संदर्भ में होता है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल:

- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए सांख्यिकी तथा डाटाबेस।
- आपदा जोखिम प्रबंधन में पर्यावरणीय विधिक की भूमिका।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना और आपदा जोखिम प्रबंधन।
- बाढ़ जोखिम प्रबंधन (गोरखपुर घटना-अध्ययन मॉड्यूल)।
- बाढ़ जोखिम प्रबंधन दृ जलविज्ञान संबंधी भविष्यवाणियाँ (बावारिया घटना-अध्ययन मॉड्यूल)।
- रासायनिक/औद्योगिकी आपदा जोखिम प्रबंधन में भू-सूचना कार्य।

अनुकूलन क्षमता

परियोजना 'भारत में असुरक्षित तटीय समुदायों की अनुकूलन क्षमताओं को बढ़ाना और उनके जोखिमों को कम करना' को भारत के आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु

राज्यों के लोगों के जानकारी में बृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के संदर्भ में तटीय समुदायों का योजना तथा अनुकूलन क्षमताएँ (सी सी ए), आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी डी आर) और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण (सी सी एम) के उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया गया था। आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम जिला और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला का क्षेत्रीय दौरा किया गया तथा प्राधिकारियों के साथ संपर्क बैठक



वर्ष 2013 में किया गया तथा जलवायु स्मार्ट आपदा प्रबंधन योजनाओं का सूत्रपात किया गया जिसमें जिला और राज्य स्तरों पर हितधारकों को शामिल किया गया। ग्राम्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में जिसमें तटीय समुदाय शामिल था, को मार्गदर्शी आधार पर 6 गाँवों के लिए सूत्रबद्ध किया गया था। थिरुवाल्लुर का वर्तमान डी डी एम पी की समीक्षा की गई और जिला प्राधिकारी को डी डी एम पी के लिए इनपुट के साथ-साथ संशोधित प्रारूप उपलब्ध कराया गया। परियोजना का कार्यान्वयन इ के डी आर एम कार्यक्रम के संपर्क उद्देश्य के साथ एन आर एम-डी आर एम के अंतर्गत जी आई जेड इंडिया (इंडो-जर्मन पर्यावरण कार्यक्रम) द्वारा एनआईडीएम के साथ संयुक्त रूप से किया गया।

3.3.6 जिला विभागीय योजनाओं में मुख्यधारायी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण

भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित गोरखपुर जिला को बाढ़ प्रभावित जिलों में सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है। यहाँ के निवासियों का मानसून ऋतुओं में दोबार बाढ़ आने का आदि हो जाने के बावजूद, पिछले 100 वर्षों का डाटा बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी दिखाता है, जो अब 3 से 4 वर्षों में वापस आती है, तथा कुछ भागों में यह वर्ष में एक बार भी आती है। गोरखपुर के 4.4 मिलियन निवासियों में अधिकांश ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही शहरों में रहते हैं। कुल जनसंख्या का पाँचवां भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसका कारण गरीब निवासियों द्वारा जीवन, स्वास्थ्य और रोजमर्रा खो देना है, तथा सार्वजनिक तथा नीजी संपत्ति की वृहत्तर क्षति है। उदाहरण के लिए 1998 के बाढ़ से 1.4 मिलियन लोग, 16,000 घरों, तथा 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (1 मिलियन डॉलर-60 भारतीय रुपया की दर से आकलित) अनुमानित खेती का नुकसान हुआ। एस

टी ए आर टी द्वारा प्रबंधित तथा सी डी के एन द्वारा समर्थित एक गतिक अनुसंधान कार्यक्रम वर्तमान में गोरखपुर में ऐसे कई मुद्दों को संबोधित कर रही है। गोरखपुर पर्यावरण गति समूह जी इ ए जी) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित, सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन संस्थान (आई एस ई टी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, कार्यक्रम का लक्ष्य गोरखपुर जिला के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन विचारार्थ को आपदा प्रबंधन योजना में प्रभावी रूप से समाविष्ट करना है।

मुख्य संदेश

- जिला आपदा प्रबंधन योजनाएँ का सृजन भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) के परिणालस्वरूप किया गया जो जिला स्तर पर जलवायु-सापेक्षिक योजनाओं को प्रोन्नत करने के लिए एक प्रभावी तंत्र हो सकता है।
- जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में जिला स्तर पर समेकित जलवायु संदर्भ 'साझा अधिगमित डायलॉग' प्रक्रिया को विभिन्न सरकारी विभागों के साथ प्रयोग कर जोड़ा जा सकता है। इसके लिए उचित सुविधाओं का होना आवश्यक है।
- 'साझा अधिगम डायलॉग' जलवायु जोखिमों को समझने, मूल्यांकित करने, योजना बनाने तथा प्रतिक्रिया करने में विभिन्न विभागों की सामर्थ्य का सृजन करने में महत्वपूर्ण है।
- जलवायु प्रक्षेपण को समुचित ढंग से अवश्य प्रकट करना चाहिए और इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रोत्साहकों द्वारा सरकारी विभागों में विकास कार्यक्रमों का आशय समझ में आ जाए।

जलवायु अनुकूलन और आपदा जोखिम के विकास के रूप में परिणाम में आए अध्ययन परियोजना जिला स्तर पर विकास योजनाओं/अवसंरचनाओं पर ध्यान केन्द्रित

करती है, तथा इससे सीख लिया जाता है, राज्य स्तर के साथ-साथ तथा केन्द्र स्तर पर फैलाया जाता है। परिणामों में जिला स्तर पर जलवायु लोच आपदा प्रबंधन योजना का विकास शामिल होता है जो मुख्य विभाग के साझा अधिगम पर आधारित होता है। इस विषय पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया गया था जिसे देश के सभी जिलों के साथ साझा किया गया।



अध्याय

4

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

विभिन्न परिमाण के आपदाओं से मुकाबला करने के लिए अपातकालीन तैयारी, न्यूनीकरण के तरीके तथा अनुक्रिया कार्य के कार्यान्वयन में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विस्तृत भूमिका होती है। ये प्रौद्योगिकियाँ एक विस्तृत संसाधन तथा सेवाएँ तैनात करने का प्रस्ताव करती हैं, यथा— जानकारी, सहयोग, नेटवर्किंग, मानचित्र, अपातकालीन संपर्क सूचना प्रणाली और विभिन्न आपदाओं से संबंधित विभिन्न आवश्यक सूचनाएँ। यह जानकारी साझा करने में मदद करती है और पारस्परिक विधि के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी पाने के लिए माहौल बनाती है।

4.1 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय(एमएचए) द्वारा जीओआई—यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2003 में, उपकरण और कुशल मानव संसाधनों का नियमबद्ध सूची का निर्माण करने के लिए किया गया, ताकि आपदा प्रबंधक संसाधनों का ब्यौरा और उसकी स्थिति को तत्काल अनुक्रिया के लिए तथा किमती समय को बर्बाद किये बिना आसानी से ढूँढ सके (चित्र 4.1)।



चित्र 4.1: नई आईआरडीएन पोर्टल का होम पेज

वस्तु-सूची जिला स्तर पर संबंधित विभिन्न लाइन विभागों और अनुक्रिया एजेंसी से इकट्ठा किया जाता है। प्राथमिक कार्य होता है कि निर्णय कर्ता को किसी भी अपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए आवश्यक उपकरण तथा मानव संसाधनों का तैयार उपलब्ध तथा अद्यतन सूचना का ब्यौरा प्राप्त करायें। यह डाटाबेस उन्हें किसी विशिष्ट आपदाओं के लिए तैयारी के स्तर को परखने में भी सहायता करेंगे। आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने 2008 से भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुवीक्षण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा है।

आईडीआरएन एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यह उपकरण, मानव संसाधनों तथा आवश्यक आपूर्तियों के बारे में, जो जिला स्तर पर लाइन विभागों और एजेंसी के पास उपलब्ध होते हैं, आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराती है। राज्य तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा किसी अपातकालीन स्थिति में, समय से सभी प्राप्त संसाधनों के बारे में अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिए आई आर डी एन का उपयोग किया जा सकता है जो किसी अपातकालीन स्थिति में जीवन की हानि तथा संपत्ति की क्षति को कम करने में काफी फायदेमंद होगा।

4.1.1. आईआरडीएन के मुख्य उपयोग

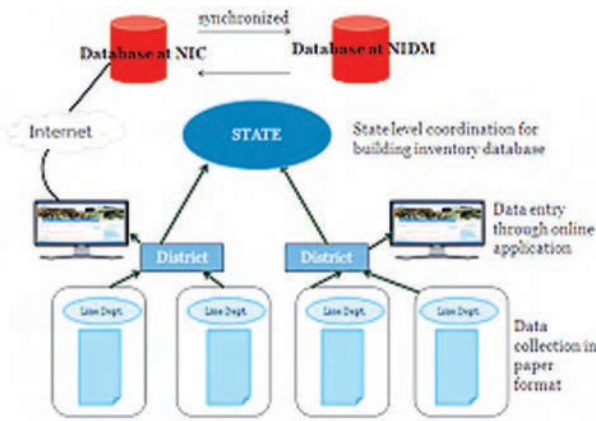
आईआरडीएन के निम्नलिखित मुख्य उपयोग हैं:

- वर्तमान मानव संसाधनों तथा उपकरणों को उसकी स्थिति तथा अन्य ब्यौरे के साथ पहचानना।
- जिला तथा राज्य स्तर पर अपातकालीन योजनाओं तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए संसाधनों का मानचित्रण
- तैयारियों का मूल्यांकन।

4.1.2. आईडीआरएन कैसे कार्य करता है?

आईडीआरएन पोर्टल का केन्द्रीय स्तर पर वर्तमान में अनुवीक्षण तथा अनुरक्षण एनआईडीएम द्वारा किया जाता

है। एनआईडीएम की भूमिका प्रयोगकर्ता के प्रशासन तक सीमित है। सहायता/राजस्व/आपदा प्रबंधन के राज्य विभाग तथा एसडीएमए जिलाधीशों/जिला कलेक्टरों के साथ आईडीआरएन पोर्टल में आंकड़ों को अद्यतन करने के संबंध में समन्वय करते हैं(चित्र 4.2)। जिलाधीश/कलेक्टर जिला स्तर पर आंकड़ा संग्रहण और अद्यतन की सुविधा प्रदान करने के प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। आंकड़ा संग्रहण प्रपत्रों का वितरण जिला कलेक्टर कार्यालय से संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को किया जाता है। एन आई सी के जिला सूचना अधिकारियों की तकनीकी सेवाओं को प्राप्त करके जिला स्तर पर आंकड़ों को दर्ज किया जाता है।

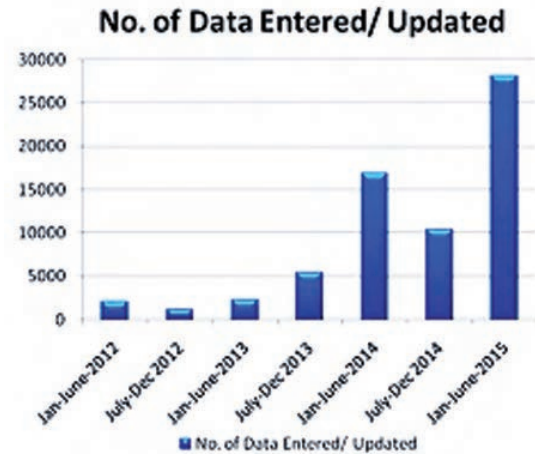


चित्र 4.2: आईडीआरएन के कार्यों को दर्शाते हुए योजनात्मक रेखाचित्र

4.1.3. 2014-15 के दौरान आईडीआरएन प्रगति

आई डी आर एन पोर्टल ने 2014-15 में तकनीकी विकास के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आंकड़ा अद्यतन करने की स्थिति के बारे में एक नई उर्जा प्राप्त की है(चित्र 4.3)। एनआईडीएम में अप्रैल, 2013 से भारतीय आपदा संसाधन तंत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाने लगा था। तब से 5 क्षेत्रीय पाठ्यक्रमों तथा 3 राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एक एक दिवसीय "राष्ट्रीय स्तर का ब्रेनस्टोर्मिंग कार्यशाला" का आयोजन आई डी आर एन पोर्टल को पुनर्संगत करने हेतु इनपुट प्राप्त करने के लिए किया गया था। आई डी आर एन ने राहत

कमिशनर के वार्षिक सम्मेलन 2014 और 2015 जैसे राष्ट्रीय स्तर के मंच में स्थान पा लिया है आई डी आर एन, एनआईडीएम के सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बन गया है।



चित्र 4.3: मार्च 2015 तक आंकड़े अद्यतन की स्थिति दर्शाता हुआ आयत चित्र

4.1.4. मुख्य उपलब्धियाँ

- आईडीआरएन पोर्टल के तिथिवार शंका उपलब्धि के लिए डाटा जानने हेतु नए पृष्ठ का सृजन किया गया ताकि सूचना प्रविष्टि/अद्यतन वाले पृष्ठ को भी देखा जा सके। डाटा तक पहुँचने के लिए दो अलग विकल्पों, पहला संसाधन के आधार पर खोज तथा दूसरा आपदा के आधार पर खोज, का सृजन किया गया। आगे, आई डी आर एन वेबसाइट के लिए प्रशिक्षण से संबंधित एक नया पृष्ठ भी विकसित किया गया।
- आईडीआरएन डाटा संग्रह के लिए एक नया फॉर्मेट बनाया गया। अपातकाल के समय पहले 72 घंटों की अवधि में आवश्यक जरूरी संसाधनों की सूची भी तैयार की गई थी जैसा कि एन डी आर एफ से संपर्क के बाद एम एच ए द्वारा सुझाव दिया गया था।
- सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ फौलो-अप कर लिया गया है तथा यूजर प्रशासन मुद्दे जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, जिला पृष्ठों का सृजन इत्यादि उत्तम संभावित स्तर तक हल कर लिया गया है। राज्यों और जिलों

से डाटा संग्रहन तथा नियमित अद्यतन के लिए राज्य प्राधिकारियों तथा जिला प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया। सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश ने आई डी आर एन में डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं। 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे— उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, पुदुचेरी, दिल्ली, केरल, सिक्किम, पंजाब और त्रिपुरा ने आईडीआरएन के सभी संबंधित जिलों के लिए संसाधनों की सूचना अपलोड/अद्यतन कर चुके हैं।

- घ) 2014-15 की अवधि में आई डी आर एन पर एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तीन राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा 104 प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त एनआईडीएम में आयोजित सभी संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आई डी आर एन के सत्रों को शामिल किया गया।
- ड) भारत आपदा संसाधन नेटवर्क(आई डी आर एन) पोर्टल का क्रात्मक डाटा, जी आई एस मानचित्र, मोबाइल कार्य इत्यादि जैसे स्टेट ऑफ आर्ट के साथ श्रेष्ठ संभावित तरीके से पुनर्संगतीकरण पर इनपुट प्राप्त करने के लिए एक एकदिवसीय “राष्ट्रीय स्तर का ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला” का आयोजन 23 सितंबर 2014 को एनआईडीएम परिसर नई दिल्ली में किया गया था। राज्य/जिला प्राधिकारियों, आर्मी, एयरफोर्स, एन डी आर एफ, दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक केन्द्र, यू एन डी पी, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के तीस कर्मचारियों ने इस एक दिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला में भाग लिया।
- च) आई डी आर एन पर एक उपयोगकर्ता मैनुवल तैयार किया जा रहा है।

4.2. भारत आपदा जानकारी नेटवर्क (आईडीकेएन)

भारत आपदा जानकारी नेटवर्क (आई डी के एन) एक वेब पोर्टल है जो संसाधनों और सेवाओं का एक विस्तृत

संग्रह जैसे— जानकारी समन्वयन, नेटवर्किंग मानचित्र, अपातकालीन संपर्क सूचना प्रणाली तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित कई अन्य जरूरी सूचना उपलब्ध कराता है (चित्र 4.4)। यह पारस्परिक प्रक्रिया द्वारा आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी साझा करने तथा एक वातावरण सृजन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।



चित्र 4.4: एसएडीकेएन के अंतर्गत आईडीकेएन पृष्ठ

4.2.1. उद्देश्य

आई डी के एन का लक्ष्य आपदा प्रबंधन जानकारी और सेवाओं तक पहुँच के लिए आसान उपयोग वाला एकीकृत केन्द्र तैयार करना है ताकि एक त्वरित तथा उन्नत गुणवत्ता प्रधान अनुक्रिया का सृजन किया जा सके। पोर्टल के मुख्य उद्देश्य हैं:

- आपदा संबंधी सूचना एवं सेवाओं का एकीकृत स्रोत उपलब्ध कराना। सूचना में विभिन्न जोखिमों की परिभाषा, इसका भौगोलिक वितरण, भारत की संवेदनशीलता (राज्य स्तर), तैयारी और न्यूनीकरण प्रक्रिया शामिल है।
- सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता सृजन करना।
- परस्पर विचार-विमर्श के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में जानने हेतु माहौल बनाने तथा जानकारी साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।

4.2.2. आईडीकेएन की वर्तमान स्थिति

भारत सरकार— यू एन डी पी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2004 में जानकारी नेटवर्क की

शुरुवात की गई। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में पोर्टल को औपचारिक रूप से एनआईडीएम को हस्तांतरित कर दिया गया। इसे क्षेत्रीय जानकारी नेटवर्क जो कि दक्षिण एशियाई आपदा जानकारी नेटवर्क (एसएडीकेएन), सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र का एक संयुक्त पहल है तथा आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है और इसकी शुरुवात मई 2011 में वैश्विक मंच पर आपदा न्यूनीकरण के लिए किया गया था, के साथ एकीकृत कर दिया गया। एन आई डी एम, एस ए डी के एन के अंतर्गत भारतीय पोर्टल के लिए आई डी के एन का केन्द्रीय बिंदु है।

अब एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन पर सूचना के सहयोग के लिए एक भारत आपदा प्रबंधन जानकारी नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। नेटवर्क वर्तमान सूचना नेटवर्कों के आधार पर सूचना और जानकारी एकत्रित करेगा और सहयोगियों से डाटा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए साझेदारी स्थापित करेगा; संग्रहित और समुचित तरीके से श्रेणीकृत सूचना की सुविधा पहचानने, विश्लेषित करने और सीखे गये पाठों को फैलाने, अच्छे अभ्यासों, तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग आपदा जोखिम के न्यूनीकरण में करेंगे। आई डी एम के एन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सूचना अंतराल को पहचानने में सहयोग करेंगे तथा हितधारकों/उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य और विशिष्ट सूचना की सुविधा तथा जानकारी सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे। आई डी एम के एन उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार तथा निर्णय लेने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जानकारी मंचों जैसे भारत आपदा जानकारी नेटवर्क, सहयोगी और विस्तृत नेटवर्क इत्यादि को एकीकृत करेंगे।

4.3. एनआईडीएम वेबसाइट का नया रूप

एनआईडीएम वेबसाइट का भारत में राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के बारे में अद्यतन सूचना के साथ नवीकरण किया गया है। (चित्र 4.5). देश के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिखाते हुए एक मानचित्र वेब पर अपलोड किया गया है, जिसमें राज्य के मानचित्र पर क्लिक कर कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य में आपदा प्रबंधन के बारे में अद्यतन सूचना

प्राप्त कर सकता है। यह सूचना चार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत आती है अर्थात् राज्य संरचना, सांस्थानिक स्थापना, आपदा जोखिम संरचना और आपदा प्रबंधन में राज्य का पहलू। इससे राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयार किये गये विभिन्न प्रकाशनों, योजनाओं तथा नीतियों, अधीनियमों इत्यादि के बारे में भी सूचना प्राप्त होती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त नया वेब आपदाओं, जिसमें आपदा के प्रकार, विचारणीय मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे सामान्य सूचनाओं के साथ उपलब्ध होते हैं।



चित्र 4.5: राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के बारे में अद्यतन सूचना दर्शाता हुआ एनआईडीएम वेबसाइट का नया रूप

4.4. एनआईडीएम ऑन-लाइन पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विश्व बैंक वाषिंगटन (जीएफडीआरआर), के साथ साझेदारी में आपदा प्रबंधन पर कई पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है(चित्र 4.6)। इन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों के अनेकों हितधारकों के विश्लेषण कौषलों तथा पेशेवर प्रतियोगिताओं के साथ साथ जागरूकता स्तर तथा तैयारी के स्तर को बढ़ाना है। एनआईडीएम ऑन-लाइन पाठ्यक्रम भारत में अपने आप में प्रथम है, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को विशय पर आधारित जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को उनके विचारों, सूचनाओं को विश्व के एक मंच पर साझा करने की सुविधा भी प्रदान

करती है। पाठ्यक्रम पेशेवर नेतृत्व के अंतर्गत आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। प्रशिक्षण सामग्रियाँ सी डी के रूप में डाक द्वारा भेजी जाती है, जिसे ऑन-लाइन पाठ्यक्रम मंच पर भी देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में वाद-विवाद, शंकाएँ, स्पष्टीकरण, गृह-कार्य और कार्यक्रम समाप्ति परियोजना शामिल होती है, जिसका मूल्यांकन अनुभवी पाठ्यक्रम प्रदाता द्वारा किया जाता है। सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है जो एनआईडीएम और विश्व बैंक (जी एफ डी आर आर) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।

यूआरएल <http://www.onlinenidm.gov.in>



चित्र 4.6: एनआईडीएम ऑन-लाइन पोर्टल का होम पेज

4.5. एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

एनआईडीएम प्रति वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। इन प्रशिक्षणों तथा प्रशिक्षुओं के संपूर्ण डाटाबेस को सरकार द्वारा इन प्रशिक्षुओं का आपदा के समय पता लगाने के लिए इसे ऑन-लाइन किया जाता है। यह सूचना वर्ष 2009 से उपलब्ध है और इसे पाठ्यक्रम के अनुसार तथा राज्य के अनुसार सजाया जा सकता है।

यूआरएल: <http://nidm.gov.in/trainee.asp>

4.6. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई एस आर ओ) के आपदा प्रबंधन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत काल्पनिक गैर सरकारी नेटवर्किंग

इसरो का आपदा प्रबंधन सहयोग कार्यक्रम (डी एम एस)

एयरो-अंतरिक्ष प्रणालियों से देश में आपदा के प्रभावी प्रबंधन की ओर समय-समय पर प्रतिबिंबित करने तथा संचार, दोनों में सहयोग और सेवाएँ उपलब्ध कराती है। डी एम एस कार्यक्रम बाढ़, चक्रवात, सूखा, जंगल की आग, भू-स्खलन और भूकंप जैसे आपदाओं को संबोधित करती है। इनमें जोखिम स्थानीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल डाटा आधार सृजन, क्षति मूल्यांकन इत्यादि, सैटेलाइट और एरियल डाटा का उपयोग कर मुख्य प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाना; निर्णय सहयोग के लिए उपयुक्त उपकरणों तथा तकनीक का निर्माण, सैटेलाइट पर आधारित विश्वसनीय तकनीकी संचार नेटवर्क की स्थापना, अपातकालीन संचार उपस्करों को भेजना और आपदा के जल्दी चेतावनी की ओर आर और डी शामिल है।

आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप के लिए अपातकालीन संचार उपलब्ध कराने की ओर, और गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेश पर, इसरो ने उपग्रह आधारित काल्पनिक निजी नेटवर्क (वीपीएन) स्थापित किया है जो एम एच ए के राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष से डी एम एस-डी एम सी के साथ एन आर एस सी पर जुड़ा है, प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी, दिल्ली के मुख्य सरकारी कर्मचारी और राज्यों के 22 बहु-जोखिम क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष भी इससे जुड़ा है। वर्ष 2006 से वी पी एन का प्रशिक्षण नोड एनआईडीएम में स्थापित किया गया है और इन सुविधाओं का उपयोग एनआरएससी, जीएसआई, आईएनसीओआई एस इत्यादि जैसे एजेंसियों से वार्तालाप के लिए किया जाता है। (चित्र 4.7).



चित्र 4.7: राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ विडियों काफेसिंग सत्र

अध्याय

5

प्रलेखन और प्रकाशन

सूचना को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहयोग करने वाला संसाधन माना जाता है। संपत्ति के रूप में सूचना का महत्त्व, इसके प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम किया जाता है। एनआईडीएम का एक अधिदेश यह है कि संस्थान का प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों के समर्थन के लिए आपदा प्रबंधन और विकास से संबंधित सूचना के प्रभावी प्रबंधन के लिए लगातार समन्वित कोशिश किया जाए। एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ हैं:

- अधिग्रहण कार्य
- संदर्भ तथा अनुमोदित कार्य
- परिचालनात्मक कार्य
- पत्रिका कार्य
- पुस्तकालय स्वचालन
- फोटोकॉपी (प्रति) कार्य

5.1 उपलब्ध सूचना स्रोत

5.1.1 पुस्तक

एनआईडीएम के पुस्तकालय का विस्तार हो रहा है। संस्थान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आपदा और विकास तथा इससे संबंधित पहलुओं पर प्रकाशित साहित्य तथा व्यवसायिक रूप से प्रकाशित साहित्य का संग्रह करने के लिए विशेष प्रयास करती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालय में कुल 1860 पुस्तकें तथा अन्य दस्तावेज प्राप्त किये गये थे (सारणी 5.1)।

सारणी 5.1 : अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक पुस्तकालय सांख्यिकी

क्र.सं.	सामग्री	कुल
1.	31-3-2015 तक कुल स्टॉक (पुस्तकें, बच्चों की पुस्तकें, पत्रिकाओं की सजिल्द प्रति, विडियो और सी डी।	2015

क्र.सं.	सामग्री	कुल
2.	वर्ष की समाप्ति के दौरान पुस्तकों का कुल आहरण	58
3.	पत्रिकाओं का अंशदान	5
4.	विनिमय आधार पर प्राप्त पत्रिकाएँ	2
5.	मुफ्त सूचना पत्र	13
6.	अंशदायी समाचार पत्रों की संख्या	10
7.	अंशदायी पत्रिकाओं की संख्या	12
8.	अंतर्पुस्तकालयी ऋण	शून्य
9.	डी इ एल एन इ टी (दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क पर अपलोड की गई पुस्तकों की संख्या	1860

5.1.2 दैनिकी

समीक्षा की गई अवधि में, एनआईडीएम ने भारतीय तथा विदेशी दोनों मिलाकर कुल 17 पत्रिकाओं और मैगजीन के लिए अंशदान किया है, जो आपदा, पर्यावरण, विकास तथा इससे संबंधित पहलुओं से संबंधित है। एनआईडीएम एक दैनिकी विनिमय तथा संपुरक आधार पर भी प्राप्त करती है तथा अलग-अलग प्रकार के लगभग नौ समाचार पत्रों के लिए अंशदान किया है।

5.1.3 सीडी रोम/विडियो कैसेट

एनआईडीएम ने ऑडियो-विडियो सामग्रियों की प्रमुखता को ई-सूचना के स्रोत के रूप में महसूस किया है तथा सी डी रोम और विडियो कैसेट का संग्रह तैयार कर रहा है। वर्तमान वर्ष में एनआईडीएम पुस्तकालय ने छः सी डी रोम अपने संग्रह में शामिल किया है।

5.2 सूचना प्रसारण

संस्थान का अधिदेश है कि आपदा एवं विकास से संबंधित सूचना का प्रसार किया जाए। अधिदेश पूरा करने के लिए यह संस्थान नियमित रूप से छमाही दैनिकी, तिमाही समाचार पत्र, अनुसंधान संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और पाठ्यक्रम मॉड्यूल, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं की सिफारिशें तथा आपदा विकास सांख्यिकी प्रकाशित

करता है। ये प्रकाशन नीति निर्माता को जमीनी हकीकत पर फिडबैक उपलब्ध कराने में मदद करती है, आपदा तथा प्रबंधन कार्यक्रमों के बेहतर योजना तथा विकास के लिए सुझाव प्रदान करती है।

5.2.1 ट्रेनिंग मॉड्यूल और पुस्तकें

तैयार किये गये मॉड्यूलों, पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

5.2.1.1 एनआईडीएम द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण मॉड्यूल

1. घटना अनुक्रिया प्रणाली पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

वर्तमान प्रशिक्षण मॉड्यूल का मौलिक उद्देश्य घटना अनुक्रिया प्रणाली को आपदा अनुक्रियावादी के बीच अर्थात् आपदा प्रबंधन दलों और प्रशासकों के बीच, प्रोत्साहित करना है। मॉड्यूल को आपदा प्रबंधन और घटना अनुक्रिया योजना में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रबंधन कौशल उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉड्यूल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ-साथ आपदा को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए विस्तृत त्वरित योजना भी प्रदान करती है। इन मॉड्यूलों का निर्माण उन आंतरिक प्रशिक्षकों तथा विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, जो घटना नियंत्रण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं तथा प्रचालन/प्रशासन संचालन में काफी अनुभव है। 2014-2015 में एनआईडीएम द्वारा घटना अनुक्रिया प्रणाली के अंतर्गत छः मॉड्यूल विकसित किये गये। घटना अनुक्रिया प्रणाली के अंतर्गत विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल इस प्रकार है:

- क) घटना अनुक्रिया प्रणाली— मौलिक तथा माध्यमिक
- ख) घटना अनुक्रिया प्रणाली— अग्रिम आईआरएस
- ग) घटना अनुक्रिया प्रणाली— क्षेत्र अधिकार
- घ) घटना अनुक्रिया प्रणाली— संपर्क अधिकारी
- ङ) घटना अनुक्रिया प्रणाली— समेकित योजना अनुभाग पाठ्यक्रम
- च) घटना अनुक्रिया प्रणाली— सुरक्षा अधिकारी



2. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) मॉड्यूल

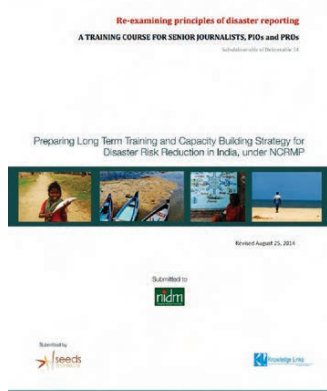
आपदा जोखिम न्यूनीकरण दीर्घकालीन विकास की कुँजी है— भारत सरकार द्वारा परिकल्पित, एन सी आर एम पी मॉड्यूल का लक्ष्य विभिन्न आपदाओं से असुरक्षा को कम करना और जनता तथा अवसंरचना की लोचता का निर्माण करना है। परियोजना का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय के संरक्षण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) तथा राज्य सरकार के

सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार (एनडीएमए) द्वारा कार्यान्वयित किया जा रहा है। इसे विश्व बैंक द्वारा फंड दिया जा रहा है।

एनसीआरएमपी का एक मुख्य भाग है, अंग 'सी' : 'आपदा जोखिम विश्लेषण के लिए तकनीकी सहायता; सामर्थ्य निर्माण; और क्षति तथा नुकसान मूल्यांकन'। इस परियोजना के अनुमानित मुख्य उपलब्धियों में एक है, प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए रणनीति संरचना और टीओटी मॉड्यूल का निर्माण।

अंग 'सी' के अंतर्गत निर्मित सात टीओटी मॉड्यूल:

- क) विकास में डी आर आर और सी सी ए को मुख्य धारा में लाने के लिए पी आर आई को मजबूत बनाना।
- ख) ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रम में डी आर और सी सी की लोचता का एकीकरण।
- ग) नगरीय विकास योजना में डी आर आर और सी सी ए को मुख्य धारा में लाना।
- घ) अस्पताल डी एम योजना को तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना।
- ड) शिक्षकों के लिए जानकारी और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा का माहौल बनाना।
- च) प्रविष्टि स्तर के पत्रकारों के लिए टी ओ टी मॉड्यूल या आपदा प्रतिवेदन की जाँच सिद्धांत।
- छ) वरिष्ठ स्तर के पत्रकारों के लिए टी ओ टी माड्युल या आपदा प्रतिवेदन के सिद्धांतों की पुनः जाँच।

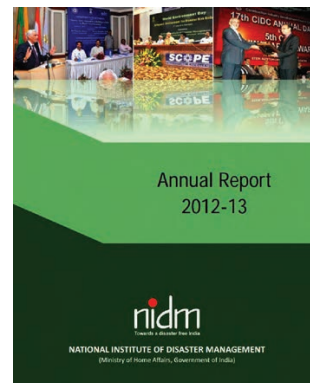


5.2.1.2 प्रकाशन

1. एनआईडीएम का वार्षिक प्रतिवेदन: 2012-2013

संकलित तथा संपादित: डॉ अनिल कुमार गुप्ता, सुश्री श्रीजा एस नायर और सुश्री स्वाति सिंह

वर्ष 2012-13 के लिए एनआईडीएम का पहला वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ। प्रतिवेदन में अवलोकन के व्यौरे, उद्देश्य, आदेश, संरचना, कार्य और संस्थान की मुख्य उपलब्धियाँ शामिल हैं। प्रतिवेदन की संरचना



आठ अध्यायों में की गई है, जैसे— परिचय, प्रशिक्षण परियोजना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहल, प्रलेखन और प्रकाशन, आउटरीच क्रियाकलाप, प्रशासन, वित्त और लेखा; सूचीबद्ध किये गये क्रियाकलाप और प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षणों की संख्या, प्रशिक्षण के प्रकार इत्यादि के रूप में प्राप्त प्रगति के अतिरिक्त। उपलब्धि की भौगोलिक, वर्गीकृत और अस्थायी रीति को दर्शाने के लिए मानचित्रों, चार्टों, तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। एनआईडीएम में तथा परिसर से बाहर आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और डीएमसी, शासित इकाई के सदस्यों की सूची और एनआईडीएम को दिखाने के लिए पाँच संलग्नक हैं।

2. पुस्तक : जंगल आग आपदा प्रबंधन

लेखक: डॉ. सतेंद्र और डॉ. ए डी कौशिक

इस पुस्तक में सात अध्याय हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंगलों, जंगल की आग तथा इसके प्रभावों, जंगल आग प्रबंधन रणनीतियों तथा

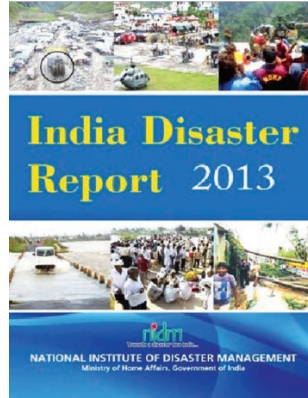
इससे संबंधित मुद्दों इत्यादि से सुसज्जित है। जंगल आग पर एक अद्यतन और व्याख्यायित ग्रंथ-सूची भी इस पुस्तक में दिया गया है, जो प्रशिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं और वनचरों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी हो सकता है।



3. भारत आपदा प्रतिवेदन 2013

संपादक: डॉ. सत्येन्द्र, डॉ. के जे आनंद कुमार और मेजर जनरल डॉ. वी के नायक

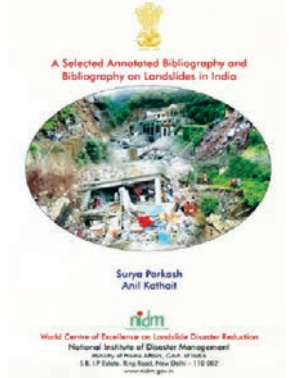
भारत आपदा प्रतिवेदन 2013 उत्तराखंड के तत्कालीन बाढ़ तथा फाइलिन चक्रवात को केन्द्र में रखते हुए उस वर्ष के मुख्य आपदाओं को प्रलेखित करता है। जैविक आपदा (जापान का जैविक आपदा) के अतिरिक्त अन्य आपदाओं जैसे— मकान का ध्वस्त हो जाना, भगदड़ को भी शामिल किया गया है। इन आपदाओं से सीखे गये पाठ ने हमें आपदा प्रबंधन के लिए आगे अपने पहुँच को और परिशुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है ताकि को आपदा रहित बनाने का हमारा लक्ष्य सफल हो सकें। वर्ष के दौरान घटित आपदाओं की समीक्षा से शाश्वत विकास की आवश्यकता के लिए प्रेरित करता है तथा सभी विकासात्मक क्रियाकलापों में आपदा जोखिम के न्युनीकरण को मुख्य धारा में लाने की प्रमुखता को सही ठहराता है।



4. भारत में भू-स्खलन पर चयनित एक विवेचित ग्रंथ-सूची और ग्रंथ-सूची

लेखक: डॉ. सूर्य प्रकाश और श्री अनिल कठैत

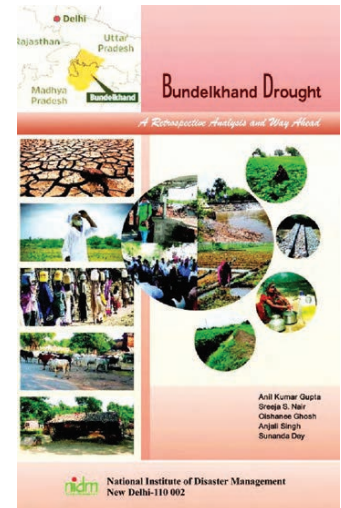
प्रलेख को प्रकाशन की सूची के स्रोत के रूप में उनके लिए तैयार किया गया है जो भूस्खलन अध्ययन, अनुसंधान और प्रबंधन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। यह भारत के भू-स्खलन पर किये गये देश के तथा देश से बाहर के अलग-अलग संगठनों तथा विशेषज्ञों द्वारा किये गये उपलब्ध साहित्य और अनुसंधान कार्य का संग्रह है। प्रलेख में अमरीकी मनोवैज्ञानिक उद्धरण(ए पी ए) शैली को अपनाया गया है जो अनुसंधान कार्य के संग्रहण के लिए उपयुक्त उद्धरण विधियों में एक है।



5. बुंदेलखंड सूखा: सिंहावलोकित विश्लेषण और उससे आगे

लेखक : डॉ.अनिल कुमार गुप्ता, सुश्री श्रीजा एस नायर, सुश्री ओसाने घोश, सुश्री अंजलि सिंह और सुश्री सुनंदा डे

एनआईडीएम ने भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद (आई सी एस एस आर) के वित्तीय सहायता से भविष्य की रणनीति में सुझाव देने के लिए बुंदेलखंड में सूखे की पद्धति तथा उसके न्यूनीकरण रणनीति की विभिन्न भूमिका को समझने के लिए एक अनुसंधान कार्य किया



है। यह पुस्तक परियोजना की उपलब्धियों में एक है। बुंदेलखंड के संदर्भ में सूखे की घटना में कई मोड़, उसका प्रभाव तथा न्यूनीकरण के तरीकों को इस पुस्तक में रखा गया है।

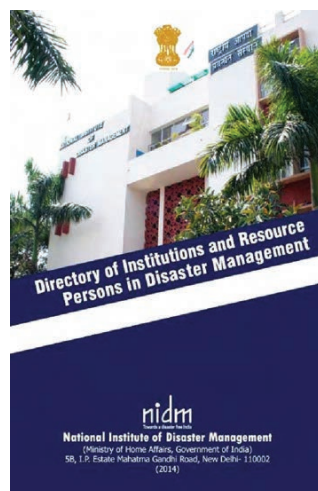
पुस्तक भू-सांख्यिकीय डाटा पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन, उपकरण तथा पद्धतियों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण का मिश्रण है जो छः आध्यायों में संकलित है। मौसम विज्ञान, जल विज्ञान तथा कृषि से संबंधित सूखा ने सामाजिक-पर्यावरणीय तथा उन्नत कार्यक्रम को सूखा न्यूनीकरण मूल्य से मूल्यांकित करने के लिए अनुसंधान परियोजना के विचार को आकर्षित किया जो असुरक्षा को परिवर्तित करता है और न्यूनीकरण उपायों के विभिन्न प्रभावों का कारण भी बनता है।

5.2.1.3 सूची

1. आपदा प्रबंधन में संस्थानों और संसाधन व्यक्तियों की सूची

संकलित तथा संपादित: डॉ सत्येंद्र, डॉ ए डी कौशिक, श्री आर पी शर्मा तथा सुश्री मेघा कोहली

दसवीं पंचवर्षीय योजना में जानकारी साझा करने, सूचना फैलाने और जन जागरूकता पहलुओं पर आधारित एक मजबूत तथा सटीक डाटाबेस का निर्माण के लिए कुछ प्रमुख प्राचाल(पैरामीटर) का सुझाव दिया गया। स्टेट ऑफ आर्ट सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग और



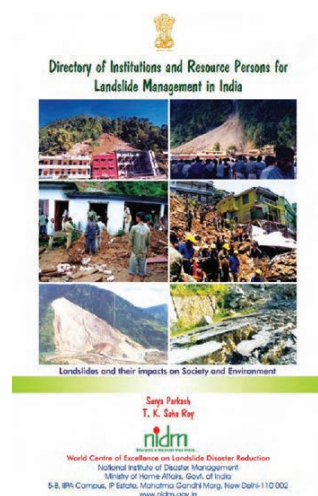
सभी जानकारी आधारित संस्थानों से संपर्क स्थापित कर इसे राष्ट्रीय आपदा जानकारी के काम में लाना, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जानकारी साझा करने और सूचना प्रसारण के प्रभावी रूपों को दर्शाता है। इस संदर्भ में एनआईडीएम ने सभी जानकारी आधारित संस्थानों और संसाधन व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार करने तथा उन्हें इस आदेश को उपलब्ध कराने के लिए, अपने अनुभवों तथा क्रियाकलापों को साझा करने के लिए

मंच उपलब्ध कराने का दायित्व लिया है। वर्तमान प्रलेख संसाधन आधार तैयार करने का एक प्रयास है, जिसे जानकारी आधारित संस्थानों के अतिरिक्त सभी संभावित उपयोगकर्ता द्वारा अपने कौशल, उपलब्धियों, और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जानकारी को साझा करने के लिए विस्तृत रूप से उपयोग किया जा सकता है। प्रलेख की साँपट प्रति www.nidm.gov.in पर उपलब्ध है।

2. भारत में भू-स्खलन प्रबंधन के लिए संस्थानों और संसाधन व्यक्तियों की सूची

संकलित तथा संपादित: डॉ सूर्य प्रकाश और श्री टी के साहा रॉय

आपदा काल में जीवन, जीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सूचना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उपयुक्त संपर्क संख्या तथा अन्य संगत सूचना के साथ एक डायरेक्टरी किसी देश की आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अति



उपयोगी होता है। यह प्रलेख एक संसाधन के विकास का प्रयास है, जिसे जानकारी आधारित संस्थानों के होते हुए भी भू-स्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में अपना विशेषज्ञता, उपलब्धि, और जानकारी अन्य हितधारकों से साथ साझा करना है उन सभी संभावित उपयोगकर्ता द्वारा विस्तृत रूप से उपयोग किया जा सकता है।

प्रलेख विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से संकलित की गई है। इसमें कई संस्थानों, विभागों, संगठनों, भू-स्खलन प्रबंधन का कार्य करने वाले संसाधन व्यक्तियों के साथ वेबसाइट के पते इत्यादि संपर्क व्यौरे संकलित है।

5.2.1.4 जागरूकता सामग्री

1. 12 सामान्य आपदाओं के लिए हिंदी में, क्या करें और क्या नहीं करें?

एनआईडीएम ने 12 आपदाओं के लिए हिंदी में, क्या करें और क्या नहीं करें जारी की है। इन आपदाओं में शामिल हैं: भूकंप, बाढ़, चक्रवात, आग, भू-स्खलन, सूखा, सुनामी, लू-तरंग, शीत लहर, महामारी, गरज और लाइटनिंग, और जंगल की आग। इसमें भारत में आपदा की स्थिति और आपदा प्रबंधन संरचना के बारे में भी संक्षिप्त रूप से लिखा है।

2. "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण की रक्षा करना" विषय पर छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता

एनआईडीएम ने पर्यावरण दिवस (4 जून 2014) के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य "पर्यावरण को आपदा जोखिम न्यूनीकरण" हेतु छात्रों के साथ-साथ समाज के अन्य भागों में जागरूकता पैदा करना था (चित्र 5.1)। एनआईडीएम ने "आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा" संदर्भ पर एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की। प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियाँ थी: (1) कक्षा 8वीं से 10वीं (हिंदी); (2) कक्षा 8वीं से 10वीं (अंग्रेजी); (3) कक्षा 11वीं और 12वीं (हिंदी); और (4) कक्षा 11वीं और 12वीं (अंग्रेजी)। कुल 1500 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिसमें दृष्टिहीन छात्रों की प्रविष्टि भी शामिल थी। स्कोप ऑडिटोरियम दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 4 जून 2014 को विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया गया।



चित्र 5.1: जागरूकता कार्यक्रम से एक ग्रुप फोटो

5.2.2 समाचारपत्र

एनआईडीएम का समाचारपत्र "टाइडिंग्स" तिमाही प्रकाशित होती है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के प्रतिवेदनों को प्रकाश में लाती है, जो एनआईडीएम द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। अगले तीन महीनों के लिए प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अग्रिम प्रचार के अतिरिक्त, समाचारपत्र विभाग के विकास, सफल कहानियों, दौरे और प्रतिनिधि मंडलों इत्यादि समाचारपत्र में शामिल किये जाते हैं। इस माध्यम के द्वारा एनआईडीएम राज्य ए टी आई, अकादमिक संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों से नियमित संपर्क बनाये रखते हैं। वर्ष 2004 में एनआईडीएम द्वारा प्रथम समाचारपत्र जारी किये जाने से आज की तिथि तक 43 प्रति प्रकाशित की जा चुकी है। इस वर्ष अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक समाचारपत्र की चार प्रतियाँ जारी की गई हैं।



5.2.3 दैनिकी

संस्थान एक द्विवार्षिक दैनिकी प्रकाशित करती है जिसका शीर्षक है आपदा और विकास"। दैनिकी की प्रथम प्रति का शुभारंभ 29 नवंबर 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारत आपदा प्रबंधन काँग्रेस के उद्घाटन समारोह में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री डॉ



मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। तब से यह दैनिकी एनआईडीएम का अग्रणी

अकादमिक प्रकाशन है। दैनिकी की दस प्रतियाँ, जिसमें भारत के साथ-साथ अन्य देशों के आपदा प्रबंधन पर विभिन्न पहलुओं का वर्णन है, एनआईडीएम द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।

5.2.4 मासिक अद्यतन

एनआईडीएम हाल के क्रियाकलापों जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं, सेमिनारों, क्षेत्र दौरों और अन्य सभी नियमित क्रियाकलापों शामिल रहते हैं, को मासिक स्तर पर अद्यतन करते रहते हैं। अगले महीने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अग्रिम प्रचार करने के अतिरिक्त, मासिक अद्यतन में विभाग के विकास, सफलता कहानी, दौरे और प्रतिनिधि मंडल इत्यादि शामिल होते हैं। इस माध्यम के द्वारा एनआईडीएम राज्य ए टी आई, अकादमिक संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों से नियमित संपर्क रखती है। इस कार्य की शुरुवात अक्टूबर 2013 में की गई। वर्ष 2014-2015 की अवधि में एनआईडीएम ने कुल बारह मासिक अद्यतन किया। ये वेबसाइट पर नियमित अद्यतन हैं, जिसे <http://nidm.gov.in/mupdate.asp> से डाउनलोड किया जा सकता है।



5.3 सूचना शिक्षा और संचार (आईसी) सामग्रियाँ

संस्थान को आपदा और तैयारी पर सूचना प्रसारण का आदेश है। आदेश को पूर करने में, संस्थान नियमित रूप से एक द्विभाषी दैनिकी, एक तिमाही समाचारपत्र, अनुसंधान की उपलब्धियाँ, पाठ्यक्रम मॉड्यूल, सेमिनारों और कार्यशालाओं का प्रतिवेदन, आपदा तैयारी सांख्यिकी तथा विभिन्न सूचना और शिक्षा सामग्रियाँ प्रकाशित करती है। प्रकाशन नीति निर्माताओं को वास्तविकता का फिड बैक प्रदान करने, बेहतर योजना बनाने में

सुझाव और दिशा-निर्देश देने तथा आपदा और विकास कार्यक्रम के प्रबंधन में मदद करती है। विभिन्न आपदाओं और उसके प्रबंधन पर सूचना और जागरूकता सृजन करने के लिए, एनआईडीएम नियमित रूप से आई ई सी सामग्रियों के साथ साथ विभिन्न जागरूकता सृजन क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को प्रकाशित करती है। ये उपकरण एनआईडीएम के वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे <http://nidm.gov.in/iec.asp> पर देखा जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा तैयार किये गये आई ई सी सामग्रियों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हितधारकों द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है और इसके विस्तृत प्रसारण के लिए इसे अलग-अलग भाषाओं में अनुदित किया जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा तैयार किये गये जागरूकता सामग्रियों का व्यौरा नीचे दिया गया है:

5.3.1 विज्ञप्तियाँ

1. एनआईडीएम विज्ञप्ति (हिंदी में)

पैम्पलेट में संस्थान के बारे में संक्षिप्त सूचना, इसका प्रबंधन ढाँचा, लक्ष्य एवं संस्थान का मिशन, कार्य, प्रशिक्षण के प्रकार तथा



एनआईडीएम की अन्य विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सूचना शामिल है। विज्ञप्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

2. लू तरंग-सुरक्षा के तरीके (अंग्रेजी और हिंदी में)

पैम्पलेट में लू तरंगों के दौरान क्या करें और क्या न करें जैसे सुरक्षा उपाय शामिल है। विज्ञप्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चित्र के साथ उपलब्ध है। इसे समय-समय पर एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न



जागरूकता अभियानों में प्रचारित किया जाता है तथा कभी-कभी देशी भाषा में प्रकाशित समाचारपत्रों में भी प्रचारित किया जाता है।

3. शीतलहर (सुरक्षा उपाय)

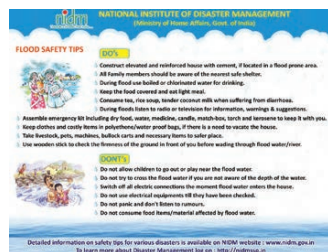
पैम्पलेट में शीतलहर की स्थिति में क्या करें और क्या न करें के बारे में सुरक्षा सझाव शामिल है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सचित्र उपलब्ध है। समय- समय पर एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न चेतना अभियान के दौरान तथा कभी-कभी प्रकाशित होने वाली देशी भाषाओं के समाचारपत्रों में भी इसका प्रचार किया जाता है।

4. अग्नि सुरक्षा के तरीके

विज्ञप्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा अग्नि संकट की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए सचित्र सूचना उपलब्ध है। एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में समय-समय पर तथा कभी-कभी स्थानीय समाचारपत्रों में भी प्रचारित किया जाता है।

5. बाढ़ से सुरक्षा के तरीके

विज्ञप्ति में बाढ़ की स्थिति में क्या करें और क्या न करें जैसे अनेक सुरक्षा उपायों के बारे में सचित्र बताया गया है। यह विस्तृत प्रचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में समय-समय पर तथा कभी-कभी स्थानीय समाचारपत्रों में भी प्रचारित किया जाता है।



6. भूकंप से सुरक्षा के तरीके 1 और 2

विज्ञप्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है तथा भूकंप की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए सचित्र सूचना उपलब्ध है।



विज्ञप्ति विस्तृत विवरण के लिए दो भागों में उपलब्ध है- आपदा से पहले, आपदा की स्थिति में और आपदा के बाद। एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में समय-समय पर तथा कभी-कभी स्थानीय समाचारपत्रों में भी प्रचारित किया जाता है। यह विज्ञप्ति मुख्य रूप से स्कूल सुरक्षा के लिए है और विभिन्न स्कूलों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किया जाता है।

7. इ-लर्निंग स्व-अध्ययन कार्यक्रम पर विज्ञप्ति

एनआईडीएम आपदा प्रबंधन पर सामान्य जनता तथा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों को जिसकी भूमिका



और दायित्व आपदा प्रबंधन में है, को इ-लर्निंग स्व-अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन में इ-लर्निंग स्व-अध्ययन कार्यक्रम का लक्ष्य आपदा प्रबंधन में रुचि पैदा करना तथा जानकारी, कौशल और जागरूकता के स्तर को बढ़ाना है। आपदा प्रबंधन पर इ-लर्निंग स्व-अध्ययन कार्यक्रम का मुफ्त में विश्व में किसी के द्वारा कहीं से भी अपने मनचाहे समय पर लाभ उठाया जा सकता है।

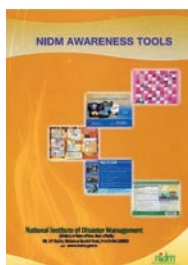
8. स्कूल में अग्नि सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें

स्कूल में अग्नि संकट की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं करें के चित्र सहित व्योरे को हिंदी भाषा में पैम्पलेट द्वारा दिखाया गया है। इसे एनआईडीएम द्वारा समय-समय पर आयोजित जागरूकता अभियान में प्रसारित किया जाता है तथा स्थानीय समाचारपत्रों में भी कभी-कभी प्रकाशित की जाती है।



9. एनआईडीएम जागरूकता उपकरण

विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन के बारे में सूचना तथा जागरूकता पैदा करने के लिए एन आई डी एम द्वारा तैयार किये गये विभिन्न उपकरणों को दिखाता हुआ एक दोतरफा पैम्पलेट।



10. एनआईडीएम के हाल ही के प्रकाशन

एक दोतरफा पैम्पलेट, एनआईडीएम द्वारा हाल ही में किये गये प्रकाशनों की सूचना को दिखाते हुए, जैसे- प्रकाशन शीर्षक, लेखक, प्रकाशन के वर्ष, संक्षिप्त सारांश इत्यादि।



5.3.2 डॉक्युमेंटरी

डॉक्युमेंटरी फिल्म जागरूकता सृजन का सबसे प्रमुख माध्यम है, जो अनेक हितधारकों में परिवर्तन लाता है। एनआईडीएम ने विभिन्न आपदाओं तथा संगत कार्यशालाओं पर डॉक्युमेंटरी फिल्म बनाया है। इन डॉक्युमेंटरी को विस्तृत प्रसारण के लिए यू-ट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। हाल ही के कुछ डॉक्युमेंटरी का वर्णन नीचे किया गया है:

1. एनआईडीएम डॉक्युमेंटरी

यह डॉक्युमेंटरी एनआईडीएम के बारे में है जो संस्थान

की उत्पत्ति, इसके लक्ष्य, मिशन, कार्यों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका को दिखाता है। संस्थान की ओर से आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण



तथा सामर्थ्य निर्माण को सुसाध्य बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के कार्यकालीन सुविधाओं जैसे- वर्ग कक्ष, सेमिनार हॉल, एक जी आई एस प्रयोगशाला तथा विडियो कॉफ्रसिंग सुविधाएँ इत्यादि पर विशेष बल देती है। संस्थान में एक अच्छी पुस्तकालय है जिसमें आपदा प्रबंधन तथा न्यूनीकरण विषय पर अलग से पुस्तकों का भंडार है। इस डॉक्युमेंटरी में भिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों जैसे- प्रत्यक्ष, ऑनलाइन, तथा स्व अध्ययन तरीके एवं उपग्रह आधारित प्रशिक्षण लिये गये हैं। इस फिल्म में एनआईडीएम द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं, आयोजित कार्यशालाओं तथा सेमिनारों और विभिन्न चेतना जागरूकता गतिविधियों पर भी विशेष बल दिया गया है।

2. भूकंप की तैयारी के लिए गृह मालिकों के लिए सामग्री

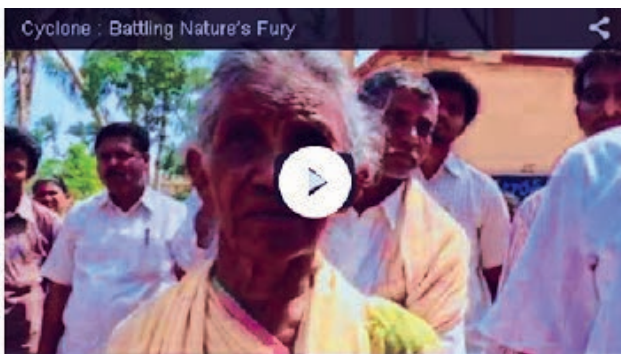
यह डॉक्युमेंटरी भूकंप, इसके विभिन्न संरचनात्मक प्रणालियों, भूकंप के प्रभावों, भूकंप से पहले, इसके वक्त तथा इसके बाद क्या करें और क्या न करें, इत्यादि के बारे में विस्तृत सूचना को सामने लाती है। यह गृह स्वामियों के लिए एक तैयार अनुदर्शक है जो एक संदर्भ उपकरण के रूप में नागरिकों को भूकंप के तैयारी मिशन हेतु तैयार करने के लिए सेवा करता है। फिल्म देश के विभिन्न भूकंप क्षेत्रों को निर्देशित करती है, जो भूत के भूकंपों से क्षति और आवृत्ति की



तीव्रता को बताता है जो देश द्वारा भूत में सहा जा चुका है। फिल्म तैयारियों और न्यूनीकरण तरीकों पर बल देती है जिसे न सिर्फ असुरक्षित लोगों के जीवन को बचाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, बल्कि आपदाओं पर समुचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए और प्रभावी अनुक्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। प्रारंभिक स्थल पर अल्प उपाय भी आपदाओं को कम कर सकता है और अरबों जिंदगी को बचा सकता है।

3. चक्रवात: प्रकृति के क्रोध से लड़ाई

देश का तटीय क्षेत्र प्रतिवर्ष भयानक चक्रवात का गवाह बनता है, जिससे कई मानव जीवन तथा भारी मात्रा में संपत्ति का नुकसान होता है। यह डॉक्युमेंटरी हाल ही में तटिय राज्यों के चक्रवातों (फाइलिन और हुदहुद) के परिणामों को विवेचित करती है। फिल्म में चक्रवातों के विरुद्ध भारत के कौशल को भी दिखाया गया है। डॉक्युमेंटरी में चक्रवात के लिए प्रभावी तैयारी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और एनआईडीएम के योगदान को भी दर्शाया गया है।



4. स्कूल सुरक्षा

बच्चे देश और समाज का भविष्य है। किसी आपदाकालीन परिस्थिति में बच्चे खतरे के सबसे संभावित समूहों में होते हैं। यह डॉक्युमेंटरी आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा की महत्ता को देखती है। यह स्कूल आपदा प्रबंधन योजना के आवश्यक जरूरतों और प्रत्येक स्कूल में आपदा पर अभ्यास ड्रिल पर बल देता है। फिल्म में राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा दिशा-निर्देशों का भी वर्णन किया गया है।



5.4 योजनाओं हेतु निवेश

5.4.1 आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना (एनडीएमपी)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानी स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारी का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2009) में उल्लेखानुसार आपदा प्रबंधन योजनाओं में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं, रोकथामों एवं न्यूनीकरण, आपातकालीन अनुक्रिया तथा मानव संसाधन सामर्थ्य निर्माण



के लिए खतरा, जोखिम तथा घातकता असुरक्षा को शामिल करना है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति(एन डी सी), जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव द्वारा की जाती है का दायित्व है कि वह सभी संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों या एजेंसियों से सहयोग लेकर भागीदारी तरीके से राष्ट्रीय योजना तैयार करें और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। वर्ष 2013 के उत्तराखंड आपदा के बाद केन्द्रीय सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने का निर्णय किया था। डॉ अनिल कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवं नीति योजना विभाग के अध्यक्ष और श्रीमति श्रीजा एस नायर, सहायक प्रोफेसर को एन डी सी ने योजना प्रलेख विकसित करने के लिए लगाया है। इन्हें संयुक्त सचिव(डी एम) तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के आपदा प्रबंधन हेतु नॉडल अधिकारियों तथा गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रभाग, ई डी एनआईडीएम इत्यादि अधिकारियों के साथ समन्वय करके इस कार्य को करना है। योजना में शामिल है: (क) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण योजना; (ख) आपदा अनुक्रिय योजना, और (ग) मानव संसाधन सामर्थ्य विकास योजना। राष्ट्रीय आपदा का अंतिम प्रारूप प्रलेख श्री अनिल गोस्वामी, गृह सचिव की अध्यक्षता में अक्टूबर 2013 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय आपदा कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया तथा एन डी एम ए को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। योजना देश में सभी स्तरों पर विभिन्न तरीकों और कार्यक्रमों एवं विकास के सभी क्षेत्रों से परे डी आर आर को मुख्य धारा में लाने के दृष्टिकोण पर बल देती है। अपातकालीन अनुक्रिया योजना में आपदाओं के दौरान बचाव, राहतों और तैयारी के लिए समन्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों, विभागों, मंत्रालयों तथा संगठनों की भूमिकाएँ तथा उत्तरदायित्वों सहित इनके दखल को ध्यान में रखा गया तथा योजना प्रलेख सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के बीच परिचालित

किया गया था तथा टिप्पणियों व निदेशों को अंतिम प्रलेख में शामिल किया गया था। राज्य सरकार के सुझावों पर आपदा पश्च पुनर्प्राप्ति ढाँचा विशयक घटक को भी शामिल किया गया था।

5.4.2 एनआईडीएम के सुदृढीकरण और प्रसारण हेतु सापेक्षिक योजना (2014-18)

देश में आपदा प्रबंधन तथा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सामर्थ्य निर्माण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यवाहियों हेतु बढ़ती आवश्यकता तथा माँग को देखते हुए राष्ट्रीय



आपदा प्रबंधन संस्थान को सुदृढ करने के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एनआईडीएम की प्रथम आम बैठक के दौरान विशेष बल दिया गया है जिसमें आगामी पाँच वर्षों के अंदर एनआईडीएम तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इसे सुदृढ करने तथा विस्तृत करने के लिए सापेक्ष योजना तैयार करने का निदेश दिया गया। तकनीकी सलाहकार समिति, एनआईडीएम के समन्वयक, डॉ अनिल कुमार गुप्ता, नीति नियोजन एवं प्रशिक्षण विभागाध्यक्ष को एनआईडीएम की सापेक्ष योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया। प्रारूप योजना इस संबंध में राष्ट्रीय मानव संसाधन योजना 2012, और एन डी एम ए की अन्य राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों, राष्ट्रीय नीतियों, विश्वविद्यालय और अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों, केन्द्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षणों तथा देश में विभिन्न स्तरों पर संस्थागत संरचना के दिशा-निर्देशों पर नीति

अनुसंधान के आधार पर तैयार की गई है। प्रारूप योजना समीक्षा तथा टिप्पणी हेतु सभी महत्वपूर्ण हितधारकों में परिचालित की गई है और एनआईडीएम की सापेक्ष योजना के बारे में चर्चा करने तथा निर्णयों को अंतिम रूप देने के लिए 17 जनवरी 2014 को एनआईडीएम के अंदर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है। परामर्श कार्यशाला के सत्र के दौरान एनआईडीएम की टी ए सी के अध्यक्ष डॉ हर्ष कुमार गुप्ता, एन डी एम ए के माननीय सदस्य डॉ मुजफ्फर अहमद ने अध्यक्षता की। विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, संगठनों, संस्थानों, यू एन एजेंसियों एत्यादि के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और योजना में दिये गये प्रावधानों को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। 2014-18 के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाले तीन चरणों जैसे तत्काल (एनआईडीएम संकाय का पुनर्गठन), अल्पकालीन (संकाय की जीविका प्रगति तथा पदों का सृजन और क्रियाकलापों का विस्तार), तथा मध्य दीर्घकालीन (रिक्तियों का भरा जाना, नये केन्द्र की स्थापना और क्रियाकलापों तथा सांस्थानिक नेटवर्क का विस्तार)।

5.5 क्षेत्र दौरे और प्रलेखन

5.5.1 एनसीआरएमपी-पीडीएनए परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा क्षेत्र का दौरा, 1 से 3 अप्रैल, 2014

भारत के लिए पीडीएनए अध्ययन के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना(एनसीआरएमपी) के परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईई) से ए डी ए सी दल के नेता श्री रोबर्टो जोवेल और सुश्री प्रियंका चौधरी ने राज्य में आपदा आवश्यकता मूल्यांकन के लिए वर्तमान अभ्यास के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए तथा

राज्य के क्रियाकलाप पर सांख्यिकीय सूचना इकट्ठा करने के लिए उड़ीसा राज्य का दौरा 1 से 3 अप्रैल 2014 तक किया ताकि इसका उपयोग भविष्य के संभावित आपदा पश्च आवश्यक मूल्यांकन में आधार रेखा के लिए किया जा सके।

भुवनेश्वर दौरा के दौरान उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का कार्यालय (ओएसडीएमए), उत्पाद विभाग और अन्य आपदा संबंधित क्षेत्रीय और सहायक संस्थानों का दौरा किया गया तथा वर्तमान आपदा प्रभाव मूल्यांकन, वापसी और पुनर्निर्माण क्रियाकलापों को जानने के लिए चर्चा किया गया।

5.5.2 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, (एनसीआरएमपी)जुलाई 2014 के अंतर्गत 'भारत में आपदा पश्च आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन' के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संपर्क

आपदा पश्च आवश्यकता मूल्यांकन(पीडीएनए) अध्ययन देश में आपदा पश्च वापसी तंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ भारत के लिए संगत मानकीकृत पीडीएनए उपकरण का निर्माण किया जाएगा। विभिन्न राज्यों के राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के परामर्शदाता से आपदा पश्च आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के लिए एन सी आर एम पी दल (इसमें विश्व बैंक के प्रतिनिधि और ओ एनआईडीएम शामिल) का दौरा की योजना बनाई गई है और अध्ययन अवधि के दौरान इस अध्ययन के अंतर्गत दस राज्यों में अध्ययन किया जाएगा। जुलाई 2014 महीने के दौरान अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित राज्यों का दौरा किया गया:

1. तमिलनाडु क्षेत्र दौरा, 3 से 5 जुलाई 2014

परामर्शदाता दल, एनआईडीएम के प्रतिनिधि के साथ राज्य में वर्तमान आपदा पश्च आवश्यक मूल्यांकन

को समझने के लिए 3 से 5 जुलाई 2014 के बीच तमिलनाडु राज्य का दौरा किया। दल में श्री एनेमुवल सी, टोरेटे तथा ट्रेनिंग, सामर्थ्य निर्माण तथा मूल्यांकन विशेषज्ञ, ए डी पी सी; श्री तारिक सोहैल, कार्यालय समन्वयक ए डी पी सी; और श्री प्रियंक जिंदल, विशेषज्ञ, एनआईडीएम ने दौरे के दौरान निम्नलिखित बैठक और चर्चा किया:

(क) दल ने 3.7.2014 को अतिरिक्त मुख्य सचिव/ उत्पाद प्रशासन आयुक्त के साथ बैठक किया तथा राज्य स्तर के सभी मुख्य विभागों से विचार विमर्श किया जिसमें राज्य योजना आयोग के कर्मचारी शामिल थे जहाँ कर्मचारियों ने अपने आपदा पश्च अनुभवों तथा पी डी एन ए के इनपुट को साझा किया।

(ख) जिला कलेक्टर, कुडालोर के साथ एक मितिग 4.7.2014 को हुई, और दल जिला, ब्लॉक, गाँव, गैर सरकारी संगठनों और किसानों के साथ-साथ सरकारी संगठनों और जिला जनसांख्यिकीय कार्यालय स्तर के कर्मचारियों से मिला। कर्मचारियों ने 2012 के चक्रवात 'थाने' और 2004 के सुनामी के अनुभवों को भी साझा किया।

(ग) मछुवारा समुदाय और अन्य के साथ, स्व-मदद समूह के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, और स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन विभाग के गाँव स्तर के कर्मचारियों इत्यादि से थाजांगुडु गाँव में भी चर्चा हुई थी (चित्र 52)।

दौरे ने दल को आपदा पश्च आवश्यकताओं का वर्तमान में अनुसरण करने वाले प्रक्रिया तथा समुदायों से संबंधित अन्य मुद्दे को समझने में मदद की। तमिलनाडु दौरा का अनुभव अन्य राज्यों में भी पी डी एन ए की वर्तमान प्रणाली को समझने में उपयोगी होगी।



चित्र 5.3: मछुवारा समुदायों और परामर्श दल के बीच चर्चा

2. महाराष्ट्र क्षेत्र दौरा जुलाई 9 - 11, 2014

परामर्शदाता दल, एनआईडीएम के प्रतिनिधि के साथ आपदा पश्च वर्तमान आवश्यकता मूल्यांकन, उनके अनुभव तथा उस क्षेत्र के प्रति सजगता को समझने के लिए महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया, जो अध्ययन के लिए चुने गये दस प्रतिनिधि राज्यों में एक है। दल में सुश्री प्रियंका चौधरी, विशेषज्ञ, एन आई डी एम; सुश्री थिटिपोन सिसुपन, पर्यावरण विशेषज्ञ और ए डी पी सी से डॉ सुनील परासर थे, इन्होंने कई हितधारकों से विभिन्न स्तर पर मुंबई और औरंगाबाद में 9 स 11 जुलाई, 2014 में बातचीत की (चित्र 5.3)।



चित्र 5.3: परामर्श दल हितधारकों से बातचीत करते हुए

दल ने राज्य स्तर पर पी डी एन ए प्रक्रिया में शामिल विभिन्न विभागों के मुख्य कर्मचारियों तथा टी आई एस एस के विशेषज्ञों से आपदाओं के बाद मनोसामाजिक

आवश्यकताओं पर बैठक किया था। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी, निचले स्तर के कार्यकर्ता तथा कार्य में शामिल विभागों के प्रतिनिधियों से इस स्तर पर प्रक्रिया, मुद्दे और चुनौतियों को समझने के लिए तथा परिनिष्ठ विस्तृत और सही पी डी एन ए हेतु सुझाव के लिए संपर्क किया गया।

3. पश्चिम बंगाल क्षेत्र दौरा-जुलाई 21-22, 2014

एनआईडीएम के प्रतिनिधि के साथ परामर्शदाता दल आपदा के पश्चात क्षति के विभिन्न सामर्थ्य और आवश्यकताओं के आकलन के साथ संबंध रखने वाले हितधारकों से मिले (चित्र 5.4). इस दल में एडी पी सी से श्री एमानुएल टोरेण्टो; एनआईडीएम विशेषज्ञ सुश्री प्रयंका चौधरी; एनआईडीएम सहायक कार्यपालिका सुश्री रानी ढाकड़ शामिल थे। दल ने अपने पश्चिम बंगाल में ठहराव के दौरान कलकत्ता और हुगली में परामर्श किया।



चित्र 5.4: दौरे में हितधारकों और परामर्शदाताओं के बीच बातचीत

दल राज्य स्तर के आपदा प्रबंधन के मुख्य कर्मचारियों से मिला और किसी प्रकार के आपदा पश्च मुल्यांकन में तथा ऐसे कार्य में संबंधित विभाग के कार्य में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास किया। इसके बाद कृषि विभाग, सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि से मिला गया। इन्होंने प्रक्रिया से

संबंधित क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन का अपने जानकारी को साझा किया। हुगली में संगत विभागों के जिला और ब्लॉक के सभी प्रमुख हितधारकों के साथ उनके वर्तमान क्षति और आवश्यकता विधि के मूल्यांकन पर तथा आपदा के पश्चात यह प्रक्रिया कब तक जारी रखना चाहिए, इसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करने के लिए बैठक बुलाई गई। यहाँ मुख्य मुद्दा था— आपदा के बाद वापसी तथा पुनर्संगठन क्रियाकलापों का लंबे समय तक जारी रखना, जैसे प्राकृतिक निकासी प्रणाली को फीर से बनाना या संरचना का पुनर्संगठन, विशेषकर डी आर आर उपायों के दौरान। पश्चिम बंगाल में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और लंबी अवधि की वापसी तथा पुनर्संगठन की आवश्यकता ऐसे क्षेत्र में अवश्य रहती है, जिससे कि वर्तमान क्षति के न्यूनीकरण के लिए इन क्रियाकलापों को करने में कोई बाधा नहीं आती है।

4. बिहार क्षेत्र दौरा - जुलाई 21 - 24, 2014

परामर्शदाता दल, एनआईडीएम के प्रतिनिधि के साथ बिहार में वर्तमान आपदा पश्च आवश्यक मूल्यांकन को समझने के लिए 21 से 24 जुलाई 2014 के बीच



चित्र 5.5: परामर्श दल का बिहार दौरा

बिहार राज्य का दौरा किया (चित्र 5.5)। दल में श्री असलम परवेज, एडीपीसी के परियोजना प्रबंधक; श्री तारिक सोहैल, एडीपीसी के कार्यालय समन्वयक; और

श्री प्रियंक जिंदल, एनआईडीएम के विशेषज्ञ ने दौरे के दौरान निम्नलिखित बैठक और कार्यक्रम किया:

- (क) दल ने 21.7.2014 को कृषि डायरेक्टरेट श्री धर्मन्द्र सिंह के साथ बैठक की, और कृषि विभाग से संबंधित प्रमुख कर्मचारियों से बातचीत की, जहाँ कर्मचारियों ने आपदा पश्च अनुभवों के साथ-साथ पी एन डी ए के लिए इनपुट के बारे में अपना अनुभव साझा किया।
- (ख) उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव, श्री सुनील कुमार से 21.7.2014 को बैठक की, जहाँ उन्होंने पी एन डी ए पर सामान्य जानकारी और अनुभव तथा विशेष रूप से प्रशिक्षण पर जानकारी सझा किया।
- (ग) दल ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार(बीएसडीएमए) से भी बातचीत की। बी एसडीएमए के माननीय उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा, बीएसडीएमए के सदस्य प्रोफेसर ए एस आर्या और अन्य बीएसडीएमए कार्यकर्ता से बातचीत हुई।
- (घ) ऑक्सफेम इंडिया, सी ए एस ए, युनिसेफ, अंतर-एजेंसी समूह(आई ए जी) के सदस्यों और अन्य गैर सरकारी संगठनों से भी बातचीत हुई।
- (ङ) सहरसा के ए डी एम, सहरसा जिला के कर्मचारियों, आपदा प्रबंधन के जिला कर्मचारियों, और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन पर विभिन्न मुख्य कर्मचारियों के साथ 22 जुलाई 2014 को बैठक हुई, जिसमें कृषि, सिंचाई, अल्प सिंचाई, ट्यूबवेल, ग्रामीण सड़क, सड़क निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, भोजन और नागरिक आपूर्ति

इत्यादि पर चर्चा हुई। उन्होंने भोजन और अन्य आपदाओं के विषय में अपने अनुभवों को साझा किया और पी डी एन ए के लिए इनपुट भी उपलब्ध कराये।

- (च) दल ने बिहार राज्य पुल निगम सहरसा के कर्मचारियों के साथ 22.7.2014 को कोहरा ब्लॉक के अमरपुर गाँव का दौरा किया और वहाँ के स्थानीय समुदायों से संक्षिप्त बातचीत भी की।

बिहार लोक प्रशासन संस्थान और ग्रामीण विकास (बीआईपीएआरडी), बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी (बीएपीइपीस) इत्यादि के साथ भी टीम ने निर्धारित बैठक की। दौरे ने दल को समुदाय से संबंधित आपदा पश्च आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए अपनाये जा रहे वर्तमान प्रक्रियाओं को समझने में मदद की। बिहार दौरे का अनुभव पी डी एन ए के वर्तमान प्रणाली को समझने में उपयोगी होगा।

5.5.3 एनआईडीएम दल का मालिन भू-स्थलन दौरा, 2 से 3 अगस्त 2014

मालिन गाँव गोदेगाँव से लगभग 40 किमी उत्तर-पश्चिम और पुणे से 111 किमी उत्तर उत्तर-पश्चिम में लगभग 19° 9'41.58" उत्तरी आक्षांश और 73° 41'19" पूर्वी देशांतर और 796 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है (चित्र 5.6)। यह गाँव बहुउद्देश्य डिम्मे बाँध साइट से 15–16 किमी पर है तथा पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नीचे के भाग का पर्वत बनाता है और जनजातीय जनसंख्या द्वारा अधिकृत है जो पहाड़ी भूमि पर खेती पर निर्भर है। 30 जुलाई 2014 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंबेगाँव तालुक में स्थित

मालिन गाँव में एक बृहत भू-स्खलन आपदा घटित हुआ, जब इस क्षेत्र के लोग अपने घरों में सो रहे थे। बादल फटने से दो दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, जिससे भू-स्खलन हुआ जिसने 150 से अधिक लोगों को अपने में समा लिया। भू-स्खलन के कारण 40 से अधिक घरें मलबे में दब गये। भू-स्खलन की शुरुवात पर्वत के ऊपर से हुई और यह नदी स्तर तक गई, इस तरह मलबे ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। भू-स्खलन सबसे पहले बस के चालक द्वारा देखा गया जो उस क्षेत्र से गुजर रहा था और देखा कि गाँव मिट्टी और मलबे से बहा जा रहा था।



चित्र 5.6: मालिन भू-स्खलन का एक दृश्य

आपदाओं का प्रलेखन एनआईडीएम का मुख्य आदेश है। इस अभ्यास को करने के उद्देश्य के साथ, एनआईडीएम दल जिसमें जानकारी प्रबंधन और संचार विभाग के प्रमुख, डॉ सूर्य प्रकाश और परामर्शदाता, श्री तपस कुमार साहा राँय ने 2 और 3 अगस्त 2014 को भू-स्खलन का दौरा किया। दल ने जिला मजिस्ट्रेट श्री सौरभ राव, एन डी आर एफ कमांडेंट श्री आलोक अवस्थी, जी एस आई के डी जी श्री हरवंध सिंह के साथ-साथ जी एस आई के अन्य दल सदस्यों, मीडिया के लोगों, स्थानीय समुदायों, जनजाति कल्याण विभाग, अकादमिसियनों, महाराष्ट्र राज्य में भू-स्खलन पर कार्य करने वाले पेशेवरों तथा राज्य के अन्य

हितधारकों से बातचीत की।

दल ने एन डी आर एफ के प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों के साथ भू-स्खलन से प्रभावित भू-भाग तथा इस कार्य में लगे लोगों का प्रथम दृष्टया सूचना एकत्रित किया और प्रभावित क्षेत्र का सतही निरीक्षण किया। दल ने भूमि दरार और अवसंरचना खोजने का प्रयास किया जो इस क्षेत्र में संरचना और पुनर्घटना को नियंत्रित कर सकता है। भू-स्खलन जनसंख्या के पुनर्वास की संभावना को मूल्यांकित करने के लिए जो कि अब तक पर्वत के ढाल पर पड़ा था उसके रिक्तिकरण, विस्थापन और संचय क्षेत्रों को सीमांकित करने का एक प्रयास किया गया। दल ने रिक्तिकरण, खोज, बचाव, राहत और पुनर्वास के साथ-साथ समुदाय जागरूकता, भू-स्खलन से बचाव, रोकथाम, न्यूनीकरण और जोखिम की कमी के लिए तैयारी से संबंधित मुद्दों पर बातचीत किया। विस्तृत भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रयोग भी भू-स्खलन से संभावित जोखिम और भय को अच्छी तरह समझने के लिए तथा योजना बनाने, नीति निर्माण, खोज करने तथा इसके उपायों को ढूँढने से संबंधित मुद्दे को साझा किया गया।



चित्र 5.7: भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य

इस तरह की घटना तथा समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सीखे गये पिछले घटनाओं के प्रभाव को बताने, वर्तमान

प्रणाली के प्रभाव में सुधार लाने के लिए एनआईडीएम देश के मुख्य आपदा घटनाओं का प्रलेखन करता आ रहा है। विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और संकायों के अलग-अलग हितधारकों के विचारों और दृष्टिकोणों को जानने के लिए एनआईडीएम ने मालिन भू-स्खलन आपदा पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भी आयोजित की।

5.5.4 एनआईडीएम दल का राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान का दौरा, 5 अगस्त, 2014

आपदाकाल में विकलांग लोगों को सामान्य लोगों से अधिक व्यक्तिगत सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के लिए सहायता सेवाओं को पूरे विश्व में मुख्य स्थान मिल रहा है।

आपदाओं में विकलांग लोगों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है; देखभालकर्ताओं द्वारा सामना किये जाने वाली चुनौतियों; देखभालकर्ताओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, और आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण से विषिष्ट विकलांगों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ। अनुसंधान और अनुभव पर आधारित विकलांगता के साथ सबसे अधिक असुरक्षित लोगों के लिए, आपदा के पहले, उसी समय और आपदा के बाद के लिए प्रणाली और आई इ सी सामग्री तैयार करने तथा विकलांग लोगों का सामर्थ्य निर्माण करने के लक्ष्य का इरादा एनआईडीएम रखती है।

इस संदर्भ में, एनआईडीएम कार्यकर्ताओं, मेजर जेनरल डॉ वी के नायक (वरिष्ठ परामर्शदाता) और डॉ सौरभ दलाल (परामर्शदाता) ने राष्ट्रीय दृष्टि विहीन संस्थान, देहरादून का दौरा किया और वहाँ के निदेशक श्रीमती अनुराधा डालमिया और संस्थान के संकायों से बहुत देर तक विचार-विमर्श किया (चित्र 5.8)। बैठक के दौरान दृष्टि बाधित बच्चों की जरूरतें, उनके लिए आवश्यक विशेष उपकरणों, और उनके स्कूल के लिए आवश्यक न्यूनीकरण उपायों और होस्टलों जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।



चित्र 5.8: एनआईडीएम कार्यकर्ताओं का दृष्टि बाधित संस्थान के साथ बातचीत

एनआईवीएच ने दृष्टि बाधित लोगों के अनुदेशकों के लिए एनआईडीएम की मदद तथा प्रयास से आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के लिए टीओटी की आवश्यकता के बारे में बताया।

5.5.5 राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान उद्यान, नई दिल्ली के लिए डीएम योजना का सूत्रीकरण- एनआईडीएम दल का दौरा, 18 अक्टूबर 2014

एनआईडीएम दल ने राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान उद्यान (एन जे पी) से एक विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए आग्रह प्राप्त किया था। इस संदर्भ में शनिवार, 18 अक्टूबर 2014 को कार्यकारी निदेशक



चित्र 5.9: कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम का एनआईडीएम दल के साथ, राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान पार्क नई दिल्ली का दौरा

डा सत्येन्द्र के नेतृत्व में एन जे पी का दौरा किया गया (चित्र 5.9)। अन्य संकाय के सदस्य जिन्होंने प्राणिविज्ञान उद्यान का दौरा किया उनमें एनआईडीएम के डॉ आमीर अली खान, डॉ सौरभ दलाल, एमिटी वन्यजीव विज्ञान संस्थान के डॉ एन पी एस चौहान शामिल थे। प्राथमिक अध्ययन में अनेक संदर्भ मौजूद थे जैसे— पशु के रहने के जगहों, सुरक्षा घेरा, वर्तमान सुरक्षा तंत्र, पशु चिकित्सालय, अपातकालीन विज्ञप्तियाँ और जोखिम विश्लेषण, इत्यादि पर विचार किया

गया। डी एम योजना के विकास हेतु संरचना और अन्य उपयुक्त मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए, एन जी पी के सचिव, श्री अमिताभ अग्निहोत्री और अन्य कर्मचारी सदस्यों तथा एन जी पी के संचालक कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। डी एम योजना के अतिरिक्त एनआईडीएम ने एन जी पी के लिए कर्मचारियों के तकनीकी सामर्थ्य और कौशल के विकास और लंबी अवधि की सामर्थ्य निर्माण उपायों का प्रस्ताव भी रखा।

अध्याय



मुख्य घटनाएँ/कार्यशालाएँ/ सम्मेलन/सेमिनार और अन्य आउटरीच क्रियाकला

6.1. आउटरिच क्रियाकलाप

6.1.1. वन महोत्सव 21 अगस्त 2014

कर्मचारियों को वनों से घनिष्ठ संपर्क की संवेदनशीलता का एहसास कराने तथा डी आर आर को पर्यावरण संवेदनशील डी आर आर योजना की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से एनआईडीएम ने 21 अगस्त 2014 को "वन महोत्सव" मनाया। पीएमओ के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर भाग लिया। बिहार— एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा; सिक्किम— एसडीएमए के उपाध्यक्ष प्रोफेसर वी के शर्मा और एनडीएमए के सचिव श्री एस एन मोहंती भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर वृक्षारोपन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों और एनआईडीएम के कर्मचारी सदस्यों द्वारा कई पौधे लगाये गये (चित्र 6.1)।



चित्र 6.1: सचिव, एनडीएमए श्री एस एन मोहंती, "वृक्षारोपन" कार्यक्रम के दौरान एनआईडीएम परिसर में पौधा लगाते हुए

6.1.2. 2 अक्टूबर 2014 को एनआईडीएम द्वारा आयोजित सफाई अभियान

"स्वच्छ भारत अभियान" के एक हिस्से के रूप में एनआईडीएम ने 2 अक्टूबर 2014 को एक सफाई अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और अपने-अपने कार्य-स्थलों की तथा एनआईडीएम परिसर की सफाई की (चित्र

6.2)। इस अवसर पर एक संक्षिप्त वार्तालाप भी आयोजित की गई। सभी कर्मचारियों ने सफाई पर एक शपथ ली और सफाई तथा स्वच्छता के विषय में कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सबसे अधिक साफ कार्य—स्थल वाले कर्मचारी को पुरस्कृत भी किया गया। तीन सबसे अधिक साफ कक्षों की पहचान के लिए एक समिति बनाई गई जिसने सभी कक्षों का निरीक्षण किया और पुरस्कार के लिए कक्ष का चुनाव किया। चुने गये तीन पुरस्कार थे— (क) पुस्तकालय (प्रथम पुरस्कार) (ख) एनआईडीएम का सुपुर्दगी विभाग (द्वितीय पुरस्कार); और(ग) डॉ सुषमा गुलेरिया और सुश्री अनुपमा सेठी का कक्ष (तृतीय पुरस्कार), इन्हें 08 अक्टूबर 2014 को आपदा न्यूनीकरण दिवस पर प्रमाण-पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया।



चित्र 6.2: सफाई अभियान चलाते एनआईडीएम कर्मचारी

6.1.3. "आपदा न्यूनीकरण दिवस", 8 अक्टूबर 2014

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 8 अक्टूबर 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "आपदा न्यूनीकरण दिवस" मनाया। "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए गृह सुरक्षा और स्थानीय तैयारी" के ऊपर राष्ट्रीय ध्यान केन्द्रित करने का यह एक अवसर था। कार्यक्रम की शोभा सचिव (सीमा प्रबंधन) एमएचए सुश्री स्नेहलता कुमार, एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल श्री ओ पी सिंह, बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा; सिक्किम एसडीएमए के उपाध्यक्ष,

प्रोफेसर वी के शर्मा और कई अन्य उच्चाधिकारियों, कर्मचारियों और बच्चों ने बढ़ाया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ. सत्येन्द्र ने इस अवसर पर प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत करते हुए एनआईडीएम और सामर्थ्य निर्माण के द्वारा आपदा प्रबंधन में इसकी सहभागिता के बारे में संक्षिप्त में बताया।



चित्र 6.3: मुख्य अतिथि, सुश्री स्नेहलता कुमार, डीआरडी के दौरान सभा को संबोधित करते हुए

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सुश्री स्नेहलता कुमार ने की (चित्र 6.3)। सुश्री कुमार ने समुदाय तैयारी की भूमिका के बारे में मुख्य रूप से बताया जो कि सभी हितधारकों के संदर्भित प्रायसों से संभव हो सका है। डॉ. सत्येन्द्र और डॉ. ए. डी. कौशिक द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई एक पुस्तक जिसका शीर्षक है "जंगल आग आपदा प्रबंधन" का अनावरण किया गया (चित्र 6.4)।



चित्र 6.4: "जंगल आग आपदा प्रबंधन" शीर्षक पुस्तक का अनावरण

मुख्य बातों "आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए गृह सुरक्षा और स्थानीय तैयारी" का संबोधन प्रोफेसर वी के शर्मा द्वारा किया गया। विशेष संबोधन बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा, एन डी आर एफ के डायरेक्टर जनरल श्री ओ पी सिंह ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया और प्रभावी अनुक्रिया परिप्रेक्ष्य के माध्यम से आपदा तैयारी की भूमिका के विषय में बताया। एनआईडीएम ने पूरे देश के स्कूलों में पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया और आपदा न्यूनीकरण दिवस पर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। (चित्र 6.5).



चित्र 6.5: कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम संकाय कर्मचारी व पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ

उद्घाटन समारोह के बाद "आपदा प्रबंधन में बच्चे और अशक्तता" पर विशेष तकनीकी सत्र प्रारंभ हुआ। सत्र की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने की और पैनल के अन्य सदस्यों में डॉ. अजय बहल (सुश्रुत ट्राउमा केन्द्र के प्रमुख); डॉ. सरस्वती आर्या (जिला समन्वयक उत्तर-पश्चिम), शिक्षा विभाग नई दिल्ली); श्री शौरभ गौतम (वैश्विक बचाव परामर्ष प्राइवेट लिमिटेड के सचिव); और श्री अनिल कुमार, आई सी आर सी के शारीरिक पुनर्वास कार्यक्रम प्रबंधक के सहायक मौजूद थे। डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव का अभिवादन किया।

6.1.4. राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर 2014

भारत सरकार ने सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस, 31 अक्टूबर को "राष्ट्रीय एकता दिवस" (नेशनल

यूनिटी डे) के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस अवसर ने हमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के वास्तविक और संभवित जोखिम से लड़ने के लिए अपने देश की आंतरिक शक्ति और लचीलापन को याद दिलाने का मौका दिया। प्रसंग एकता, अखण्डता सुरक्षा और बचाव का था। इस अवसर पर सभी एनआईडीएम कर्मचारी एक साथ इकट्ठा हुए और एकता की शपथ ली।

6.2. सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएँ

6.2.1. एनआईडीएम में एनसीआरएमपी के अंतर्गत भारत के लिए आपदा पश्च आवश्यकता निर्धारण पर परामर्श कार्यशाला, 7 अप्रैल, 2014

एनआईडीएम में भारत के लिए आपदा पश्च आवश्यकता निर्धारण (पीडीएनड) पर अध्ययन के लिए एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला 7 अप्रैल, 2014 को आयोजित की गई जो एन सी आर एम पी के अधीन एनआईडीएम द्वारा कार्यान्वित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य था—परिकल्पना से वास्तविक कार्य तक पी डी एन ए की ओर एक सामान्य समझ रखना, ए डी पी सी दल द्वारा तैयार किया गया मसौदा प्रारंभिक प्रतिवेदन की समीक्षा करना, जो इस अध्ययन के लिए श्री रोबर्टो जोवेल—एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के नेतृत्व में तकनीकी परामर्श उपलब्ध करा रहा है। अध्ययन का लक्ष्य विभिन्न अभ्यासों, उपकरणों, क्षति के संरचनाओं, और वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा आयोजित हानि मूल्यांकन करना और इन्हें प्रोन्नत करना था। कार्यशाला के प्रतिभागियों में उत्पाद/आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्यकर्ता और दस परियोजना राज्यों के ए टी आई; एम एच ए, एन डी एम ए, विश्व बैंक, सी डब्ल्यू सी, एम ओ इ एफ, योजना आयोग, आई एम डी, अकादमी संस्थानों, विभिन्न विकास सहभागी संस्थाओं के प्रतिनिधि/विशेषज्ञ और अध्ययन के तकनीकी परिचालक समिति शामिल थे (चित्र 6.6)।

मुख्य अतिथि, डॉ के सलीम अली, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में माननीय सदस्य ने कार्यशाला में उपस्थित

समूहों को संबोधित किया और विशेषकर जब डी एम अधिनियम में ऐसा प्रावधान के संदर्भ में, इस प्रकार के अध्ययन की अति आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस पहल की प्रशंसा की और राज्यों को इस अध्ययन के प्रयोगिक परिणाम से सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ मुख्य उच्चाधिकारियों में जो अपने व्यस्त कार्य से समय निकालकर यहाँ आये हुए थे उनमें शामिल थे— सिविकम एसडीएमए के माननीय वी सी, प्रोफेसर वी के शर्मा; उत्पाद शुल्क तमिलनाडु के सचिव, श्री गगनदीप सिंह वेदी; एनसीआरएमपी, एनडीएमए के परियोजना प्रबंधक, श्री एस पी वासुदेव; कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम डॉ. सत्येन्द्र इत्यादि।



चित्र 6.6: कार्यशाला में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों के प्रतिभागी

एनसीआरएमपी— पीआईयू, एनआईडीएम के परियोजना प्रबंधक डॉ. के. जे. अनंदा कुमार ने अध्ययन का परिचय आवश्यकता और उद्देश्य का संदर्भ देते हुए दिया। इसके बाद पी डी एन ए संदर्भ पर तकनीकी सत्र हुआ और अध्ययन के भागों का ब्योरा के साथ-साथ दल के नेता श्री रोबर्टो जोवेल और ए डी पी सी के परियोजना प्रबंधक श्री असलम परबेज ने दो राज्यों के दौरे के अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या की दृष्टि से और पूरे सत्र तक सभी प्रतिभागियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, दोनों ही दृष्टियों से कार्यशाला काफी सफल रहा। पी डी एन ए के चारो ओर के जटिल मुद्दे पर चर्चा की गई और विस्तृत जानकारी वाले जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के साथ कार्य

कर रहे अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा कुछ बहुमूल्य इनपुट सुझाये गए। परियोजना के दौरान सामाजिक प्रभाव जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए आकर्षित किया गया। सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य इनपुट और उनके अच्छे कामनाओं के लिए डॉ के जे अनंदा कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव किया गया और कार्यशाला बहुत ही विचारणीय स्वर के साथ समाप्त हुई।

6.2.2. "हिमालय के विशेष संदर्भ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम", ए टी आई, नैनीताल, 20 से 22 मई 2014

एनआईडीएम आपदा जोखिम प्रबंधन की नीति और संचालन स्तरों के माध्यम से जलवायु सापेक्षिक विकास और अनुकूलन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं तथा एमओएफ, टीआईआरआई, यूएनडीपी, आईएसडीटी(यूएसए), विनरॉक इंटरनेशनल, जीआईजेड-आईजीडीपी, सीडीकेएन यूरोलीय संघ, आईसीआईएमओडी, यूएनडीपी इत्यादि के साथ पायलाट परियोजना का कार्यान्वयन किया है। इस विषय पर प्रथम पाठ्यक्रम एनआईडीएम द्वारा राजस्थान में 2007 में आयोजित किया गया, इसके बाद इसी वर्ष एन आई डी एम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन परियोजनाओं से सीखे गये जानकारी के आधार पर तथा भारत और इसके बाहर से पहुँच के आधार पर, एनआईडीएम के संकाय सदस्यों डॉ अनिल कुमार गुप्ता और सुश्री स्वाति सिंह ने "जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन" नामक एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया है और इसके अंतिम मसौदे का हिमालय के विशेष संदर्भ में जाँच कर ली गई है तथा उत्तराखंड में बाढ़ और भू-स्खलन के खतरों के प्रबंधन संबंधी मुद्दे को संबोधित करने के लिए भेजी जा चुकी है। हाल ही के उत्तराखंड आपदा 2013 के, तकनीकी विधिक संरचना कार्य, राज्य और स्थानीय स्तर पर नीति तंत्र, उपकरण, समुदायिक जीविका, आपदा के पहले भोजन तथा पर्यावरण स्वास्थ्य मुद्दे, संकट प्रबंधन और आपदा पश्च शाश्वत पुनर्निर्माण

तथा वापसी संदर्भ पर विशेष बल दिया गया था।

कार्यक्रम का आतिथ्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल द्वारा किया गया तथा इसमें आपदा प्रबंध विभाग, वन, कृषि, पी डब्ल्यू डी, जल संसाधन, स्वास्थ्य, पर्यटन, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय इत्यादि विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। एनआईडीएम के नीति योजना के अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार गुप्ता के अतिरिक्त, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी सी तिवारी और प्रोफेसर आर के पांडेय, केन्द्रीय हिमालय पर्यावरण संघ के डॉ पुस्किन पटियाल, आई एफ ए एन ओ एस- ईंडिया के डॉ सन्ध्या छेत्री, एटीआई के डॉ ओमप्रकाश और डॉ मंजु पांडेय, इत्यादि जैसे विशेषज्ञ उपस्थित थे (चित्र 6.7)। भूमि उपयोग और भू-दृश्य पारिस्थितिकी, भू-स्खलन और जल संरचना, शहरीकरण और नागरिक ढाँचा के संदर्भ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए नैनीताल में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षेत्र दौरा आयोजित किया।



चित्र 6.7: विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एटीआई नैनीताल में प्रतिभागी

6.2.3. एनआईडीएम में समूह दुर्घटना प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, 26 से 27 मई 2014

एक समूह दुर्घटना प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनआईडीएम में 26 और 27 मई 2014 को किया गया जिसमें आपदा प्रबंधन योजना में आपदा दवा की महत्ता को प्रकाश में लाया गया। दिल्ली- एन सी आर के विभिन्न अस्पतालों के 45 मेडिकल अधीक्षकों,

डॉक्टरों, नर्सिंग प्राधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया (चित्र 6.8)। कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु था, समूह



चित्र 6.8: सामूहिक दुर्घटना प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

दुर्घटना प्रबंधन, जिसमें विशेष रूप से आपदा और मानव संकट पर ध्यान दिया गया था। इस प्रशिक्षण में संबोधित किये गये मुद्दे थे:

1. भारत में डी एम की परिकल्पना और डी एम का संरचनात्मक संगठन;
2. ट्रिएज की विज्ञप्ति ;
3. आपदाओं के स्वास्थ्य और मनोसामाजिक प्रभाव;
4. अस्पताल डी एम योजना;
5. सीबीआरएनइ जोखिम; और
6. अस्पताल द्वारा संकट प्रबंधन पर घटना अध्ययन पर भी चर्चा की गई।

प्रतिभागियों को युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुर्घटना प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। एनआईडीएम के डॉ सौरभ दलाल ने आपदा प्रबंधन के मूल की ओर जागरूकता की आवश्यकता और संकट के समय चिकित्सा भाईचारे में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया। एनआईडीएम के वरिष्ठ परामर्शदाता मेजर जनरल डॉ वी के नायक ने प्रायोगिक और कार्ययुक्त आपदा प्रबंधन योजनाओं की महत्ता और अस्पताल दुर्घटना कमांड प्रणाली की स्थापना तथा सभी कार्य स्तर पर एस ओ पी की अनिवार्यता के बारे में प्रतिभागियों को बताया।

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र ने विदाई संबोधन में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त

जानकारी के प्रसारण में एक उत्प्रेरक जैसा कार्य करने की अपील की और अपने संबंधित अस्पतालों में इसी तरह के कार्यक्रम संचालित करने की अपील की। उन्हें ऐसे कार्यक्रमों के संचालन में सहायता और सहयोग का आश्वासन भी उन्होंने दिया। उन्होंने घटना अध्ययन और पेशेवर पेपर को एनआईडीएम पत्रिका में प्रकाशन के माध्यम से अनुभवों को साझा करने की आशा भी व्यक्त की।

6.2.4. एनआईडीएम ने फाइलिन चक्रवात 2013 : सीखे गये सबक“ पर कार्यशाला आयोजित की, 30 मई 2014

एनआईडीएम ने “फाइलिन चक्रवात: एक सीख पर राष्ट्रीय कार्यशाला 30 मई 2014 को आयोजित की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य फाइलिन चक्रवात से सीखे गये अनुभव के बारे में चर्चा करना और सबसे अच्छे अभ्यास जिससे इस आपदा के अनुक्रिया की सफलता में योगदान मिला था, पर बल देना था। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माननीय सदस्य, डॉ के सलीम अली थे (चित्र 6.9)। उन्होंने आपदा प्रबंधन के मे संबंध में आपदा के संरचना की जानकारी, गुप्त सामुदायिक जागरूकता की शुरुवात, जैविक-रक्षा की बढ़ोतरी और बीमा की धारणा का परिचय देने संबंधी जानकारी दी।



चित्र 6.9: एनडीएमए के माननीय सदस्य, डॉ के सलीम अली, वीसी बीएसडीएमए, श्री अनिल के सिन्हा; डीजी जीआईडीएम डॉ पी के मिश्रा; स्पेशल डीजीपी श्री संजिव मारिक; आईपीएस और कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम उद्घाटन सत्र के दौरान

श्री संजीव मलिक, आई पी एस, स्पेशल डी जी पी, जो 1999 के सुपर चक्रवात के समय उड़ीसा में उपस्थित थे, ने दोनों 1999 के चक्रवात तथा 2013 के चक्रवात की तुलना की और बताया कि उड़ीसा ने पिछले चक्रवात से बहुत कुछ सीखा है और समान गलती फिर से नहीं दोहराने देगा। इस संबंध में उन्होंने भूत से ऐसे कई उदाहरण दिये, जो फाइलिन चक्रवात के समय और बाद में पहले से ही जाँच कर ली गई। उन्होंने कहा कि चक्रवात के धीमा होने के तत्काल बाद वहाँ के जीवन को सामान्य स्तर पर लाने के लिए 1117 से अधिक लोगों को लगाया गया। उन्होंने आई एम डी को समय से चक्रवात की भविष्यवाणी करने के लिए धन्यवाद दिया जिससे योजना को पहले बनाने में तथा लोगों को समय से जगह खाली कराने में मदद मिली। इसके बाद गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान(जिआईडीएम) के डी जी डॉ पी के मिश्रा द्वारा चक्रवात जोखिम प्रबंधन के ऊपर एनआईडीएम के इ-लर्निंग पाठ्यक्रम (स्व अध्ययन पाठ्यक्रम) की शुरुवात की गई। डॉ पी के मिश्रा ने समन्वित पहुँच, न्यूनीकरण और चेतावनी प्रणाली पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की जानकारी, संचालन, सूचना का प्रसारण और नागरिक जानकारी, आपदा प्रबंधन के मुख्य पहलू हैं। उन्होंने भविष्य के लिए प्रभावी चेतावनी हेतु तकनीकी प्रोन्नयन की आशा की। बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा ने अच्छे प्रलेख की महत्ता के बारे में बताया जो लोगों को आपदा के बारे में जानकारी तथा चेतावनी देने में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास क्षमता है, लेकिन जागरूकता तथा शिक्षा की कमी के कारण देश को आपदा का त्रास भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने एनआईडीएम के साथ काम करने की तथा जागरूकता उद्देश्य के लिए अच्छे प्रलेख तैयार करने हेतु सभी संभव मदद करने की अपनी इच्छा जताई। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ. सत्येन्द्र

ने उदघाटन समारोह में मुख्य अतिथि का अभिवादन किया और उन्हें आतिथ्य सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि एनआईडीएम के आदेश के अनुसार, संस्थान में “फाइलिन” चक्रवात का प्रलेखन किया जा रहा है। इस संबंध में एनआईडीएम ने क्षेत्र दौरा, संबंधित प्रशासनों से संपर्क, लोगों से कार्यशाला के आयोजन द्वारा संपर्क, तथा सभी हितधारकों से फीडबैक इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का विचार और अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रलेख के मसौदा तैयार करने में मदद पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि प्रलेख को और संशोधित करने के लिए तथा इसे अपग्रेड करने के लिए इस प्रलेख का कच्चा खाका भी सभी हितधारकों से साझा किया जाएगा और उनसे बहुमूल्य फीडबैक लिया जाएगा।

कार्यशाला का उद्देश्य पूर्व चेतावनी प्रणाली, समन्वय, प्रशासनिक और सामुदायिक मुद्दे और इससे आगे के बारे में चर्चा करना है। उन्होंने इस अवसर पर अगस्त बैठक में एनआईडीएम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न चेतावनी क्रियाकलापों को सूचित करने और कार्यशाला में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को 4 जून को एस सी ओ पी इ संग्रहालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किये जा रहे कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने हाल के चक्रवात में बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए उड़ीसा और आंध्रप्रदेश सरकारों की प्रशंसा की।

कार्यशाला का प्रथम सत्र जल्द चेतावनी और अनुक्रिया पर आधारित था, जिसमें एन डी एम ए के माननीय सदस्य श्री के एम सिंह जो सत्र के अध्यक्ष भी थे, ने ओडिसा त्वरित आपदा कार्य बल (ओआरडीएएफ) के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि ओ आर डी ए एफ ने आपदाकाल में बहुत ही अच्छे कार्य किया है। उन्होंने तीनों टायरों अर्थात् एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए की महत्ता और तैयारी की प्रशंसा की और

संपूर्ण तटीय सीमा पर ओड़ीसा सरकार द्वारा बनाये गये चक्रवात शरण की प्रशंसा की। उन्होंने जागरूकता सृजन और माक ड्रील को आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपकरण के रूप में जानने पर बल दिया।

कार्यशाला का दूसरा सत्र फाइलिन चक्रवात के समय समन्वयन, प्रशासनिक और समुदायिक मुद्दे पर केन्द्रित था, जिसकी अध्यक्षता सिक्किम एसडीएमए के सम्माननीय उपाध्यक्ष, प्रोफेसर वी के शर्मा ने की तथा उपाध्यक्षता एम एच ए के संयुक्त सचिव(डी एम), श्री जी वी वी शर्मा; बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा और आई एम डी के भूतपूर्व डी जी डॉ अजित त्यागी ने की। इस सत्र के दौरान पाँच प्रस्तुतीकरण दिये गये जिसमें सषस्त्र सेना, पाँवर सेक्टर और जिला प्रशासन शामिल था।

दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता एन डी एम ए के माननीय सदस्य डॉ एच के गुप्ता ने की तथा इसकी उपाध्यक्षता बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा ने की। इस सत्र में भविष्य के चक्रवात से संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर रणनीति की महत्ता प्रदर्शित करना तथा इसे किस प्रकार प्रभावी और बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जाए, पर आधारित था।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य पदाधिकारियों में आई एम डी के डी जी प्रोफेसर एल एस राठौड़, एन डी आर एफ के डी जी प्रोफेसर एम आलम; स्पेशल ओडिसा के आर सी, श्री पी के महापात्रा; आई एन सी ओ आइ एस के वैज्ञानिक-एफ, डॉ टी एम बालाकृष्णन नायर; एन डी आर एफ के आई पीस आई जी श्री संदीप आर राठौड़; नई दिल्ली के आई एम डी डॉ एम महापात्रा; एन आई ओ टी के डायरेक्टर डॉ एम ए आत्मानंद और कई अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञ।

6.2.5. "स्थानीय स्तर पर आपदा सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 9 जून 2014

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 9 जून 2014 को

गाँधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा हाल, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली में एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न आयु वर्ग के साठ से अधिक प्रतिभागी जैसे- शिक्षक, छात्र और बूढ़े व्यक्ति, इस प्रशिक्षण में थे। अधिकांश प्रतिभागी नजदीकी जे जे कॉलोनी के महिलायें और बच्चे थे। प्रशिक्षण सामुदायिक तैयारी, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा और खोज तथा बचाव पर केन्द्रित था, क्योंकि किसी आपातकाल या आपदा के समय समुदाय ही प्रथम अनुक्रियावादी होते हैं(चित्र 6.10)।



चित्र 6.10: विशेषज्ञों द्वारा बताये जा रहे आपातकालीन तैयारी पर तकनीक

प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ एनआईडीएम की सुश्री नेहा सिवाच के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने आपदा प्रबंधन के मूल विषय के बारे में बताया। वैश्विक बचाव परामर्श लिमिटेड के श्री एम एम गुप्ता ने प्राथमिक उपचार के बारे में संक्षिप्त विचार दिये। एनआईडीएम के श्री मनोज ने अग्नि सुरक्षा के बारे में बताया और डीडीएमए (उत्तर-पश्चिम) के श्री हेमंत ने आपातकालीन बचाव विधि, प्राथमिक उपचार इत्यादि के बारे में प्रतिभागी को प्रायोगिक सत्र दिया। प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति गाँधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के सुश्री कुसुम बेन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुई।

6.2.6. पारिस्थितिकी आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (इको डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नीति कार्यशाला, बोगोर, इंडोनेशिया, 16 से 21 जून 2014

पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर साझेदारी (पीइडीआरआर), राष्ट्रीय संसाधन और विकास केन्द्र (सीएनआरडी) और इंडोनेशिया विज्ञान संस्थान (एलआईपीइ) ने पारिस्थितिक तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा इको-डीडीआर सीसीए पर अनुदेशकों का वैश्विक प्रशिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नीति कार्यशाला का आयोजन 16 से 21 जून 2014 तक बोगोर, इंडोनेशिया में किया (चित्र 6.11)।



चित्र 6.11: कार्यशाला के दौरान अन्य प्रतिभागियों के साथ का एक समूह फोटो

नीति कार्यशाला का लक्ष्य डीआरआर और सीसीए का पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित पहुँच के माध्यम से अधिकतम एकीकरण करना था तथा ये समेकित रणनीति किस प्रकार सूचना नीति को मदद पहुँचा सकती है तथा इस लक्ष्य को आपदाओं को स्थानीय तथा राष्ट्रीय लोच को मजबूत करने के लिए इस लक्ष्य को कार्यान्वित करना तथा अगले दस वर्षों तक किसी अनुसंधान कार्यसूची की पहचान करना जो नीति तथा निर्णय लेते समय प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हो। लगभग 100 अनुसंधानकर्ताओं नीति निर्माताओं और अभ्यासकर्ताओं ने सफल कहानियों को साझा किया और बताया कि किस तरह इको प्रणाली से संबंधित डी आर आर/सी सी ए पर आधारित विज्ञान और साक्ष्य किसी प्रभावपूर्ण निर्णयों को प्रभावी रूप से कैसे सूचित करते हैं। एनआईडीएम के असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री श्रीजा एस नायर ने थिमेटिक सत्र 2, इको-डी आर आर/सी सी ए निर्णायक उपकरण के अंतर्गत, इस कार्यक्रम में भाग ली और नीति उपकरणों तथा विधि के माध्यम से भारत में सी सी ए-डी डी आर को मुख्य धारा में लाने और इ आई ए एक उपकरण के रूप में उत्तराखंड

में आपदाओं के संबोधन से संबंधित पेपर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत की। कार्यकारी समूहों ने इको-डी डी आर के कार्यान्वयन के लिए संबोधन और अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया।

सुश्री नायर ने इको-डीडीआर-सीसीए पर तीन दिवसीय वैश्विक अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, पश्च सम्मेलन में भी भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था: (क) डीआरआर के लिए इको-प्रणाली सेवाओं के कई लाभों और शाश्वत विकास तथा इन सेवाओं को बनाये रखने तथा बढ़ाने की विधियों के बारे में मुख्य कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना।; (ख) इको प्रणाली प्रबंधन और डी आर आर को जलवायु लोच विकास योजना विधि में समेकित करने पर जानकारी और कौशल का विकास करना; (ग) पर्यावरणीय/इको प्रणाली प्रबंधन, डी आर आर, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और विकास पेशेवरों के बीच विपरीत खण्डीय सहयोग को प्रोन्नत करना तथा सुविधा प्रदान करना; और (घ) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में इको-डी आर आर तथा इको- डी आर आर से संबंधित राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के अन्य प्रशिक्षण को प्रोन्नत करने के लिए अनुदेशकों का एक संघ तैयार करना।

6.2.7. "रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" ओडिसा, 8 से 11 जुलाई 2014

एनआईडीएम सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित बहु अनुशासनिक केन्द्र (एसएचइ के लिए एमडीसी), ओडिसा के सहयोग से 8 से 11 जुलाई 2014 तक एमडीसी-एसएचइ परिसर भुवनेश्वर में रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का लक्ष्य औद्योगिक आपदाओं विशेषकर रासायनिक उद्योगों, से रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी और अनुक्रिया, से संबंधित मुद्दों पर प्रतिभागियों की जानकारी और कौशल को अद्यतन करना था। एम डी सी के उपाध्यक्ष श्री जी एस कुंठिया ने मंच पर सभी प्रतिनिधियों तथा उच्चाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। एनआईडीएम के

एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनिल के गुप्ता ने मुख्य बिंदु पर संबोधन किया; श्री उपाध्याय ने मुख्य वक्तव्य को संबोधित किया; और एनआईडीएम के सहायक प्रोफेसर सुश्री श्रीजा नायर ने कार्यक्रम संदर्भ के बारे में बताया; ओडिसा सरकार के म्युनिसिपल प्रसासन के आई ए एस डायरेक्टर श्री संजीव कुमार मिश्रा सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता ओडिसा राज्य के फैक्टरी और उबालक के डायरेक्टर श्री पी सी दास ने की। उद्घाटन समारोह की समाप्ति एम डी सी के सचिव श्री जी डी रथ के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में एक संसाधन पुस्तक “केमिकल (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन” का उद्घाटन किया गया। कुल 12 तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ जिसमें रासायनिक आपदा का परिचय, कारणों, प्रभावों तथा प्रबंधन, रासायनिक आपदा के लिए विधिक और सांस्थानिक संरचना, उपकरणों तकनीकों और रासायनिक आपदा प्रबंधन में विधियाँ और तैयारियाँ, अनुक्रिया और आपदा प्रबंधन संरचना के साथ एकीकरण, इत्यादि शामिल किये गए। कार्यक्रम के तीसरे दिन एम ए एच उद्योग, इफको पारादीप के क्षेत्र दौरा का आयोजन किया गया और किसी पाइपलाइन से डाइमिनियम फॉस्फेट उद्योग (डी ए पी) में आपूर्ति के समय अमोनिया लिक दृश्य के लिए एक बनावटी ड्रिल का आयोजन किया गया। 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कुल अड़तीस कर्मचारी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और उद्योग के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, ने प्रशिक्षण में भाग लिया (चित्र 6.12)।



चित्र 6.12: प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी

6.2.8. “शाश्वत विकास के लिए डी आर आर रणनीति- योजना और नीति उपकरण” पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, 21 से 22 अगस्त 2014

आपदा प्रबंधन में प्रतिमान ‘अनुक्रिया से राहत’ से ‘रोकथाम-न्यूनीकरण और तैयारी’ की ओर जाता है। आगे का केन्द्रीय पहुँच द्वितीय प्रतिमान की ओर जाता है जो ‘जोखिम असुरक्षा और पर्यावरण’ की ओर जाता है जिसे विकास और शाश्वतता के कई भागो में डीआरआर को मुख्य धारा में लाने के लिए गंभीर प्रयास कहा जाता है। इस यात्रा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक कार्यक्रम के साथ साक्ष्यित किया जाता है, जैसे- यूएन-आईडीएनडीआर, कार्य का हाइड्रो संरचना, एषीआई मंत्रालयी सम्मेलन- बैंकाक घोषणा और एचएफए-2 शासन रणनीति।

इस प्रसंग पर एनआईडीएम द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आपदा प्रबंधन योजना पर विभिन्न उपकरणों और तरीकों की भूमिका, विप्लेशन, निर्णय लेने और मूल्यांकन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/संगठनों से बाइस संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध आपदा प्रबंध विशेषज्ञ और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा ने किया (चित्र 6.13)। डॉ. मिश्रा ने अपने उद्घाटन



चित्र 6.13: संयुक्त सचिवों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुए डॉ. पी के मिश्रा

भाषण में सामर्थ्य निर्माण में और अधिक क्रमिक पहुँच की आवश्यकता पर बल दिया और सरकार में सभी हितधारकों का सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए कहा। डॉ. मिश्रा ने एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों के सहयोग विशेषकर हाल ही के वर्षों में इसके प्रकाशनों पर खुशी जताई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव, श्री एस एन मोहंती और योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार ने भी इस अवसर पर संबोधित किया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, डॉ सत्येन्द्र ने स्वागत भाषण दिया तथा डॉ गुप्ता ने कार्यक्रम के परिदृश्य के बारे में बताया।

प्रसंग पर चार तकनीकी सत्र थे, जैसे— डीआरआर को दीर्घकालीन विकास में एकीकृत करना, उपकरण और तकनीक, पहुँच और रास्ते, और तत्कालीन विकास, बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा, सिक्किम एसडीएमए के उपाध्यक्ष, प्रोफेसर वी के शर्मा, यूएनडीपी के श्री डी पद्मनाभन, और डॉ बी एन सथपति द्वारा क्रमशः अध्यक्षता की गई। उपकरणों और तकनीकी पर सत्र की संयुक्त सचिव (डीएम) जीओआई ने उपाध्यक्षता की। संसाधन व्यक्तियों में शामिल थे— डॉ अखिलेश गुप्ता (सलाहकार, डीएसटी, जीओआई), डॉ आर के भंडारी (भूतपूर्व निदेशक सीबीआरआई), डॉ ए बी हाप्पनहल्ली (वरिष्ठ सलाहकार और परियोजना निदेशक, सिकोम, एमओइएफ), डॉ. के जे रमेश (सलाहकार, भू विज्ञान मंत्रालय), डॉ. अनिल गुप्ता (एनआईडीएम), डॉ. वी के नायक (एनआईडीएम), श्री तापस कुमार साहा राँय (एनआईडीएम), डॉ. के जे अनंदा कुमार (एनआईडीएम), श्री आलोक चंद्रा (सलाहकार, पेट्रोलियम मंत्रालय), प्रोफेसर जमाल अंसारी (भूतपूर्व निदेशक, एसपीए), प्रोफेसर सी (एनआईडीएम), श्री एन एम प्रुष्टि (रणनीति केन्द्र), डॉ. सुमाना भट्टाचार्य (कार्यक्रम समन्वयक, सह-समन्वयक), डॉ. जीनत नियाजी (उपाध्यक्ष, विकास विकल्प)।

हाल ही के विकास के सत्र में, प्रतिभागियों ने अपने समूह प्रतिवेदनों के विषय में संबोधित किया, जिसमें डी आर आर को विकास तथा स्थानीय विकास रणनीति

के मुख्य धारा में लाना शामिल था, और सामर्थ्य विकास के मुद्दे का सुझाव दिया। विदाई कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (डीएम), श्री जी वी वी शर्मा ने की। डी एस एस से संबंधित मुद्दे जिसमें रिमोट सेंसिंग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पीडीएनए, डीआरआर के लिए मानव संसाधन योजना, स्थानीय स्तर पर योजना, शामिल थे, डीआरआर को विभागीय योजना में एकीकृत करने के बारे में प्रशिक्षण सत्र में चर्चा की गई।

6.2.9. "आपदा काल में अस्पताल को कार्यरत रखना" पर कार्यशाला, 5 सितंबर 2014

"आपदा काल में अस्पताल को कार्यरत रखने पर" एक दिवसीय कार्यशाला एनआईडीएम में 5 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और जियो जोखिम समाज भारत के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई (चित्र 6.14)। इस कार्यशाला का लक्ष्य दिल्ली एन सी आर के अस्पताल प्रशासक और अस्पताल अनुक्रिया से संबंधित मुख्य व्यक्ति थे।

सत्र का शुभारंभ डॉ सत्येन्द्र, इ डी, एनआईडीएम द्वारा किया गया। जियो हाजार्ड इंटरनेशनल के श्री विलियम होम्स और डॉ जेनिसे रोजर्स भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आपदा काल में अस्पताल सबसे प्रमुख संरचना होते हैं, इसका आवश्यक अधिकतम सक्रियता समाज के बढ़ते हुए प्रवारक क्षमता के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभागियों को न्यूनीकरण के संरचनात्मक



चित्र 6.14: कार्यशाला के दौरान अस्पताल प्रशासन के प्रतिभागी

और गैर-संरचनात्मक भागों से जागरूक कराया गया जिसका अस्पताल के कार्यकारी या संरचनात्मक क्षति से बचाने के लिए देखभाल करने की आवश्यकता है। अन्य पहलुओं, जैसे— कर्मचारी की तैयारी, अस्पताल के भवन की बनावट तथा चिकित्सा उपकरण और संदर्भों की रक्षा का भी विवरण किया गया।

6.2.10. भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पर राष्ट्रीय स्तर की ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला (आईडीआरएन), 23 सितंबर 2014

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क(आईडीआरएन) पोर्टल के प्रोत्साहन का उत्तम संभावित तरीके से कार्यरत रहने जैसे, गतिक डाटा, जी आई एस मानचित्र, मोबाइल एप्लिकेशन इत्यादि के इनपुट प्राप्त करने के लिए एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला 23 सितंबर 2014 को एनआईडीएम परिसर नई दिल्ली में आयोजित की गई। एन डी आर एफ के निदेशक जनरल, श्री जी वि वि शर्मा, समयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र ने इस अवसर पर प्रतिनिधियों को संबोधित किया (चित्र 6.15)। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र ने प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और आई डी आर और आपदा के प्रबंधन में विशेष रूप से अपातकाल में इसकी प्रमुखता के बारे में बताया।



चित्र 6.15: कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, जेएस (डीएम), एमएचए, आईडीआरएन पर राष्ट्रीय स्तर के ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला में

डॉ शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि एनआईडीएम उपयोगकर्ताओं और हितधारकों से इनपुट की अपेक्षा करता है ताकि पोर्टल को उत्तम संभावित तरीके से तैयार किया जा सके। आपदा प्रबंधन के संयुक्त सचिव श्री जी वि वि शर्मा ने आपात काल के दौरान जीवन बचाने के लिए तथा मानव पीड़ा को कम करने के लिए आई डी आर एन के रख-रखाव और उपयोग में राज्य की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। बाद में उन्होंने सभा में सुझाव दिया कि एनआईडीएम को पोर्टल को उतना यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए जितना संभव हो सके और इसकी उपयोगिता को लोकप्रिय करना चाहिए।

एनआईडीएम की सहायक प्रोफेसर सुश्री श्रीजा एस नायर ने कार्यशाला के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के बारे में बताया। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के सचिव जनरल श्री ओ पी सिंह ने उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की और प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए तथा पीड़ितों के कष्ट को कम करने में हितधारकों के शामिल होने की प्रमुखता तथा सूचना प्रौद्योगिकी और घरेलू तकनीक की उपयोगिता को बताया। आई डी आर एन प्रोग्रामर सुश्री अनूपमा सेठी ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापन किया। राज्य/जिला प्राधिकार, आर्मी, एयर फोर्स, एन डी आर एफ, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, यूएनडीपी, एनजीओ इत्यादि से कुल इकतीस कर्मचारियों ने इस एकदिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला में भाग लिया (चित्र 6.16)।



चित्र 6.16: आई डी आर एन में राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी

सुश्री अनूपमा ने प्रतिभागियों को आईडीआरएन के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य तथा आईडीआरएन डाटाबेस के प्रगति के लिए रोड मैप के साथ-साथ अग्रिम कार्य वाले पोर्टल, जैसे जोयो कोडिंग, हिट मैप, तथा मोबाइल और ऑफलाइन एप्लिकेशन के विकास इत्यादि के बारे में बताया। प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत के साथ-साथ समूह में इनपुट देने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधियों ने आई डी आर एन के प्रयोग में अपने अनुभव को साझा किया और डाटाबेस को उन्नत बनाने, नये उपकरण शामिल करने, मानचित्र उपलब्ध कराने, ऑफलाइन एप्लिकेशन इत्यादि में इनपुट उपलब्ध कराया। कार्यशाला का अन्य मुख्य प्रतिवेदन है कि एनआईडीएम को कई स्तरों पर आई डी आर एन कार्यान्वयन के लिए एक दल बनाना चाहिए और निम्नतम संभावित प्रशासनिक स्तर पर तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए।

6.2.11. पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा-जोखिम विश्लेषण और योजना पर पूर्व-सम्मेलन कार्यशाला, 24 से 25 सितंबर 2014

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) सामुदायिक औषधि विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सहयोग से, सितंबर 24 से 25, सितंबर 2014 के दौरान एनआईडीएम में “पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा-जोखिम विश्लेषण और योजना” पर दो दिवसीय सम्मेलन पूर्व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया (चित्र 6.17)।



चित्र 6.17: पूर्व-सम्मेलन कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी

भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेज, सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के 51 प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया। आपदा प्रबंधन, स्थानिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य जैसे- आपदाओं का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संरचना और वर्तमान परिदृश्य, औद्योगिक आपदाओं और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आपदा काल में भोजन की न्यूनतम मात्रा, घटना/महामारी का आपदा पश्य प्रबंधन, शरण संबंधी मुद्दे और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को उजागर किया गया। कार्यशाला द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर चलाई गई थी जो नई दिल्ली में सितंबर 26 से 28, 2014, को आयोजित की गई थी।

6.2.12. “वन अग्नि न्यूनीकरण और प्रबंधन” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13 से 17 अक्टूबर, 2014

एनआईडीएम ने वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) के सहयोग से “वन अग्नि न्यूनीकरण और प्रबंधन” पर एफ आर आई देहरादून में 13 से 17 अक्टूबर, 2014 को एक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एफ आर आई के कार्यकारी निदेशक, डॉ आर के आइमा, आई एफ एस ने किया (चित्र 6.18)।



चित्र 6.18: डॉ आर के आइमा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

सिल्वीकल्चर विभाग देहरादून के अध्यक्ष श्री कुनाल सत्यार्थी, आई एफ एस; एन आई डी एम, नई दिल्ली के वरिष्ठ संकाय डॉ ए डी कौषिक और एफ आर आई देहरादून के रिसर्च अधिकारी, श्री वी के धवन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के विभिन्न राज्यों के कई प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

6.2.13. "विकास नीति और अभ्यास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन" पर सम्मेलन, 20 अक्टूबर 2014

उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकार (यूपी-इसडीएमए), लखनऊ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), नई दिल्ली के सहयोग से गोरखपुर पर्यावरणीय कार्य समूह (जीइएजी), गोरखपुर, और सामाजिक तथा वातावरण समस्थान (आईएसईटी), यूएसए ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और विकास नीतियों और अभ्यासों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर एक एकदिवसीय सम्मेलन ताज के होटल विवांता, लखनऊ में 20 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने सरकार, यू एन एजेंसी, दाताओं और अकादमियों के लगभग 150 नीति-निर्माताओं और अभ्यासकर्ताओं को एक साथ लाया। यू पी सरकार के मुख्य सचिव, श्री सुरेश चंद्र; यू पी सरकार के सचिव और बचाव आयुक्त, श्रीमती लीन जौहरी; यू पी सरकार के कृषि उत्पाद आयुक्त, श्री वी एन गर्ग; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नीति और योजना के अध्यक्ष, डॉ अनिल के गुप्ता; लखनऊ युनिसेफ के राज्य प्रमुख, गी ओ एल सुश्री निलोफर पोरजाण्डे; अखिल भारतीय न्यूनीकरण संस्थान (एआईडीएमआई) के निदेशक, श्री मिहि भट्ट, और जी इ ए जी के अध्यक्ष, डॉ सिराज ए वाजिह मंच पर उच्चाधिकारियों में से थे (चित्र 6.19)। उद्घाटन समारोह के बाद तीन मुख्य विचारणीय मुद्दों पर बातचीत हुई: (क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: परिकल्पना और अंतर्दृष्टि; (ख) आपदा और जलवायु जोखिमों की चुनौतियों को संबोधित करने पर प्रायोगिक अनुभव; (ग) आपदा और जलवायु जोखिम

न्यूनीकरण को समर्थ करना: स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर नीति, कार्यक्रम, और संस्थान। प्रायोगिक पहुँच और अनुसंधान तथा नीति भाषण से पाठों को संपूरक बनाया गया और सी सी ए और डी आर आर को विकास नीति और योजना के मुख्य धारा में लाने में चुनौतियों पर चर्चा की गई। सम्मेलन की समाप्ति "डी आर आर और सी सी ए को मुख्य धारा में लाने के लिए लखनऊ घोषणपत्र" के साथ हुई— हाल ही के विकास को देखते हुए उत्तर प्रदेश में डी आर आर और सी सी ए को मुख्य धारा में लाने के लिए एक रोड मैप और मुख्य अनुमोदन तैयार किया गया।



चित्र 6.19: उद्घाटन समारोह के दौरान मंच पर उपस्थित पदाधिकारी गण

6.2.14. "भारत आपदा बचाव नेटवर्क" पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी (यूपीएएएम) में आयोजित, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 27 से 28 अक्टूबर 2014

"भारत आपदा बचाव नेटवर्क" पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 27 से 28 अक्टूबर 2014 तक उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी (यूपीएएएम), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बचाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश की सुश्री लीना जौहरी द्वारा किया गया। यूपीएएएम के निदेशक जनरल श्री नेत राम; यूपीएएएम के अतिरिक्त सचिव सुश्री शीतल वर्मा; यूपीएएएम के संयुक्त निदेशक, डॉ राकेश वर्मा ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। राज्य के 32 जिलों से तैंतीस प्रतिभागियों (राष्ट्रीय इंफोर्मेटिक्स केन्द्र और

जिला प्रशासन के कर्मचारी) ने पाठ्यक्रम में भाग लिया (चित्र 6.20)। कर्मचारियों को आई डी आर एन पोर्टल, इसके उपयोग, कार्य गति और प्रशासन से परिचित कराया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को आई डी आर एन पोर्टल, यूजर लॉग-इन, डाटा अपलोडिंग, विभिन्न फॉरमेट, डाटा एक्सेसिंग इत्यादि की जानकारी देने के लिए एक तत्काल सत्र आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने आई डी आर एन से संबंधित अपने अनुभवों और विशिष्ट चुनौतियों को साझा किया। विभिन्न आपदा परिदृश्यों को प्रबंधित करने के लिए समूह अभ्यास का आयोजन भी किया गया। प्रतिभागियों द्वारा आई डी आर एन की उपयोगिता को निर्विरोध सहमति दी गई। प्रतिभागियों ने संबंधित जिलों के आंकड़ों को अद्यतन करने की सहमति दी और एनआईडीएम से आवश्यक तकनीकी / प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध काराने का आग्रह किया। तकनीकी, मुद्दे, पोर्टल प्रशासन, डाटा संग्रह तथा डाटा प्रविष्टि इत्यादि से संबंधित समूह से प्राप्त फीडबैक और सुझाव का प्रयोग पोर्टल को आगे अपग्रेड करने में किया जाएगा।



चित्र 6.20: एनआईडीएम संकाय सदस्य पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

6.2.15. राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान उद्यान के कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण, 21 नवंबर 2014

राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान उद्यान (एनजेडपी), दिल्ली के कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईडीएम में 21 नवंबर, 2014 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनजेडपी के लगभग 35 कर्मचारी सदस्य उपस्थित थे।

कार्यक्रम के उद्देश्य में आपदा को प्रतिबंधित करना तथा आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। एनआईडीएम के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर कर्मचारी सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। सत्र का उद्घाटन एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र और एन जेड पी दिल्ली के निदेशक, श्री अमिताभ अग्निहोत्री की उपस्थिति में किया गया (चित्र 6.21)। अनुभव साझा सत्र के दौरान, चेतावनी और संचार प्रणाली की संस्थापन, प्रशिक्षित कर्मचारी का परिक्रमण, और त्वरित अनुक्रिया दल का गठन, भगदड़ से रोक की रणनीति, आगंतुकों द्वारा वर्तमान संसाधनों के उचित उपयोग पर जागरूकता और सामान्य भावी जोखिम के प्रबंधन इत्यादि पर चर्चा हुई। एनआईडीएम के डॉ सौरभ दलाल और पी ची एच के वरिष्ठ पारामेडिक अनुदेशक, श्री नितेश कुमार द्वारा मूल जीवन सहायता तथा प्राथमिक उपचार पर तत्काल अभ्यास के साथ विस्तृत प्रशिक्षण सत्र आयोजित की गई। चूँकि, एनआईडीएम चिड़ीयाघर के लिए आपदा प्रबंधन योजना के विकास में गये थे, यह प्रशिक्षण उस प्रक्रिया का एक भाग था और विशेषज्ञों द्वारा आगे ब्रेनस्टोर्मिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा।



चित्र 6.21: कार्यक्रम के दौरान श्री अमिताभ अग्निहोत्री, निदेशक, एनजेडपी, दिल्ली एनआईडीएम दल के साथ

6.2.16. प्राणिविज्ञान उद्यानों के लिए मॉडल आपदा प्रबंधन योजना के कार्य योजना विकास हेतु ब्रेनस्टोर्मिंग सत्र, 19 दिसंबर 2014

प्राणिविज्ञान उद्यानों के लिए मॉडल आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) के कार्य योजना विकास हेतु

एनआईडीएम द्वारा शुक्रवार, ग्यारह बजे, 19 दिसंबर 2014 को एनआईडीएम, नई दिल्ली के सभा भवन में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का आयोजन किया गया था।

सत्र की अध्यक्षता एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक ने की और एमओइएफ, एनडीएमए, केन्द्रीय जू प्राधिकरण, आईआईपीए, राष्ट्रीय जैविक उद्यान, एमिटी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, विश्व पशु संरक्षण और एनआईडीएमके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

चर्चा के दौरान, कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये। इसमें जू में कार्य योजना की आवश्यकता वाली सभी संभावित परिस्थिति की सूची बनाना और तदनुसार कार्य कारना; जू के संपूर्ण प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन प्रविधि तैयार करना; मॉडल डी एम पी को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों की पहचान तथा उसे शामिल करना; रिक्तिकरण योजना की तैयारी, सामर्थ्य निर्माण; और आपातकाल से निपटने हेतु नियमित बनावटी ड्रिल और लगातार प्रशिक्षण का आयोजन इत्यादि शामिल थे। एनआईडीएम राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उद्यान के लिए आपदा प्रबंधन योजना पर एक मॉड्यूल तैयार करने के पक्ष में है।

6.2.17. घटना अनुक्रिया प्रणाली पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम "योजना अनुभाग प्रमुख", एनआईडीएम, 12 - 16 जनवरी 2015

घटना अनुक्रिया प्रणाली "अनुभाग प्रमुख योजना" पर एनआईडीएम ने 12 से 16 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोआ, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे राज्यों के पंद्रह प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया (चित्र 6.22)। विभिन्न लाइन के अधिकारियों ने भी इस टी ओ टी पाठ्यक्रम में भाग लिया, जैसे— सचिव— आपदा प्रबंधन, निदेशक— आपदा प्रबंधन, पुलिस के डी आई जी, सहायक डिविजनल अधिकारी— अग्नि और बचाव

सेवा; अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, आई जी पुलिस, सहायक कमांडेंट, पुलिस अधीक्षक, इत्यादि।

पाठ्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य आईआरएस पर विस्तृत जानकारी देना, एकीकृत नियोजन अनुभागों के पाँच उप-मॉडल पर अभ्यास के साथ ट्रेनिंग देना था। ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के आपदा के दौरान अपातकालीन अनुक्रिया प्रबंधन और योजना में आई आर एस की महत्ता को संबोधित किया गया।

6.2.18. डीआरआर के लिए दीर्घावधि प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण रणनीति पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र : एनसीआरएमपी, एनआईडीएम के भाग 'सी' के अंतर्गत, 20 जनवरी 2015



चित्र 6.22: आईआरएस "अनुभाग मुख्य योजना" पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समूह फोटोग्राफ

एनआईडीएम ने डीआरआर के लिए दीर्घावधि प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण रणनीति पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र : एनसीआरएमपी, एनआईडीएम के भाग 'सी' के अंतर्गत, अध्ययन को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। अध्ययन की उपलब्धियाँ, जैसे— प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रत्यायन कार्यक्रम इत्यादि को एनसीआरएमपी के अगले चरण में कार्यान्वयित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक परियोजना बैठक एनआईडीएम में 20 जनवरी 2015 को किया गया जहाँ अध्ययन के सभी आउटपुट को साझा किया गया और इससे

आगे का कार्य को अनुमोदित किया गया तथा उस पर चर्चा किया गया।

आगे, विमोचन 3 का मसौदा प्रतिवेदन— वर्तमान पी डी एन ए प्रविधि का विश्लेषण और प्रलेखन संबंधी प्रतिवेदन जिसे चूने गये दस राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रविधियों की तुलना में पर्याप्त और अटना अध्ययन की समीक्षा, भारत के लिए आपदा पश्च मूल्यांकन आवश्यकता अध्ययन के अंतर्गत (राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना का एक भाग— एनसीआरएमपी), को सुपुर्द कर दिया गया है।

6.2.19. "भारत आपदा संसाधन नेटवर्क" पर केन्द्र शासित प्रदेश लक्षदीप में, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कावारत्ती, द्वीप पर आयोजित, राज्य स्तर प्रशिक्षण, 30 जनवरी, 2015

"भारत आपदा संसाधन नेटवर्क" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र शासित प्रदेश लक्षदीप के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कावारत्ती द्वीप में 30 जनवरी 2015 को आयोजित किया गया (चित्र 6.23)। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन, लक्षदीप के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्री वदोदरिया करणजीत ने किया। केन्द्र शासित प्रदेश के छः द्वीप के बीस प्रतिभागियों (राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक केन्द्र और जिला प्रशासन के कर्मचारियों) ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। कर्मचारियों को आईडीआरएन पोर्टल, इसके उपयोग, यूजर लॉग-इन, डाटा अपलोडिंग, विभिन्न फॉरमेट, डाटा एक्सेसिंग इत्यादि के बारे में परिचित कराया गया। प्रतिभागियों द्वारा आई डी आर एन की उपयोगिता को निर्विरोध स्वीकार किया गया। प्रतिभागी संबंधित द्वीपों के डाटा अपलोड करने के लिए सहमत हो गए और एनआईडीएम से आवश्यक तकनीकी/प्रशासनिक सहयोग तथा अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश के दस द्वीपों के लिए यूजरनेम और पासवर्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया।



चित्र 6.23: संकाय सदस्य एनआईडीएम, प्रशिक्षण के दौरान आईडीआरएन पोर्टल की व्याख्या करते हुए

6.2.20. "जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में वन्य जीवन जीविका के रूप में" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, एफआरआई, देहरादून, 9 से 13 फरवरी 2015

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एक पाँच दिवसीय कार्यक्रम "जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के रूप में वन्य जीवन जीविका" एफ आर आई देहरादून का आयोजन 9 से 13 फरवरी 2015 को किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन, एफआरआई के आईएफएस निदेशक, डॉ पी पी भोजवैद ने किया। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के सिविकल्चर विभाग के प्रमुख श्री कुनाल सत्यार्थी; वरिष्ठ संकाय डॉ ए डी कौशिक; एनआईडीएम की सहायक प्रोफेसर श्रीमती चंद्रानी बंदोपाध्याय और वैज्ञानिक 'सी' श्री वी पी सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया। देश के विभिन्न राज्यों के कुल तेरह प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण विभिन्न वन्य जीवन के उभरते मुद्दे पर केन्द्रित था, जो जीविका, आपदा तैयारी और जलवायु के परिवर्तित परिदृश्य, जंगल आग के बढ़ती घटना, हमलावर प्रजाति, कीड़े-मकोड़े के प्रादुर्भाव और अन्य जंगली आपदाओं में न्यूनीकरण रणनीति से संबंधित थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिये गये अधिकांश भाषणों ने प्रतिभागियों को काफी प्रभावित किया। वन आधारित जीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए प्रतिभागियों को एक दिन का क्षेत्र दौरा पर कालेसर (हरियाणा) भेजा गया। प्रतिभागियों द्वारा क्षेत्र अनुभव की काफी सराहना की

गई। प्रशिक्षण के अंत में एफ आर आई देहरादून डिम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति आई एफ एस डॉ नीलू गेरा ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किया।

6.2.21. एन सी आर एम पी और आई आर एस के अंतर्गत, गांधीनगर, गुजरात में "भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घवधि प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण रणनीति तैयार करना" पर परामर्श कार्यशाला, 12-13 फरबरी 2015

भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एनडीएमए और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (जीएसडीएमए), के साथ राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाएँ (सीआरएमपी) के अंतर्गत भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श 12 से 13 फरबरी 2015 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया (चित्र 6.24)।

एनडीएमए के सचिव ने राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन किया और राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए किये जाने वाले सभी पहल पर पूर्ण सहयोग देने का वादा किया किया। दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का केन्द्र बिन्दु इस परियोजना के अंतर्गत विकसित टीओटी मॉड्यूल को अंतिम रूप देने पर था, जिसने पाँच प्रमुख खण्डों को लाभ पहुँचाता है, नामतः स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मीडिया और सूचना। घटना अनुक्रिया प्रणाली (आईआरएस) के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और आगे की कार्यवाही पर चर्चा भी की गईगया। कार्यशाला में सरकारी कार्यकर्ताओं और विभिन्न राज्यों के इन सभी विभागों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसकी समाप्ति चर्चा पर आधारित कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा दिये

गये इनपुट को समेकित कर और संबंधित राज्यों में इन प्रशिक्षण को चलाने संबंधी ड्राफ्ट योजना के साथ किया गया।



चित्र 6.24: उद्घाटन सत्र के दौरान बातचीत करते हुए प्रतिनिधि एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर संतोश कुमार, और एसडीएमसी के निदेशक ने एनआईडीएम के दल का नेतृत्व किया। सभी की उपस्थिति तथा सहयोग द्वारा परामर्श सत्र में प्राप्त उद्देश्य के लिए परियोजना समन्वयक एन सी आर एम पी, एनआईडीएम डॉ के जे अनंदा कुमार के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यशाला की समाप्ति हुई।

6.2.22. "अस्पताल आपदा प्रबंधन योजनाओं पर टीओटी कार्यक्रम: आपातकाल स्वास्थ्य सेवाओं पर केन्द्रित", 16 से 20 फरबरी 2015

"अस्पताल आपदा प्रबंधन कार्यक्रम" पर एनसीआरएमपी परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल पर आधारित एक पाँच दिवसीय टीओटी कार्यक्रम का एनआईडीएम में 16 से 20 फरबरी 2015 की अवधि में आयोजित की गई। भारत तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल और राष्ट्रीय नागरिक रक्षा कॉलेज के विभिन्न प्रमुख चिकित्सा संस्थानों से वरिष्ठ स्तर के डॉक्टरों/प्रकाशकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया (चित्र 6.25)।

स्वच्छ परिप्रेक्ष्य में अस्पताल आपदा योजना की तैयारी के लिए एक विस्तृत ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। एन सी आर एम पी के परियोजना समन्वयक और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ के जे अनंघा कुमार पाठ्यक्रम निदेशक थे और इन्होंने अपने भाषण द्वारा विभिन्न स्तरों पर आपदा के दौरान अस्पताल की प्रमुखता, सामर्थ्य निर्माण और बनावटी ड्रिल और योजना तैयार करने की वास्तविक विधि की आवश्यकता को उजागर किया। अन्य संकायों ने भी अस्पताल के लिए संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण उपायों तथा पिछले आपदाओं से स्वास्थ्य विभागों पर केन्द्रित सुधारों को साझा किया। चौथे दिन जे एन एपेक्स ट्राउमा केन्द्र का क्षेत्र दौरा भी कार्यक्रम का एक भाग था, जिसमें देश के प्रमुख ट्राउमा केन्द्र द्वारा प्रतिदिन बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की आंतरिक तैयारी की जाती है।



चित्र 6.25: कार्यक्रम प्रतिभागी और एनआईडीएम संकाय

सामूहिक क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में प्रतिभागी ने भी स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर अस्पताल आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार किया और उसे प्रस्तुत किया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक और एस डी एम सी के निदेशक, प्रोफेसर संतोश कुमार ने प्रतिभागियों के साथ परिचय किया और विदाई सत्र में भाग लिया और प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल

का प्रयोग देश के अन्य भागों में इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया।

6.2.23. मिजोरम सचिवालय सेवा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण, 18 फरवरी 2015

मिजोरम सचिवालय सेवा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए एक अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) नई दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन (आईएसटीएम) के आग्रह पर 18 फरवरी 2015 के पूर्वाह्न में किया गया।

सचिवालय के विभिन्न विभागों के तेइस प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर संतोश कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एनआईडीएम के क्रियाकलापों के परिचय के साथ उद्घाटन भाषण दिया। जानकारी प्रबंधन और संचार विभाग के प्रमुख डॉ सूर्यप्रकाश ने राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियमों और नीतियों की सूचना को साझा किया, तथा एनआईडीएम के आदेशों को भी विवेचित किया। इसके बाद कनिष्ठ सलाहकार, सुश्री बलजिंदर कौर का अपातकालीन संचालन केन्द्र (इओसी) के बारे में प्रस्तुतीकरण हुआ। कनिष्ठ सलाहकार श्रीमती अनूपमा सेठी ने भी प्रतिभागियों को भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल (आईडीआरएन) के बारे में परिचय दिया। कार्यक्रम के अंत में एनआईडीएम संकाय और सलाहकारों ने मिजोरम राज्य की असुरक्षा के बारे में प्रतिभागियों से प्रश्न किया और तैयारी तथा न्यूनीकरण के चरणों का सुझाव दिया। कार्यशाला का समापन दोनों और से धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

6.2.24. एनसीआरएमपी के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण और प्रत्यायन हेतु आपदा प्रबंधन नीति पर कार्यशाला, 3 मार्च, 2015

राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण नीति, प्रत्यायन नीति और उत्कृष्ट केन्द्र पर परामर्श सभी वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन के साथ हुआ था। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) के परियोजना समन्वयक, डॉ के जे अनंदा कुमार ने आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रशिक्षण, सामर्थ्य निर्माण नीति और प्रत्यायन नीति पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण नीति ने प्रशिक्षण कार्यान्वयन, प्रशिक्षण तक समुचित पहुँच, सामर्थ्य निर्माण विज्ञान, सामर्थ्य निर्माण उद्देश्यों, प्रशिक्षण उद्देश्य और लक्ष्य के लिए रणनीतिक ढाँचा का निर्माण करती है। प्रत्यायन नीति पर प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अनुसंधान और शिक्षा की स्थिति, प्रत्यायन विधि और अवस्था, गुणवत्ता प्रधान प्तबंधन की विधि इत्यादि आता है। इसके अंतर्गत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के टिप्पणी (एनडीएमए), झारखंड सरकार, केरल सरकार और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान भी आता है।

आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण नीति और प्रत्यायन नीति के कार्यान्वयन का संपूर्ण सहमति है। इसके संरचना और कार्यक्रम का माध्यम के ऊपर ऐसे और परामर्श में कार्य करना है जिसमें सभी नीति निर्माताओं और अकादमिसियनों को शामिल करना है। अठारह राज्यों के प्रतिनिधि जिसमें, बिहार एसडीएमए के उपाध्यक्ष श्री अनिल सिन्हा, उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त जी एसडीएमए, के सी इ ओ सुश्री लीना जोहरी शामिल थे, चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनिक भागों के नीतियों के लिए अनुमोदन

दिया तथा इसके कार्यान्वयन रणनीति का भी सुझाव दिया। (चित्र 6.26)



चित्र 6.26: कार्यशाला के दौरान अपना अनुभव साझा करते हुए प्रतिनिधि

6.3. अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एनआईडीएम

6.3.1. एशिया में मजबूत आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणाली निर्माण संबंधी नीति के विचार-विमर्श में चेंगडु, चीन में एनआईडीएम की प्रतिभागिता, 10 से 12 जून 2014

एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई), जापान और आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण संस्थान (आईडीएमआर), चेंगडु, चीन ने संयुक्त रूप से "एशिया में मजबूत आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणाली" पर 10 से 12 जून 2014 तक चेंगडु, चीन में एक नीति विचार-विमर्श आयोजित किया। इन देशों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित प्रणालियों को समझने के लिए 15 अलग-अलग देशों से लगभग 25 प्रतिभागी को इसमें भाग लेने और अपना अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किये गये थे। इनमें से हाल के आपदाओं, सिचुआन भूकंप 2008, फाईलिन चक्रवात 2013 और हैयान टाइफून 2013 को शामिल किया गया।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनआईडीएम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सूर्यप्रकाश को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित किया (चित्र 6.27)। कार्यक्रम



चित्र 6.27: भूकंप प्रभावित स्थल के दौरे पर गये और एशिया में मजबूत डीआरएम प्रणाली संबंधी नीति चर्चा में भाग लिए प्रतिभागियों का एक समूह फोटो

के दौरान वेंचुवान भूकंप प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया (12 मई 2008 को) इसके साथ-साथ बेचुवान काउंटी के भूकंप प्रभावित समुदायों के पुनर्मिर्माण स्थल का भी दौरा किया गया। आपदा निवारण तथा शिक्षा केन्द्र, चीन द्वारा स्थापित 5.12 वेंचुआन भूकंप स्मारक संग्रहालय का दौरा उसके लिए आँख खोलनेवाला था, जिसने किसी मुख्य भूकंप के नहीं देखा है। संग्रहालय भूकंप क्षतिग्रस्त चीजों का संग्रह स्थल है और इसमें वह उपकरण भी रखा है जो आपदा के बाद बचाव या राहत कार्य में खोजने के लिए प्रयोग किया गया था। इसमें बाद में चीनियों द्वारा किये गये कार्यों का विडियो के साथ-साथ सरकारी समुदाय और स्वयं सेवकों द्वारा किये गये कार्य की एकता भी दिखाया गया है। लोगों को भूकंप तथा इसके प्रभाव से जागूक करने के लिए स्मारक संग्रहालय से सटे एक भूकंप विज्ञान शिक्षा केन्द्र भी स्थापित की गई है डॉ. सूर्य प्रकाश ने नीति चर्चा के समय भारत में डी आर एम प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिवेदन के साथ-साथ चर्चा से निकले मुख्य मुद्दों को विचार-विमर्श के लिए रखा।

6.3.2. एएसइएम देशों के बीच आपदा राहत प्रयास के लिए तकनीकी नवीकरण पर गोलमेज सम्मेलन और काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वीकेपी) तथा इएस देशों के 24 x 7 पी ओ सी की बैठक, 4 से 5 दिसंबर 2014

एशियाई यूरोप (एएसइएम) देशों के बीच आपदा राहत प्रयास के लिए तकनीकी नवीकरण पर दो दिवसीय गोलमेज सम्मेलन और काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वीकेपी) तथा इ ए एस देशों के 24 x 7 पीओसी की बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा 4 और 5 दिसंबर 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री (गृह), श्री हरीभाई पारथीभाई चौधरी ने 4 दिसंबर 2014 को 9:30 बजे किया (चित्र 6.28)।



चित्र 6.28: माननीय राज्य मंत्री(गृह), श्री हरीभाई पारथीभाई चौधरी दो दिवसीय गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

श्रीमति स्नेहलता कुमार, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय; श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय; डॉ अरविंद प्रसाद, डायरेक्टर जनरल, फिक्की ने कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को सुशोभित किया। इस सम्मेलन में एशिया-यूरोप मितिग (एएसइएम) और पूर्व एशिया सम्मेलन (इएस), यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों, और दक्षिण पूर्व एशियाई संघ (एशियन) सचिवालय के 26

प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त दस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागिता जैसे— एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र (एडीपीसी), आपदा प्रबंधन तथा अपातकालीन राहत के लिए अंतरिक्ष आधारित संयुक्त राष्ट्र मंच(यू एन-सपाइडर), संयुक्त राष्ट्र बाल अपातकालीन फंड (युनिसेफ), एशिया और पेरिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (युनेस्कोप), सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र (एसडीपीसी), युरोपियन संघ मानव सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग (इसीएचओ) और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, सशस्त्र बलों, राज्य सरकारों और भारत के तकनीकी संगठनों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। 360 से अधिक प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

काल्पनिक जानकारी पोर्टल (वीकेपी), प्राकृतिक आपदा जोखिम मूल्यांकन, न्यूनीकरण, और इएएस देशों के बीच अनुक्रिया को साझा करने वाला एक वेब आधारित उपकरण का शुभारंभ राज्य मंत्री (गृह), श्री हरीभाई पारथीभाई चौधरी द्वारा उद्घाटन सत्र के दौरान किया गया।

“आपदा राहत प्रयास के लिए तकनीकी का नवीकरण” पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय व्यवसाय चौम्बर्स संघ (फिक्की) द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन भी राज्य मंत्री (गृह), श्री पारथीभाई चौधरी ने किया। इस प्रदर्शनी में 40 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों ने भाग लिया।

इस गोलमेज सम्मेलन में आपदा राहत प्रयासों के लिए तकनीकियों के नवीकरण के विषय में एएसडिएम देशों के बीच विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों में आपदाओं की स्थिति में सीमापार सहायता के लिए बहुपक्षीय अवसरों के बारे में भी चर्चा हुई

और इएएस देशों से 24 x 7 संपर्क स्थापित करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया गया और इस बात पर भी चर्चा की गई कि तकनीकी नवीकरण का जीवन रक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जाए तथा सरकारों द्वारा अनुक्रिया समय को किस प्रकार कम किया जाए।

6.3.3 जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सेंदाई, जापान, 14 - 18 मार्च 2015

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जापान के मियाउ प्रिफ्रेक्चर के सेंदाई शहर में 14 से 18 मार्च 2015 को हुआ। कार्यक्रम में विश्व भर के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय या राष्ट्रीय रणनीतियों/ संस्थानों से प्राप्त अनुभवों को साझा करने के लिए भाग लिया और विश्वभर में आपदा से जीवन और संपत्ति की हानि को कम करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजना बनाई। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रिम संस्थानों में एक, एनआईडीएम, ने भी सम्मेलन में भाग लिया। महामहिम श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे यूएन विश्व सम्मेलन में अपना वक्तव्य दिया (चित्र 6.29)।



चित्र 6.29: श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, तीसरे डब्ल्यूसीडीआर में अपना राष्ट्र वक्तव्य देते हुए

महामहिम श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिया गया देश का वक्तव्य:

“आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक भाग के रूप में हमें बहुत खुशी मिल रही है। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से मैं संयुक्त राष्ट्र तथा आतिथ्य देश, जापान सरकार को, कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ।

कार्य का हगोगो ढाँचा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्रियाकलाप का एक कच्चा चित्र उपलब्ध कराया है, इसमें बचाव की संस्कृति का प्रोन्नयन, न्यूनीकरण, तैयारी और सभी स्तर पर लचीलापन शामिल है। तब से, संसाधन खर्च करने में विचारणीय प्रगति हुई है और आपदाओं से निपटने के लिए सामर्थ्य में भी वृद्धि की गई है। फिर भी भविष्य में काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

एनआईडीएम ने हाल ही की प्रगति पर इको प्रणाली की पहुँच संबंधी नीति चर्चा में एक सत्र आयोजित किया था। सत्र 15 मार्च को सेंटाई प्रदर्शनी शहर में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित की गई थी:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इको-संरचना पहुँच पर चर्चा।
- खण्ड में किये गये कार्य और पहल।
- इको-डीआरआर के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और जन नीति के लिए एकीकरण का स्थान

मुख्य वक्ता थे, भारत सरकार के पी एम ओ, डॉ पी के मिश्रा, यू एन एस्केप की सुश्री शमिखा सिरिमाने, यूनेप की सुश्री मेरिसोल एस्पेरेरेला, एपीडीआरआर के श्री मनु गुप्ता, एनडीएमए, भारत सरकार के श्री कमल किशोर, एनआईडीएम, भारत सरकार के प्रोफेसर संतोश कुमार। बहुत विचार-विमर्श के बाद, सत्र में जिस प्रमुख संदर्भ

पर जोर दिया गया, वह था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबोधन के लिए अभी भी देशों के बीच गंभीर खाई बची हुई है। दूसरे देशों में एनआईडीएम जैसे संस्थान के पास इस क्षमता की खाई को दूर करने के लिए विस्तृत रोड मैप होना चाहिए। ऐसे संस्थानों से देश में तथा देश के बाहर अनुभव को साझा किया जा सकता है। अंतः सरकारी क्षेत्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र और सिविल समाज के साथ साझेदारी का विकास, एक अच्छी पहल हो सकती है।

भारत में हाल की घटनाएँ जैसे, हिमालय राज्य उत्तराखंड का 2013 का भू-स्खलन और बाढ़, ओडिसा का 2013 का फाइलिन चक्रवात, जम्मू-काशीर का भू-स्खलन और बाढ़ और 2014 में आंध्र-प्रदेश का हुदहुद चक्रवात, एक बार फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर हमारे प्रयास को बढ़ाने की ओर केन्द्रित करता है। नगरों का गैर-नियोजित विकास और उचित अचसंरचना का अभाव भविष्य की मुख्य चुनौतियाँ हैं। जहाँ समुदायों, विशेषकर औरतों और बच्चे, जो इन घटना में बाहर आते हैं, इन नियमित घटनाओं को अपनाने की कोशिश करता है, आर्थिक और सामाजिक मूल्य साल दर साल बढ़ना जारी है।

भारत सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र का आतिथ्य करता है जो आपदा जोखिम को कम करने और सार्क देशों के बीच जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर संरचना को सही स्थान पर रखने की ओर कार्य करता है। सामुद्रिक सूचना सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र त्वरित सुनामी चेतावनी प्रणाली को संचालित करती है। यह वास्तविक सुनामी सूचना होती है जो न सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन के सभी तटीय देशों को लाभ पहुँचाती है। हमारा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल जो राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने में निपुण है, इन क्षेत्रों तथा इससे बाहे के आपदाओं को भी देखने का काम करते

हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विभिन्न भू-संपत्ति विशयक आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित करती है। हम आपनी निपुणता को साझा करने के लिए तथा अन्य देशों को आपदा अनुक्रिया और सामर्थ्य निर्माण में मदद करने के लिए उत्सुक हैं। हम एषिया प्रशांत क्षेत्र में सामर्थ्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 2015-संरचना के अंतर्गत शाश्वत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी निर्माण की ओर प्रयास करते हैं। विशिष्ट एजेंसी की भूमिका के अतिरिक्त, प्रकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम देशीय तकनीकी तथा समुदाय आधारित तकनीकी जानकारी की महत्ता की ओर ध्यान देना चाहूंगा।

मैं साझा करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सभी स्तरों पर विकास नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में रखा है। आपदाओं को निपटाने के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त उपायों को अपनाकर हम फाइलिन चक्रवात में ओडिसा राज्य में मानव जीवन की हानि को कम करते हुए 44 तक पहुँचने में सफल हुए हैं। यह 1999 में राज्य में आए सुपर चक्रवात जिसमें 8900 लोगों की मृत्यु हुई थी के ठीक विपरीत है। यह लगातार कमी, समुदाय सहित सामर्थ्य निर्माण उपायों के अतिरिक्त हमारे भविष्यवाणी प्रणाली में नियमित निवेश के कारण आ सकी है। इस अवधि में कई बहुउद्देशीय चक्रवात शरण बनाया गया है। चक्रवात फाइलिन के स्थल पर पहुँचने से पहले, एक मिलियन से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर लाया गया था।

हमारा वित्त आयोग, जो कि एक सांबैधानिक इकाई है, जो कर की राशी को संघ सरकार और राज्यों में बाँटती है, अपने हाल के प्रतिवेदन में, हमारे सभी राज्यों में जोखिम, संकट तथा असुरक्षा मूल्यांकन के लिए आगे आया है। यह इस बात को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख कदम होगा कि अतिरिक्त समय,

जोखिम न्यूनीकरण की धारणा हमारे विकास पर खर्च हम सहयोगी संघवाद को प्रोन्नत करते हैं तथा जमीनी स्तर के नजदीक रहते हुए अधिक शक्ति और संसाधनों का विकास करते हैं।

समाप्त करने से पहले, हम 2015-पश्च संरचना, इसके उद्देश्य और प्राथमिकता के सहयोग का वचन देते हैं। हम इस क्षेत्र के देशों के साथ कार्य करने के लिए बचनबद्ध हैं तथा इससे आगे आपदा के विरुद्ध, सहयोगी देश और समुदाय के निर्माण के लिए बचनबद्ध हैं। हम सभी सरकारी और निजी हस्तियों को विश्वसनीय और आधुनिक समर्थ प्रौद्योगिकी को साझा कर सामर्थ्य निर्माण और सांस्थानिक तथा नीति पर्यावरण को सभी स्तरों पर अपनाकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आएँ।

6.4. सम्मेलन/प्रतिनिधिमंडल

6.4.1. एनसीआरएमपी-पीडीएनए परियोजना के अंतर्गत योजना आयोग में सम्मेलन, 24 अप्रैल, 2014

योजना आयोग के सलाहकार, श्री तुहीन कांत पांडेय के साथ एक बैठक, 24 अप्रैल, 2014 को उनके कार्यालय में आपदा पश्च आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) के अध्ययन का कार्यान्वयन एनआईडीएम द्वारा किये जाने के संबंध में हुआ। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र; एनआईडीएम एनसीआरएमपी के परियोजना समन्वयक डॉ के जे आनंदा कुमार; और एनसीआरएमपी- परियोजना कार्यान्वयन इकाई से एनआईडीएम के विशेषज्ञ श्रीमती प्रियंका चौधरी बैठक में उपस्थित थे। अध्ययन का लक्ष्य और उद्देश्य, आने वाले महीने में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलाप के बारे में चर्चा की गई थी।

श्री टी के पांडेय द्वारा अध्ययन के बारे में कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये गए, ताकि और अधिक उपलब्धियाँ मिल सकें। उन्होंने इस अवसर पर इस अध्ययन का स्वागत किया और इसके विचारों की प्रशंसा की, उनके अनुसार यह सरकार में, योजना आयोग सहित निर्णयकर्ता के लिए कई स्तरों पर लाभदायक होगा।

6.4.2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण का छठा आसियान मंत्री स्तर का सम्मेलन, बैंकाक, थाइलैण्ड, 22 – 26 जून 2014

भारत सरकार ने छठी एएमसीडीआरआर, बैंकाक, जून 22 – 26, 2014 के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जिसमें माननीय राज्यमंत्री (गृह) श्री किरन रिजिजु (चित्र 6.30) के साथ-साथ भारत सरकार की सचिव (सीमा प्रबंधन) सुश्री स्नेहलता कुमार और एनआईडीएम के नीति नियोजन के प्रमुख डॉ अनिल गुप्ता शामिल थे।



चित्र 6.30: माननीय राज्य मंत्री (गृह) श्री किरन रिजिजु छठी एएमसीडीआरआर के उद्घाटन समारोह में

छठी एएमसीडीआरआर, बैंकाक, का आतिथ्य रॉयल थाई सरकार द्वारा यूएनआईएसडीआर के सहयोग से बैंकाक में किया गया। सम्मेलन देशों, संगठनों और वैयक्तिक अभ्यासकर्ताओं के मिलने तथा क्षेत्र में आपदा जोखिम

को कम करने के लिए चर्चा करने हेतु मिलन स्थाल था। यह ह्योगो संरचना कार्य 2005–15 के पूरा होने, जनवरी 2015 तथा मार्च 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे विश्व सम्मेलन सेंदई (जापान) से पहले एषिया में अंतिम क्षेत्रीय अंतर-सरकारी सम्मेलन था। छठी एएमसीडीआरआर, बैंकाक, के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एचएफए 2) के लिए 2015–पश्च संरचना हेतु एषिया–पेसिफिक इनपुट दस्तावेज,
- एषिया और पेसिफिक 2014 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर बैंकाक घोषणा, और
- एषियन हितधारक समूह का स्वैच्छिक वचनबद्धता कथन— बैंकाक घोषणापत्र में संलग्न

भारत के माननीय राज्यमंत्री (गृह) श्री किरन रिजिजु ने छठी एएमसीडीआरआर, बैंकाक, में उच्च स्तरीय गोलमेज 2 की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आपदा जोखिम को नियोजित तरीके से कम करने की भारत की बचनबद्धता व्यक्त की और इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों को साझा किया। मंत्री क्षेत्र में 41 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने भाग लिया। भारत के राष्ट्रीय भाषण में माननीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा लिये जा रहे पूर्व-रक्तिकरण कदमों को बताया जिसमें अक्टूबर 2013 में भारत के पूर्वी तट पर आए 'फाइलिन' चक्रवात से पहले एक मिलियन से अधिक लोगों को निकाला गया।

माननीय मंत्री ने सम्मेलन के पूर्ण सत्र 2— 'आपदा और जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए जन निवेश में बढ़ोतरी' की अध्यक्षता की। 'पूर्ण' के दौरान पैनल सदस्यों में चीन, अस्ट्रेलिया के मंत्री, और पाकिस्तान, जापान, तथा यूएन के प्रतिनिधि शामिल

थे। पैनल ने आपदा और जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन में सुधार पर जोर दिया और सभी निवेश योजना विधि में जोखिम आवश्यकता को शामिल करने हेतु अनुमोदन किया। भारत सरकार की सचिव (सीमा प्रबंधन) सुश्री स्नेह लता कुमार ने पूर्ण सत्र 1 में अपना वक्तव्य दिया और भारतीय सरकार के अनुभव परिदृश्य को प्रस्तुत किया। उन्होंने फिलिन चक्रवात, ओडिसा से पहले अधिकतम लोगों को हटाने के अनुभव को साझा किया और प्रभावी तथा शाश्वत आपदा-पश्च वापसी के और अधिक सुधार पर बल दिया। इस अवसर पर 24 जून 2014 को भारत और जापान के प्रतिनिधिमंडलों बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें जापानी सहयोगियों ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को डी आर आर पर विश्व सम्मेलन सेंडई 2015 के लिए आमंत्रित किया और आपसी सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। डॉ गुप्ता ने अकादमी और तकनीकी सहयोग पर अपना विचार दिया और संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम को प्रोन्नत करने, सामुदायिक सहयोग की ओर कार्य करने, वन्यीकरण जैसे परियोजना पर डी आर आर प्रभाग, प्राकृतिक संसाधनों और जीविका पर बल दिया। यूएनइपी के सहयोग से एनआईडीएम (आपदा प्रबंधन शाखा जेनेवा) द्वारा एक विशेष नीति भाषण का आयोजन 23 जून को किया गया, जिसमें “आपदा प्रबंधन में दीर्घ मुद्दे— हालिया प्रगति” पर ध्यान दिया गया और इसकी अध्यक्षता थाइलैंड में भारतीय राजदूत माननीय श्री हर्षवर्द्धन श्रींगला ने की। भारत सरकार की सचिव (सीमा प्रबंधन) सुश्री स्नेहलता कुमार ने सत्र की सह-अध्यक्षता की (चित्र 6.31)। कार्यक्रम का आयोजन एनआईडीएम के डॉ अनिल गुप्ता और यूएनइपी की सुश्री मेरिसोल इस्ट्रेला ने किया।



चित्र 6.31: एनआईडीएम द्वारा आयोजित विशेष नीति डायलॉग मुद्दे के दौरान, सुश्री स्नेहलता कुमार, सचिव (बीएम), जीओआई अन्य पदाधिकारियों के साथ

राजदूत माननीय श्री इंगला ने सुरक्षित और आपदा रहित विकास की ओर शाश्वतता एकीकरण में जोखिम के कारणों और इसे कम करने के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीविका, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य चुनौतियों के मुद्दे को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिकल्पना से अलग नहीं किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, इको-प्रणाली प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पुष्ठीकरण के समदर्भ में अच्छा कदम है। उन्होंने पर्यावरण के विकास और सुरक्षा के लिए इन दो क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ही अधिक समन्वयन की आवश्यकता बताया। श्री श्रींगला ने यू एन इ पी और एनआईडीएमकी इस दिशा में प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ‘शाश्वतता’ को सिर्फ मानव जीवन के लिए ही लंबी अवधि का जीवंत नहीं कहा बल्कि सभी जीवन रूपों को जिसमें अन्य पशुओं, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों, पौधों, और अन्य पारिस्थितिक तंत्र इत्यादि को इसमें शामिल किया।

यूएनइपी के कार्यक्रम निदेशक (डीएम शाखा जेनेवा) डॉ मुरली थुमारकुडि ने नये पहुँच, इको डीडीआर की यात्रा को साझा किया और जोर दिया कि कई देशों में ह्योगो संरचना कार्य बचा रह गया है, जो चौथी प्राथमिकता है, उन्होंने ‘आज के आपदा जोखिम के

कारण' को संबोधित करने पर बल दिया। उन्होंने एच एफ ए के अंतर्गत पर्यावरणीय मुद्दे को समेकित करने की ओर इशारा किया।

सुश्री मेरिसोल एस्ट्रेला ने विभिन्न देशों के मुद्दों और उदाहरणों को साझा किया, जैसे स्विटजरलैंड, फिलिपिंस, अफगानिस्तान, जापान इत्यादि। क्योटो विश्वविद्यालय, जापान के प्रोफेसर राजीव सॉव ने समुदायों के लिए पारिस्थितिकी आधारित आपदा लोच अनुकूलन पर वक्तव्य दिया। समेकित पर्वत विकास के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीआईएमओडी) से श्री हरि कृष्ण ने अधिकतम डी आर आर में भागीदारी विशेषकर प्रभावी समुदायों के पहाड़ी क्षेत्रों के औरतों के लिए के लिए सामर्थ्य निर्माण पर आह्वान किया। लगभग 40-45 प्रतिभागी ने संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे- संयुक्त राष्ट्र, एशियन आपदा तैयारी केन्द्र, सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र, भारत, नेपाल, थाइलैंड, कोरडैड इत्यादि, जिसने विस्तृत विचार-विमर्श में भाग लिया। सुश्री स्नेहलता कुमार, सचिव (सह-अध्यक्ष) ने अपने समापन भाषण में भारत के मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों को गिनाया, जहाँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की सुविधा नियुक्ति, भूमि प्रबंधन या जिला तथा स्थानीय स्तरों पर सामाजिक कल्याण कार्यों के रूप में प्रदान की गई है। डॉ अनिल गुप्ता ने भविष्य के कार्य के लिए घटनाओं के सारांश और अनुमोदन को प्रस्तुत किया।

एएमसीडीआर आर के दौरान मार्गरेटा वाल्सट्रोम, संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल के विशेष प्रतिनिधि के साथ माननीय मंत्री का आपदा प्रबंधन पर एक बैठक 24 जून को संपन्न हुई। इसमें सेंडाई के तीसरी दुनिया सम्मेलन की ओर तैयारी की वर्तमान स्थिति और भारत में डी आर आर के उभरते मुद्दे पर बातचीत हुई। सचिव(सीमा प्रबंधन) सुश्री स्नेह लता कुमार और डॉ

अनिल गुप्ता एनआईडीएम ने बैंकॉक घोषणापत्र, एशिया और पसिफिक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण-2014 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पश्च-2015 के लिए एशिया-पसिफिक इनपुट दस्तावेज (एचएएफ2) के ड्राफ्टिंग समिति में भाग लिया।

एचएएफ 2 और बैंकाक घोषणापत्र का इनपुट भूत में अनुभव किये गये चुनौतियों के संबोधन की ओर केंद्रित रहा, जैसे- सहयोग, एकीकरण, स्थानीय योजना और लचीलापन, पारिस्थितिक तंत्र और जीवन सुरक्षा, सेवाओं को पहचानने, पारदर्शिता और क्षेत्रों में डी आर आर को मुख्य धारा में लाना। एक विशेष अतिथि के रूप में श्री अनिल गुप्ता ने 22 जून पूर्व सम्मेलन कार्यशाला में समुदाय, एशिया में आपदाओं से लचीलापन को मजबूत करने के लिए विश्वास आधारित और बहु-हितधारक सहयोग की आवश्यकता पर अपना वक्तव्य दिया। इसका आयोजन केरिटेस एशिया/ कोरडैड इंटरनेशनल इंडोनेशिया, म्यानामार, थाइलैंड, भारत और केफोड सी ने समुदाय की आवाज को पूरे एशिया में उनके आपदाओं से बचाव के प्रयासों को बताने, समुदाय की भूमिका को बताने जिसमें लचीलापन सशक्तिकरण पहुँच और भूमि आधारित योजना विधि में डी आर आर सूचना शामिल था, बताये गये समूह और देशीय/क्षेत्रीय लोगों के साफ भूमिका के लिए आयोजित किया था।

एशिया देशों के हितधारकों के सहयोग से डी आर आर को स्थानीय योजनाओं और कार्यों के लिए एकीकृत करने से एक साथ अनुभव और सीख लेने के लिए शाश्वत विकास की विस्तृत लक्ष्य की ओर छठी एएमसीडीआरआर के दौरान केरिटेस इंटरनेशनल और कोरडैड द्वारा 24 जून को एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी। गोरखपुर (यूपी) और तमिलनाडु/आंध्रप्रदेश में स्थानीय डी आर आर सामर्थ्य और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के अनुभवों को साझा करने के लिए डॉ अनिल कुमार को पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया।

छठी एमसीडी आर आर के दौरान, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिनिधि (सुश्री मेरिसोल एस्ट्रेला) ने माननीय राज्य मंत्री (गृह) को आगे की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग के विषय में बताया और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित “डी आर आर का इको-प्रणाली पहुँच” नामक पुस्तक भेंट की। यूएन-इस्केप और यूएन-स्पाइडर ने भी सामर्थ्य निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में पी डी एन ए, आपदा डाटाबेस और जोखिम मानचित्रण इत्यादि से संबंधित परिप्रेक्ष्य में आपसी सहयोग की इच्छा जताई। माननीय राज्यमंत्री (गृह) श्री किरें रिजिजु के सम्मान में 25 जून को बैंकाक में भारतीय दूतावास द्वारा एक स्वागत रात्रिभोज आयोजित किया गया।

6.4.3. रेड क्रॉस के अंतराष्ट्रीय समिति के सरकारी प्रतिनिधिमंडल (आईसीआरसी) ने एनआईडीएम का दौरा किया, 8 जुलाई 2014

आईसीआरसी के एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय अदालती विज्ञान विशेषज्ञ चेरि काजमारजेक-आईसीआरसी-भारत का सुरक्षा समन्वयक, मौजूद थे, ने 08-07-14 को एनआईडीएम का दौरा किया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र, मेजर जनरल डॉ वी के नायक और एनआईडीएम के डॉ सौरभ दलाल ने प्रतिनिधिमंडल का आतिथ्य किया (चित्र 6.32). प्राथमिक रूप से उठाये गये मुद्दे थे, आपदा पश्चात् परिवारिक सहयोग की पुनर्स्थापना तथा मृत शरीर का प्रबंधन तथा निपटान।

आईसीआरसी दल ने मृत शरीर के पहचान में अपने अनुभव तथा कमियों को साझा किया। डॉ सत्येन्द्र ने एनआईडीएम के भविष्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुभव के एकीकरण का प्रस्ताव रखा और भारत में वर्तमान विज्ञप्ति के बदले विषय को आगे लाने की आवश्यकता को अनुसंधान के आधार पर, उचित अभ्यास द्वारा तथा अंतराल की पहचान द्वारा उस पर जोर दिया।



चित्र 6.32: कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम, आईसीआरसी प्रतिनिधिमंडल के साथ

6.4.4. यूएसएआईडी प्रतिनिधिमंडल का दौरा, 22 जुलाई 2014

भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए यूएसए और भारत एक दशक से अधिक समय से साथ-साथ काम कर रहा है। इस सहयोग का अधिकांश यू एस अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के माध्यम से हुआ है। कुछ मुख्य सहयोग कार्यक्रमों में आपातकालीन अनुक्रिया बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम (पीइइआर), जलवायु भविष्यवाणी प्रणाली (सी एफ एस), जो एक भाग है आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना (डीएमएस) का, घटना कमान प्रणाली (आईसीएस) और जीओआई-यूएनडीपी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम यू एस ए आई डी का एक प्रतिनिधिमंडल ने आपदा प्रबंधन में यू एस-भारत सहयोग के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य सीखे गये चीजों के प्रलेखन के लिए तथा सहयोग की सफलता के लिए मुख्य मुद्दे की पहचान के संदर्भ में 22 जुलाई को एनआईडीएमका दौरा किया। यू एस ए आई डी का प्रतिनिधित्व दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सलाहकार सुश्री मीन निनका; आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना के भूतपूर्व परियोजना प्रबंधक सुश्री बालका डे और देश के संपर्काधिकारी, यू वन सेवा अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम इकाई के एस के श्री बाला सिंह ने किया।

प्रतिनिधिमंडल का आतिथ्य एनआईडीएममें डॉ सत्येन्द्र (इडी, एनआईडीएम), डॉ वी के नायक, श्री शेखर चतुर्वेदी और कर्नल पी के पाठक ने किया। एनआईडीएम ने घटना अनुक्रिया प्रणाली माड्युल को यूएसएआईडी के रणनीतिक साझेदारी में विकसित किया और आपदा प्रबंधन पेशेवरों के राष्ट्रीय स्तर के आई आर एस प्रशिक्षण में भाग लेना जारी रखा है। यूएसएआईडी प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के कार्यान्वयन में अपना अनुभव साझा किया और संयुक्त कार्यक्रम की सफलता पर जोर दिया। जमीनी स्तर पर आई आर एस की उपयोगिता और इसकी कार्यान्वयन पर अर्थपूर्ण फिडबैक प्राप्त करने के लिए एनआईडीएम में एक संयुक्त कार्यशाला पर बातचीत हुई। असम और गोआ जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने अनुभवों को साझा करना जहाँ आपदा प्रबंधन के लिए आई आर एस की आवश्यकता है, प्रगति पर है।

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को एनआईडीएम के कार्य के बारे में तथा सामर्थ्य निर्माण में तथा प्रशिक्षण में इसके वर्तमान पहल के बारे में बताया जिसमें भारत आपदा जानकारी नेटवर्क (आईडीकेएन) और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) शामिल था। यूएसएआईडी प्रतिनिधिमंडल ने एनआईडीएम के पूरे देश में आपदा प्रबंधन पर सामर्थ्य निर्माण की प्रशंसा की और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आने वाले समय की साझेदारी के लिए वे बहुत उत्सुक दिखे।

6.4.5 मॉरिशस रिपब्लिक और एएआरडीओ के सरकारी प्रतिनिधिमंडल का एनआईडीएम दौरा, 10 सितंबर 2014

नई दिल्ली में एफ्रो एशियन ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ), मॉरिशस उच्च आयोग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन केन्द्र (एनडीडीआरएमसी), मॉरिशस

के अधिकारियों ने 10 सितंबर 2014 को "आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन" पर विचार-विमर्श और बैठक के लिए एनआईडीएम का दौरा किया (चित्र 6.33). यह एक सूचना आदान-प्रदान बैठक थी और ए ए आर डी ओ देश, मॉरिशस और भारत में आपदा के सहयोग पर बातचीत पर केन्द्रित थी। चर्चा में प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय-वस्तु, दोनों देशों में आपदा प्रबंधन की स्थापना, प्रलेखन और नीति अनुसंधान इत्यादि शामिल था।

प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता महामहिम इंजिनियर वास्फी हसन इल श्रेहिन (सचिव जेनरल और मिशन प्रमुख, नई दिल्ली, भारत) ने की। अन्य सदस्यों में डॉ मनोज नरदेव सिंह, (सहायक सचिव जेनरल एएआरडीओ), श्री जोयकेर नायेक (उप उच्चायुक्त, मॉरिशस उच्च आयोग), सुश्री प्रेमा अपाडु (द्वितीय सचिव, मॉरिशस उच्च आयोग), श्री खेमराज सर्वेनसिंग (उप आयुक्त पुलिस और सचिव जेनरल एनडीआरएमसी, मॉरिशस), और श्री धर्मेन्द्र इल्लाया (पुलिस इंस्पेक्टर, एनडीआरएमसी, मॉरिशस) शामिल थे।



चित्र 6.33: दौरे के अवसर पर मॉरिशस रिपब्लिक और एएआरडीओ के प्रतिनिधिमंडल

डॉ सत्येन्द्र, कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और एएआरडीओ राष्ट्र की प्राकृतिक आपदा से असुरक्षा और ग्रामीण विकास की आवश्यकता को उद्घाटित किया, जिसका केन्द्र जोखिम न्यूनीकरण था। महामहिम इंजिनियर वास्फी हसन इल

श्रेहिन ने एनआईडीएम में अपने उद्घाटन भाषण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर एएआरडीओ की भूमिका का महत्त्व बताया।

डॉ अनिल कुमार गुप्ता, नीति प्रमुख, एनआईडीएम ने भारत आपदा जोखिम संरचना पर एक प्रस्तुतिकरण किया और अनुसंधान, प्रशिक्षण, सामर्थ्य निर्माण, प्रलेखन और प्रकाशन में एनआईडीएम की भूमिका को भी उद्घाटित किया। श्री धर्मेन्द्र इल्लया (पुलिस इंस्पेक्टर, एनडीआरएएमसी, मॉरिशस) ने मॉरिशस और एनडीडीआरएमसी की स्थापना पर प्रस्तुतिकरण दिया। इसके अतिरिक्त सामर्थ्य निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के सहयोग पर चर्चा भी किया गया। महामहिम इंजिनियर वास्फी हसन इल श्रेहिन ने एएआरडीओ के साथ संभावित सहयोग क्षेत्रों में सहयोग की बात भी उद्घाटित की। कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम ने प्रतिनिधिमंडल को चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में मॉरिशस के लिए तथा अन्य सदस्य देशों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

6.4.6. "भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दीर्घावधि प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण रणनीति के लिए" एनडीएमए में केन्द्रीय समीक्षा समिति बैठक, 29 दिसंबर 2014

"भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दीर्घावधि प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण रणनीति के लिए" समीक्षा हेतु एक केन्द्रीय समिति बैठक, एनडीएमए में 29 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण के भाग 'सी' के अंतर्गत संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एनडीएमए के सचिव श्री आर के जैन ने की।

प्रारंभ में, प्रोफेसर संतोष कुमार, कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम और एन सी आर एम पी के परियोजना निदेशक ने सभी प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया। इसके बाद एनआईडीएम ने सभी 17 कार्यों की उपलब्धि बताते हुए एक प्रस्तुतिकरण दिया। एनडीएमए के सचिव ने आपदा के कारण जोखिम को कम करने के लिए

दी गई सामग्रियों के उचित उपयोग की आवश्यकता, सभी हितधारकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर बल दिया जो को आपदा प्रबंधन तथा असुरक्षित समुदाय के कार्य में शामिल रहते हैं। यह सूचित किया गया है कि अब तक विकसित मॉड्यूल के साथ-साथ सभी सामग्रियाँ एनआईडीएम वेबसाइट www.nidm.gov.in पर उपलब्ध है और फिडबैक(यदि कोई हो) उपलब्ध कराने के लिए लिंक www.nidm.gov.in/ncrmp.asp है।

6.4.7. "सूखा प्रबंधन के लिए मैनुवल का संशोधन" पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक, 25 मार्च 2015

एनआईडीएम में श्री नरेन्द्र भूषण, आईएएस, संयुक्त सचिव, कृषि तथा सहयोग विभाग, कृषि मंत्रालय (एमओइ) की अध्यक्षता में; डी एम अधिनियम, 2005 के अनुसार कृषि मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सूखा आपदा प्रबंधन के विकास में सूखा प्रबंधन मैनुवल के संशोधन में अपनायी जाने वाली रणनीति और कार्य के विषय में चर्चा करने के लिए एनआईडीएम में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक आयोजित की गई (चित्र 6.34)। बैठक की शुरुवात में एनआईडीएम द्वारा कृषि मंत्रालय के लिए 2009 में तैयार किये गये 'सूखा प्रबंधन के लिए मैनुवल' की प्रशंसा की गई और इस मैनुवल को देश में राज्य स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।



चित्र 6.34: ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक के दौरान प्रतिनिधि

सभी प्रतिभागी मैनुवल को अध्ययन करने के विचार में थे, इनमें शामिल किये जाने वाले कुछ मुद्दे थे, सावधिक

असुरक्षा मूल्यांकन, सही मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए अग्रिम तकनीकी और पहुँच, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, डी आर आर और सी एस आर जैसे संदर्भों को शामिल करना, जल संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सूखा प्रतिरोधक फसल के प्रकार, सरलीकृत फसल बीमा प्रणाली, सामर्थ्य निर्माण और सांस्थानिक क्षमता में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आर के वाई योजना, राज्य सूखा मैनुवल की तैयारी, उनमें से कुछ थे।

मैनुवल को अद्यतन करने तथा अलग से राष्ट्रीय डी एम योजना तैयार करने के लिए पूर्ण सहमति थी। सूखा मैनुवल के लिए एक 'समीक्षा समिति' और एक 'कोर समूह', दोनों संयुक्त सचिव, एमओए की अध्यक्षता में, सदस्य सचिव के रूप में एनआईडीएम के कार्यकारी सचिव होगा, बनाने का निर्णय भी लिया गया, जो इन कार्यों को निर्दिष्ट समय के अंतर्गत पूरा करे।

बैठक में कृषि मंत्रालय, एनआरएससी, सीएजेडआरआई, आईएआरआई, एनआरएए, राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, एनआईडीएम और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में भाग लिया और सूखा मैनुवल के संशोधन में कई प्रतिवेदन भी दिये।

6.5. क्षेत्रीय सहयोग

6.5.1. सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना

सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र (एसडीएमसी) अक्टूबर 2006 से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली के परिसर में अस्तित्व में है। केन्द्र को सार्क के आठ सदस्य देशों, यथा: अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान भारत, मालदिव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, की सेवा का आदेश है। एन आई डी एम ने एस डी एम सी को दक्षिण एशिया में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए नीति सलाह और सामर्थ्य निर्माण सेवा उपलब्ध कर वित्तीय सहायता (100 प्रतिशत) और तकनीकी सहायता देना जारी रखा है।

6.6. अन्य क्रियाकलाप

6.6.1. एनआईडीएम ने चङ्गुहीन राहत संगठन स्कूल, नई दिल्ली के साथ दृष्टिहीन बच्चों के लिए भूकंप ड्रिल का आयोजन किया, 24 अप्रैल, 2014

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) ने दृष्टिहीन राहत समुदाय स्कूल, ओबेरॉय होटल नई दिल्ली के पास, इस स्कूल के कक्षा एक से दस तक के बच्चों के लिए एक जाँच भूकंप बनावटी ड्रिल का आयोजन किया। दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्कूल सुरक्षा की तैयारी और कार्य योजना के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम 24 अप्रैल 2014 को अध्ययन समय के बीच में अचानक आयोजित किया गया। एनआईडीएम ने स्कूल में पाये गये उत्कृष्ट स्तर की अनुक्रिया तैयारी की प्रशंसा की।

एनआईडीएम के डॉ सौरभ दलाल ने स्कूल में आपदा प्रबंधन की महत्ता पर स्कूल के अधिकारियों और शिक्षकों को भूकंप प्रतिरोधक स्कूल भवन पर और आपदा की स्थिति में आपातकालीन रिक्तिकरण योजना को कार्य में लाने संबंधी कार्य पर विशेष बल देकर सुग्राह्य किया। डीडीएमए की सुश्री नेहा सिवाच ने आपदा प्रबंधन और इसकी महत्ता के बारे में दृष्टिहीन बच्चों में जागरूकता सृजन करने के लिए स्कूल प्राधिकार द्वारा लिये जा रहे कदमों की प्रशंसा की। एनआईडीएम ने महाविपत्ति को समझने के लिए विशेष आवश्यकता वाले समाज के क्षेत्र को केन्द्र में रखने की आवश्यकता पर बल दिया, ड्रिल का आयोजन अनुसंधान पर आधारित आई इ सी सामग्रियाँ और उपकरणों के भाग के रूप में "ब्रेल" आपदा की स्थिति में दृष्टिहीन स्कूल के बच्चों के लिए "क्या करें और क्या नहीं करें" यह जानने के लिए किया गया था।

6.6.2. सीखे गये सबक और चुनौतियाँ 2014 कार्यशाला

में एनआईडीएम की भागीदारी, भुवनेश्वर, 29 – 30 अप्रैल 2014

‘फाइलिन’ चक्रवात और अकस्मात बाढ़ के बाद अद्वितीय अनुभव और बड़ी संख्या में शक्ति वापसी में असफल कार्य अवसर से सीखने के उद्देश्य से, ओडिसा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (ओ पी टी सी एल) ने ओडिसा सरकार के उर्जा विभाग के सहयोग से “2014 से आगे सीखे सबक और चुनौतियाँ” विषय पर 29 और 30 अप्रैल 2014 को भुवनेश्वर में दो दिनों के कार्यशाला का आयोजन किया (चित्र 6.35)। कार्यशाला में चक्रवात के पश्चात विद्युत पुनर्प्राप्ति के प्रयास में पाये गये अद्वितीय और आंतरिक अनुभवों को सभी हितधारकों को प्रतिबिंबित करने और बताने के लिए प्रायोगिक सीख मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया था ताकि राज्य में भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपदा का सामने करने वाला लोच विद्युत प्रणाली बहाल किया जा सके।



चित्र 6.35: ओडिसा में कार्यशाला के दौरान अधिकारी

राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और परामर्श समस्थान के जाने माने विशेषज्ञ जैसे— केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार, केन्द्रीय शक्ति अनुसंधान संस्थान, बंगलोर, एनआईडीएम, पीआरडीसी बंगलोर, टीईआरई नई दिल्ली, और एलएण्डटी के जानकार कार्यकर्ता, स्नेडर, एबीबी उपस्थित थे और इस अवसर का लाभ हालिया तरीके और तकनीकी, विद्युत प्रणाली के उत्तम अभ्यास को विभिन्न ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र में विस्तृत संदर्भ में साझा

करने में उठाया। गहराई में जाने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि तकनीक, प्रणाली और लोगों के एकीकरण के द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन अवसंरचना का विकास किया जाए।

दूसरे दिन, डॉ के जे अनंदा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम, ने चक्रवात से सीखे गये सबक को प्रस्तुत किया जिसने कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी पर संकट फैलाया था, और सामर्थ्य निर्माण में एनआईडीएम के विशेषज्ञों का लाभ लेने का सुझाव दिया। आगे प्रोफेसर कुमार ने एनसीआरएमपी-पीडीएनए अध्ययन के बारे में सूचित किया और ओडिसा राज्य से आग्रह किया भविष्य में इस अध्ययन का लाभ उठाकर प्राकृतिक आपदा के कारण आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन के लिए अपने कार्यबल और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें।

6.6.3. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राहत आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन में एनआईडीएम ने भाग लिया, 27 मई 2014

एक पाँच सदस्यों वाला दल जिसमें कार्यकारी निदेशक, डॉ सत्येन्द्र; एसोसिएट प्रोफेसर के जे अनंदा कुमार; असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री श्रीजा नायर; परामर्शदाता, सुश्री प्रियंका और एनआईडीएम की प्रोग्रामर सुश्री अनूपमा शामिल थे, न राहत कमिशनर बैठक में भाग लिया जो 27 मई 2014 को विज्ञान भवन में हुई थी। बैठक में एन आई डीएम के संकाय सदस्यों ने भी दो प्रस्तुतिकरण किया। इन प्रस्तुतिकरण का संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया है:

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन): एनआईडीएम की सुश्री श्रीजा ने आईडीआरएन पर एक सार प्रस्तुत की। राहत आयुक्तों और उनके प्रतिनिधियों को आईडीआरएन कार्यान्वित करने में, उन्होंने कार्य रफ्तार, उपयोग और उपयोगकर्ता, लाभ और चुनौतियाँ के बारे में बताया। राज्यों को भी आग्रह किया गया कि वे जिला के माध्यम से आई डी आर एन में

डाटा अद्यतन करने की सुविधा उपलब्ध कराएँ। इस उद्देश्य के लिए एनआईडीएम ने आवश्यक सहयोग भी दिया। आगे संयुक्त सचिव ने एक समिति भी गठित की जिसमें पाँच आई डी आर एन पोर्टल को आगे अपग्रेड और अद्यतन करने के लिए राज्यों की एक समिति भी गठित की, जैसे— राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, झारखंड इसमें शामिल थे।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी): डॉ. के जे अनंदा कुमार ने एनसीआरएमपी के अंतर्गत आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन के बारे में विस्तार से बताया और पीडीएनए पर एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें अध्ययन का क्षेत्र, और अध्ययन के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है? और अध्ययन के अंतर्गत आनेवाली क्रियाकलाप शामिल थे। इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य राज्यों द्वारा पीडीएनए को आपदा प्रबंधन योजना का एक प्रमुख पहलू में शामिल करना था। एनआईडीएम ने भी इस संबंध में राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान किया।

6.6.4. "पर्यावरण को आपदा जोखिम न्यूनीकरण से बचाना" पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान और "विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम, 4 जून 2014

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आईआईपीए के सहयोग से "पर्यावरण को आपदा जोखिम न्यूनीकरण से बचाना" विषय



चित्र 6.36: उच्चाधिकारी दीप प्रज्वलित करते हुए

पर स्कोप संग्रहालय, लोधी रोड नई दिल्ली में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया (चित्र 6.36)। अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अकादमिषियन, नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता, एन जी ओ, शैक्षिक संस्थानों, मंत्रालयों और सिविल समाज समुदायों के अतिरिक्त 250 से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

एनडीएमए के माननीय सदस्य श्री बी भट्टाचार्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, और डॉ जे एस शर्मा, राष्ट्रीय रेनफेड क्षेत्र प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्माननीय अतिथि थे। प्रोफेसर सी के वार्सेन्या ने यूएनइपी विषय पर मुख्य संदर्भ "छोटा द्वीप और जलवायु परिवर्तन" को डिआरआर के संदर्भ में संबोधित किया। इस अवसर पर "बुंदेलखंड सूखा" पर एक पुस्तक विमोचित की गई। अन्य पदाधिकारियों में आईआईपीए के निदेशक डॉ टी चटर्जी; सिविकम एसडीएमए के उप कुलपति; एनडीएमए के जे एस, डॉ अनिता जैन भटनागर; और एनआईडीएम के इडी डॉ सत्येन्द्र मौजुद थे।

अपने स्वागत भाषण में डॉ सत्येन्द्र ने प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध असुरक्षा को कम करने के लिए पर्यावरण, जीविका और शाश्वत विकास के बीच संबंध को समझने पर जोर दिया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के निदेशक (पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव) डॉ टी चटर्जी ने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। सामाजिक और आर्थिक तथ्य जैसे— बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, शहरीकरण, बदलती जीवन-शैली, कृषि विकास, आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण पर्यावरणीय पतन का मुख्य कारण है। हमें कुछ निश्चित नियमों और तरीकों का पालन करते हुए अपने पर्यावरण का संरक्षण करने की कोशिश करना चाहिए।

श्री भट्टाचार्य ने, अपने अध्यक्षीय भाषण में, आने वाले पीढ़ी को रहने के लिए शश्वत और सुरक्षित वातावरण के निर्माण हेतु समाज, विशेषकर छात्रों की जागरूकता

पर बल दिया। उन्होंने पर्यावरण को सभी लाभों का आधार बताया, जो हम अपने जीवन के लिए तथा आर्थिक विकास के लिए निकालते हैं, लेकिन इसमें जोखिम घटना पैदा करने की भी क्षमता है, जैसे— बाढ़, सूखा, भू-स्खलन, जंगल आग, बिमारियाँ और भूकंप इत्यादि। उन्होंने एनआईडीएम के ऐसे सभी अभियानों की प्रशंसा की और अन्य देशों, राज्य स्तर के संस्थानों, मीडिया एजेंसियों और स्थानिय समाजों को शामिल कर सहयोगी प्रयासों के लिए सुझाव दिया।

डॉ जे एस शर्मा, राष्ट्रीय रेनफेड क्षेत्र प्राधिकार के सीईओ ने स्थानीय और सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त जन प्रबंधन को परारंपरिक बुद्धिमान और स्थानीय नवीकरण के लिए सूखी भूमि कृषि को प्रोन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदा जोखिम के वृहत्तर लचीलेपन के लिए खेती के विविधिकरण और ग्रामीण जीविका के लिए अनुसंधान और जागरूकता हेतु आह्वान किया।

प्रोफेसर सी के वार्सनेया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इमेरिटस प्रोफेसर, इस अवसर के मुख्य नोट वक्ता थे, इन्होंने इस वर्ष के विश्व पर्यावरण जागरूकता अभियान "छोटा द्वीप और जलवायु परिवर्तन" के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में वक्तव्य दिया। प्रोफेसर वी के शर्मा ने पर्यावरण सुरक्षा को प्रोन्नत करने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में समेकित योजना और समुदायों का सम्मिश्रण पर बल दिया। डॉ अनिता भटनागर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार

के संयुक्त सचिव ने "एक पृथ्वी, एक जीवन" पर्यावरण के दायित्व भरे देखभाल पर एक फिल्म दिखाया और बताया कि कैसे सभी नागरिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना योगदान कर सकते हैं।

आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय परिणाम के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान आयोजित किया गया जिसमें छात्रों के लिए लेख प्रतियोगिता (हिंदी और अंग्रेजी) "आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पर्यावरण की रक्षा" का प्रबंध किया गया।

देश भर से 1500 से अधिक प्रविष्टि की प्राप्ति हुई जिसमें 80 से अधिक स्कूलों का प्रतिनिधित्व था। लेख प्रतियोगिता के विजेताओं को डॉ बी भट्टाचार्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य ने कार्यक्रम में जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कोप संग्रहालय में आयोजित किया गया था, पुरस्कृत किया। प्रथम पुरस्कार मध्यम स्तर का अंग्रेजी लेख था जिसे पियुस खरबंदा ने जीता, हिंदी में एमेट्री अंतर्राष्ट्रीय स्कूल दिल्ली के श्रेया शैलान को पुरस्कार के लिए चुना गया। उच्च विद्यालय की श्रेणी में दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा के सुब्रोज्योति मुखर्जी को अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार मिला और गुरुनानक गर्ल सिनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के प्रियंका महेश चंद को हिंदी में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। कुल 32 छात्रों को पुरस्कार दिया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी श्रेणियों में पाँच सांत्वना पुरस्कार शामिल थे (चित्र 6.37)।



चित्र 6.37: कार्यक्रम के दौरान विजता छात्र सम्मानित अतिथियों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए



चित्र 6.38: "बुदेलखंड सूखा: एक सिंहावलोकन विश्लेषण और इससे आगे शीर्षक पुस्तक का विमोचन

एक पुस्तक जिसका शीर्षक था “बुंदेलखंड सूखा: एक सिंहावलोकित विश्लेषण और इससे आगे” जो एनआईडीएम संकाय सदस्य डॉ अनिल कुमार गुप्ता, सुश्री श्रीजा नायर तथा अनुसंधान दल द्वारा लिखा गया, तथा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अनुसंधान पर आधारित था और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान (आई सी एस एस आर) के सहायता से लिखा गया का विमोचन 4 जून 2014 को किया गया (चित्र 6.38)। इस पुस्तक में बुंदेलखंड के आपदा के संदर्भ में घटना, प्रभाव, न्यूनीकरण, उपायों का वर्णन किया गया है। एनआईडीएम निगम फिल्म के सी डी और भवन मालिकों के लिए भूकंप सुरक्षा उपाय के अतिरिक्त आपदा के समय क्या करें? और क्या नहीं करें? के रूप में एक शैक्षिक प्लायर भी विमुक्त की गई।

6.6.5. एनआईडीएम ने उत्तराखंड त्रासदी को स्मरण किया, 17 जून 2014

उत्तराखंड राज्य को भू-स्खलन, झील के टूटने और तीव्र बाढ़ के कारण 16 और 17 जून 2013 को घोर आपदा का सामना करना पड़ा था जिसमें स्थानीय लोगों और यात्रियों के साथ सैकड़ों लोगों की जानें गई थी, इस क्षेत्र के मकानों, सड़कों, अवसंरचनाओं, तथा उपयोगी चीजों की भारी क्षति हुई थी और जीविका, अर्थव्यवस्था, तथा पर्यावरण पर काफी उल्टा प्रभाव पड़ा था। एनआईडीएम दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और वहाँ के लोगों से मिलकर आपदा का प्रलेखन किया था और इस घटना से सीखे गये आपदा के विषय में जानकारी को उभारा था, जो क्षेत्र अध्ययन, प्रभावित लोगों से बात-चीत और आपदा पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला द्वारा विभिन्न हितधारकों से अनुभव साझा करने पर आधारित था। मसौदा प्रलेखन प्रतिवेदन राज्य सरकारों और अन्य के साथ साझा किया गया।

17 जून 2014 को त्रासदी के एक वर्ष बाद एन आई ने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रस्थान किये गये पीड़ित आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जो उत्तराखंड आपदा के समय मारे गये और अपने अनुभवों को साझा किया (चित्र 6.39)।



चित्र 6.39: एनआईडीएम संकाय, कर्मचारी और अन्य प्रतिभागी उत्तराखंड त्रासदी को स्मरण करते हुए

एनआईडीएम के डॉ सूर्यप्रकाश ने संस्थान के संकाय, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं से अपना विचार व्यक्त करने और आवश्यक कार्य करने के लिए आग्रह किया ताकि ऐसी आपदा फिर से न आए और यदि यह रोकने के योग्य न हो तो जोखिम को कम किया जा सके।

नवोदय विद्यालय के उप प्रधानाध्यापिका, सुश्री नर्वदा वालोदी ने अपना अनुभव आपदा के बारे में भारी मन से व्यक्त किया जो उनके स्कूल से 30 किमी पर घटी थी। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल के कई छात्र प्रभावित हुए; कुछ मारे गये, कुछ ने अपने माता-पिता खो दिये और कुछ गाँव पूरी तरह से उजड़ गये। उन्होंने सूचना दी कि एक ‘लमगिंडी’ नाम का गाँव है जिसने सभी पुरुषों को खो दिया है (अपने परिवार के लिए रोटी कमानेवाला) और वहाँ अब सिर्फ विधवाएँ ही बची हैं। श्री बलवीर सिंह धालीवाल, उत्तर पूर्व के एक स्कूल प्रिंसिपल ने प्रकृति की ओर मानव संदर्भ पर बल दिया और पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने का आह्वान किया। एनआईडीएम के डॉ कौशिक ने आपदा के बाद जीविका और भूमि के समाप्त हो

जाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवासन की समस्याओं को उजागर किया। श्री डी के कौशिक, एक स्कूल के उप-प्रधानाचार्य ने किसी आपदा के लिए सामान्य जागरूकता और स्वयं तैयारी पर बल दिया। इस क्षेत्र में गलत निर्माण और असामान्य भूमि प्रयोग की स्थिति को भी उजागर किया गया।

मेजर जनरल (भूतपूर्व) डॉ वी के नायक, वरिष्ठ सलाहकार एनआईडीएम ने आपदा की असुरक्षा को कम करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उजागर किया कि सभी विकासात्मक क्रियाकलापों में हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। एनआईडीएम के श्री आर पी शर्मा ने मानव क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकृति के अनिच्छित छेड़छाड़ पर अपना अनुभव साझा किया जिसे उन्होंने पर्यावरणीय संरक्षण पर लिखे एक स्व-लिखित कविता के द्वारा वर्णित किया। मुख्य मुद्दा था मानव जीवन को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए पर्यावरण के छेड़-छेड़ को नकारे बिना सुरक्षित और शाश्वत योग्य विकास।

6.6.6. "आपदा प्रबंधन: समेकित अनुक्रिया रणनीति" सेमिनार में एनआईडीएम की प्रतिभागिता, 4 सितंबर 2014

भूमि युद्ध अध्ययन केन्द्र (सीएलएडब्ल्यूएस) ने 4 सितंबर, 2014 को "आपदा प्रबंधन: समेकित अनुक्रिया रणनीतियाँ" पर दिल्ली कैंट में एक सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार की अध्यक्षता जेनरल एन सी विज, पीवीएस म, यूवाईएसएम, एवीएसएम, भूतपूर्व सीओइएस और एनडीएमए के उपाध्यक्ष ने की। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र को पैनल के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने "भारत में आपदा प्रबंधन : उभरते मुद्दे और अनुक्रियाएँ" विषय पर वक्तव्य दिया। सेमिनार में आर्म फोर्स के वरिष्ठ और मध्य स्तरों के अधिकारियों ने भाग लिया। एनआईडीएम ने भी अपने आई इ सी सामग्रियों और प्रकाशनों को

वितरित किया जिसमें मॉड्यूल, पुस्तकें, घटना अध्ययन और जागरूकता सामग्रियाँ शामिल इत्यादि थे।

6.6.7. "जलवायु परिवर्तन और संकट- अनुभवों और रणनीतियों को साझा करना" वैश्विक नेतृत्व सम्मेलन में एनआईडीएम की प्रतिभागिता, 17 सितंबर 2014

एसोचेम भारत ने "जलवायु परिवर्तन और संकट के अनुभवों और रणनीतियों को साझा करना" विषय पर 17 सितंबर 2014 को इंडिया हैबिटेट केन्द्र, नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें श्री डी एस रावत, एसोचेम के सचिव जेनरल; डॉ आर के पचौरी, निदेशक जेनरल, टीईआरआई; श्री बाबुलाल जैन, सीइओ, इइएआर कंसल्टेंट्स सर्विसेज और सह फाउंडर, विश्व बीपीओ फॉर्म; श्री मंगु सिंह, प्रबंध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेक निगम लिमिटेड; एचइश्री फ्रांकोइस रिचियर, राजदूत, फ्रांस दूतावस, भारत; और अन्य ने भाग लिया।

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र ने इसमें भाग लिया और "जलवायु परिवर्तन की ओर न्यूनीकरण और अनुकूलन के चरण" विषय पर सत्र की अध्यक्षता की (चित्र 6.40)। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के साथ हाइड्रो-मौसमविज्ञानी आपदा जैसे- बाढ़, चक्रवात, सूखा इत्यादि में भी वृद्धि होती



चित्र 6.40: एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

है, जो जीवन यापन को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि या कमी और वर्षा की अवधि या समय में परिवर्तन से कृषि प्रभावित होती है। उन्होंने यह कहते हुए विराम लिया कि अनुकूलन की ओर कदम बढ़ाने तथा जागरूकता फैलाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने उस सत्य की ओर भी ध्यान दिया जिसमें समुचित योजना रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक जलवायु सूचना और ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यक अनुकूलन के बीच का अंतराल भरा जा सके।

6.6.8. एसडीएमए और डीडीएमए के अधिकारियों का मेघालय से एनआईडीएम का दौरा, 19 सितंबर 2014

मेघालय के एसडीएमए और डी डी एम अधिकारियों के एक दल ने 19 सितंबर 2014 को एनआईडीएम का दौरा किया। प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व श्री एच बी मारक, एम सी एस, कार्यकारी अधिकारी, एसडीएमए, मेघालय ने किया। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक डॉ सत्येन्द्र ने प्रतिनिधि को संबोधित किया। इन्होंने उन्हें एनआईडीएम के कार्य, भूमिका और प्रमुख क्रियाकलापों का संपूर्ण व्यौरा दिया। डॉ सुर्य प्रकाश ने "पहाड़ों पर आपदा प्रबंधन" के बारे में प्रतिनिधियों को बताया तथा इस विषय पर विचार-विमर्श का आयोजन किया। मेजर जेनरल वी के नायक, के सी, ए वी एस एम ने प्रतिनिधियों को आई आर एस और इ ओ सी के कार्य के संदर्भ में संबोधित किया। इसके बाद सुश्री बलविंदर कौर ने इ ओ सी पर प्रस्तुतिकरण की तथा आई डी आर एन पर एक प्रस्तुतिकरण सुश्री अनूपमा सेठी ने दी।

6.6.9. "विकास नीतियों और अभ्यासों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मुख्य धारा में लाने

और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन" पर सम्मेलन, 20 अक्टूबर 2014

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (यूपी-एसडीएमए), लखनऊ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थानी (एनआईडीएम), दिल्ली के सहयोग से गोरखपुर पर्यावरण कार्य समूह (जीइएजी) और सामाजिक तथा पर्यावरण संक्रमण संस्थान (आईएसडीटी), यूएसए, के साथ 20 अक्टूबर 2014 को ताज के विवांता होटल, लखनऊ में "विकास नीतियों और अभ्यासों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मुख्य धारा में लाने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन" विषय पर एकदिवसीय संमेलन का आयोजन किया। इस घटना ने सरकारों, यू एन एजेंसियों, एन जी ओ, दाताओं और अकादमियों से लगभग 150 नीति-निर्माताओं और अभ्याकर्ताओं को एक साथ लाया।

श्री सुरेश चंद्रा, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार; सुश्री लीन जौहरी, सचिव और राहत युक्त, उत्तर प्रदेश सरकार; श्री वी एन गर्ग, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार; डॉ अनिल कुमार गुप्ता, नीति और योजना प्रमुख, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत सरकार; सुश्री निलोफर पोरजांडे, राज्य प्रमुख, यूनिसेफ, लखनऊ; श्री मिहिर भट्ट, निदेशक, अखिल भारतीय न्यूनीकरण संस्थान (एआईडीएमआई) और डॉ सिराज ए वाजिया, अध्यक्ष, जीइएजी, मंच पर के पदाधिकारी थे(चित्र 6.41)।



चित्र 6.41: मंच पर उपस्थित पदाधिकारी गण

उद्घाटन भाषण के बाद पूरा दिन तीन मुख्य विचारणीय मुद्दों पर विचार-विमर्श में गया, वे हैं: (क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: परिकल्पना और अंतर्दृष्टि; (ख) आपदा और जलवायु जोखिम द्वारा दिये गये चुनौतियों का सामना करने के लिए विकेन्द्रीकृत योजना पर प्रायोगिक अनुभव; (ग) आपदा और जलवायु जोखिम न्यूनीकरण को समर्थ करना: नीतियाँ, कार्यक्रमों और संस्थानों को विविध स्तर पर, स्थानीय से राष्ट्रीय तक। वक्तव्यों में सीसीए और डीआरआर को विकास नीति और योजना में लाने पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें प्रायोगिक पहुँच और अनुसंधान से तथा नीति भाषणों से लिया गया अनुभव शामिल था। सम्मेलन का समापन “डीआरआर और सीसीए को मुख्य धारा में लाने संबंधी लखनऊ घोषणापत्र”— उत्तर प्रदेश में हालिया विकास की स्थिति में डीआरआर और सीसीए के लिए एक रोडमैप और मुख्य प्रतिवेदन के साथ हुआ।

6.6.10 एनआईडीएम का आईआईटीएफ - 2014 में भागीदारी, 14 से 27 नवंबर 2014

एनआईडीएम भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में नियमित रूप से तीन वर्षों से भाग लेता आ रहा है। वर्ष 2014 के दौरान, एनआईडीएम का स्टॉल हॉल संख्या 12 पर एनडीएमए और एनडीआरएफ के साथ रखा गया था। आईआईटीएफ पर एनआईडीएम का स्टॉल में 30 से अधिक वितरण सामग्रियाँ थी तथा कई पुस्तकें और अन्य प्रकाशन प्रदर्शनी के लिए भी थे। इसके अतिरिक्त, स्टॉल पर एक शेक टेबल भी था जो भूकंप के समय भूकंपीय लिक्विफेक्शन दिखाता है और अन्य मॉडल घी प्रदर्शनी के लिए था, जैसे—भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित मकान बनाना। मॉडल में भूकंप प्रतिरोध मकान निर्माण के लिए विभिन्न रेट्रोफिट तकनीक दिखाया गया था। स्टॉल का उद्घाटन तथा दौरा डॉ पी के मिश्रा, अतिरिक्त प्रधान सचिव, पी एम ओ द्वारा 14 नवंबर, 2014 को सचिव (बीएम); डीजी, एनडीआरएफ; सचिव, एनडीएमए; और संयुक्त सचिव, एनडीएमए (चित्र 6.42) की उपस्थिति में किया गया।



चित्र 6.42: स्टॉल पर डॉ पी के मिश्रा, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के साथ सुश्री स्नेहलता कुमार सचिव (बीएम) एमएचए तथा कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम

स्कूल सुरक्षा पर एनआईडीएम कैलेण्डर का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह ने आईआईटीएफ में आयोजित एक कार्यक्रम में 18 नवंबर 2014 को किया (चित्र 6.43)। इस कार्यक्रम के दौरान एनआईडीएम ने भी स्कूल स्तर पर आपदा जागरूकता के लिए एक स्कीट का आयोजन किया था। एनआईडीएम कैलेण्डर में 14 पृष्ठ हैं जो विभिन्न क्या करें और क्या नहीं करें के साथ-साथ स्कूल सुरक्षा से संबंधित अन्य तकनीक को भी दिखाता है, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, से पहले, आपदा के समय और आपदा पश्चात क्या करें और क्या नहीं करें के बारे में बताता है। कैलेण्डर की प्रशंसा विभिन्न हितधारकों ने की और स्टॉल पर आये आगंतुकों में इसकी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता संबंधी विभिन्न क्रियाकलाप को लाकर, भारत को आपदा न्यूनीकृत देश बनाने के लिए एनआईडीएम अपने उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु धीरे-धीरे प्रगति कर रही है



चित्र 6.43: माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह स्कूल सुरक्षा पर एनआईडीएम कैलेण्डर विमुक्त करते हुए

6.6.11. "आपदा पश्चात आवश्यक मूल्यांकन का सामाजिक और लिंग विस्तार" पर प्रस्तुतिकरण, डॉ आशा कंबन द्वारा, एनसीआरएमपी के अंतर्गत भारत के लिए पीडीएनए अध्ययन, 20 नवंबर 2014

डॉ आशा कंबन के द्वारा एक वक्तव्य, सामाजिक विस्तार और लिंग विशेषज्ञ "भारत के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) अध्ययन", राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत पी डी एन ए के सामाजिक और लिंग संबंधी विस्तार पर 20 नवंबर 2014 (चित्र 6.44) को एनआईडीएम में आयोजित किया गया। डॉ आशा कंबन, त्रिनिदाद और टोबैगो पर आधारित विश्व बैंक में एक अग्रिम तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करती आ रही है और एक अनुसंधानकर्ता तथा जन नीति विशेषज्ञ है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक विकास के जनसांख्यिकीय अनुसंधान में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है।



चित्र 6.44: एनआईडीएम में व्याख्यान के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि/ प्रतिभागी

अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान, डॉ आशा ने आपदा के बाद के आवश्यक मूल्यांकन में विभिन्न सामाजिक, लैंगिक और मनो-सामाजिक प्रभाव पर नजर डाला। अपने बहुत ही प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को बताते उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संदर्भ से खींचे गये सबसे अधिक प्रासंगिक सूचक से कितना ऐसा मूल्यांकन

किया जा सकता है? ऐसे मूल्यांकन के गुणात्मक और संख्यात्मक संदर्भ का वर्णन करते समय उन्होंने ऐसे क्षेत्रों से संख्यात्मक मूल्यांकन तक पहुँचने के लिए आवश्यक डाटा के प्रकार पर जोर दिया, जैसे—स्वास्थ्य, शिक्षा, घर इत्यादि, जिसे साथ में रखने पर आवश्यक संपूर्ण सामाजिक क्षेत्र आधारित मूल्यांकन को एक वैकल्पिक आधार दे सकता है। सत्र का समापन एक संक्षिप्त विचार-विमर्श के साथ हुआ जहाँ प्रतिभागी उनके विचारों से सहमत थे और कुछ संदर्भों पर जैसे— पुनर्स्थिति और मनो-सामाजिक मूल्यांकन प्रचलन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया।

6.6.12. राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जम्मू और काश्मीर क्षेत्रीय शाखा द्वारा आयोजित "2014 में बाढ़: जम्मू काश्मीर के लिए आपदा प्रबंधन पर सीख" में एनआईडीएम की प्रतिभागिता, 2 - 3 फरवरी 2015

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग, केन्द्रीय जम्मू विश्वविद्यालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जम्मू और काश्मीर क्षेत्रीय शाखा ने "2014 में बाढ़: जम्मू और काश्मीर के लिए आपदा प्रबंधन हेतु सीख" विषय पर 2 से 3 फरवरी 2015 को एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का आयोजन चार सत्रों में हुआ यथा— "बाढ़ और होतधारकों की अनुक्रिया"; "बाढ़ के कारण और गति"; "राहत और पुनर्निर्माण I"; और "आपदा के जोखिम को कम करने के लिए तैयारी"।

एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व मेजर जनरल डॉ वी के नायक, केसी, एवीएसएम ने किया जिन्होंने "बाढ़ और हितधारकों की अनुक्रिया" विषय पर सत्र की अध्यक्षता

की तथा “तैयारी और अनुक्रिया की महत्वपूर्ण पहलू” विषय पर अपना वक्तव्य भी दिया (चित्र 6.45)। मेजर जेनरल नायक ने विदाई सत्र में भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सामुदायिक स्तर पर तैयारी की महत्ता को उद्घाटित किया और आपदाओं के अपातकालीन अनुक्रिया चरण में विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों को अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सहगामी अनुक्रिया की आवश्यकता और घटना अनुक्रिया प्रणाली के कार्यान्वयन को भी चिह्नित किया।



चित्र 6.45: सेमिनार में मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण

6.6.13. आपदा प्रबंधन योजना के सूत्रीकरण पर पाठ्यक्रम (डीडीएमपी) आरआईपीए, जयपुर, 18 से 20 फरवरी, 2015

राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (आरआईपीए) एनआईडीएम के सहयोग से आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी विषय पर 18 से 20 फरवरी तक आरआईपीए में तीन दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया। राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 26 मध्य स्तरीय अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वयन एनआईडीएम के श्री शेखर चतुर्वेदी और डॉ सुषमा गुलेरिया ने किया। एक स्थानीय टी वी चैनल जिसे इ-टीवी कहा जाता है, ने प्रोग्राम को दिखाने का काम किया और पाठ्यक्रम के बारे में संकाय का

साक्षात्कार लिया तथा आपदा प्रबंधन के बारे में सरकार की नीतियों के बारे में भी पूछा (चित्र 6.46)।



चित्र 6.46: एनआईडीएम संकाय सदस्य का साक्षात्कार लेती हुई मीडिया

6.6.14. एनडीएमए के सदस्यों का एनआईडीएम दौरा, 23 फरवरी 2015

श्री आर के जैन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य सचिव, एनडीएमए के तीन सदस्यों के साथ, यथा— लेफ्टिनेंट जेनरल एन सी मारवाह, डॉ डी एन शर्मा और कमल किशोर ने 23 फरवरी 2015 (चित्र 6.47) को एनआईडीएम का दौरा किया। दौरा का उद्देश्य सदस्यों को संस्थान और इसके क्रियाकलापों के बारे में परिचित कराना था। दौरा के प्रारंभ में, प्रोफेसर संतोष कुमार, कार्यकारी निदेशक ने सभी प्राधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें संस्थान के बारे में संक्षेप में बताया। बाद में संस्थान के दो सदस्यों, श्री शेखर चतुर्वेदी और डॉ सुषमा गुलेरिया ने संस्थान तथा इसकी क्रियाकलापों के बारे में एक प्रस्तुतिकरण किया जिसमें संस्थान की उत्पत्ति, विजन और उद्देश्य कथन, संरचना, कार्य तथा क्रियाकलापों जैसे— प्रशिक्षण मापदंड तैयार करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, आ इ सी सामग्रियाँ तैयार करना, प्रकाशन, राज्य सरकारों की सहायता करना, अनुसंधान परियोजना, विभिन्न आपदाओं का प्रलेखन तथा संस्थान का वेबसाइट इत्यादि।



चित्र 6.47: एनडीएमए सदस्यों और एनआईडीएम संकाय के बीच बातचीत

संकाय के सदस्यों के प्रस्तुतिकरण के बाद, कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि संस्थान ने अवसंरचना और मानव संसाधनों जैसी चुनौतियों

का सामना करने के बावजूब भी इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। चारों संकायों के प्रमुखों और संस्थान के अन्य संकाय सदस्यों ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने-अपने विचार साझा किये। एन डी एम ए के सदस्यों ने संस्थान के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि एन डी एम ए और एनआईडीएम को आपदाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों को दिखाने, सापेक्ष मूल्य हानि इत्यादि का संयुक्त रूप से अध्ययन करना चाहिए तथा इसमें जीविका और सामाजिक मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए। यह निर्णय निर्माताओं को विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक वसूली से संबंधित मुद्दों के लिए समुचित मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरण तैयार करने में मदद करेगी। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की समाप्ति हुई।

अध्याय



प्रशासन

संस्थान द्वारा किये जा रहे प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श कार्यों को संस्थान के प्रशासन स्कंध द्वारा अच्छी तरह से सहयोग प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय गृह मंत्री संस्थान निकाय के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। संस्थान निकाय में 42 सदस्य होते हैं जिसमें प्रख्यात विद्वानों, वैज्ञानिकों और व्यवसायी के अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय

स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के प्रमुखों के कई केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों को शामिल किया जाता है।

संस्थान की एक 16 सदस्यों वाली प्रबंधक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता एनडीएमके उपाध्यक्ष करते हैं। संस्थान के संचालन इकाई का उपाध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव होते हैं (सारणी 7.1)।

सारणी 7.1 : एनआईडीएम के संचालन इकाई सदस्यों की सूची

क्र.स	नाम और पता	संपर्क व्यौरा
1.	माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, एन डी एम ए भवन, ए 1 सफदरजंग एलक्लेव, नई दिल्ली	दूरभाष: 91-11-26701701, 704 फैक्स: 91-11-26701706 माननीय उपाध्यक्ष के व्यक्तिगत सचिव दूरभाष: 26701721
2.	केन्द्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, कमरा संख्या. 113 उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली -110001	दूरभाष: 23092989, 23093031 फैक्स: 23093003
3.	सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या. 124 उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली -110001	दूरभाष: 23092440 फैक्स: 23092717
4.	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली -110001	दूरभाष: 23092929, 23092663 फैक्स: 23092546
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, नई मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली -110016	दूरभाष: 26590412, 26511439 फैक्स: 26863847
6.	सचिव, अंतरीक्ष विभाग, लोक नायक भवन, खान बाजार, नई दिल्ली - 110003	दूरभाष: 24698313 फैक्स: 24617377
7.	सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, एन डी एम ए भवन, ए-1 सफदरजंग एलक्लेव, नई दिल्ली	दूरभाष: 26701710 फैक्स: 26701716
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग 315 सेवा भवन (एस), आर के पुरम, नई दिल्ली- 110606	दूरभाष: 26187232 फैक्स: 26195516
9.	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लाक, नई दिल्ली-110001	दूरभाष: 23094709 फैक्स: 23093002
10.	प्रधान सचिव उत्पाद शुल्क और आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 असम	दूरभाष: 0361-2237255, फैक्स: 0361-2237268 vkpindia@rediffmail.com

11त्र	सचिव, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, डायमंड हार्बर रोड, पी ओ जोका, कोलकाता 700 104, पश्चिम बंगाल	दूरभाष: 033-24678310 फैक्स: 033-24678307
12.	सचिव, भारतीय तकनीकी संस्थान, रुड़की, 247 667, उत्तराखंड	दूरभाष: 01332-285500 फैक्स: 01332-273560, 285815
13.	सचिव, भारतीय जियोफिजिकल अनुसंधान संस्थान. उपाल रोड, हैदराबाद 500606	दूरभाष 040-23434700, 4711 फैक्स: 040-27171564
14.	उप-कुलसचिव, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय सेक्टर - 16सी द्व ारका, दिल्ली - 110078, भारत	दूरभाष 91-11.25302104, 25302105 फैक्स: 91-11.28035243
15.	कार्यकारी निदेशक भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान आई आई पी ए कैपस, 5 बी, आई पी इस्टेट, महात्मा गांधी रोड, नई दिल्ली-110002	दूरभाष स. 91.11.23702445 फैक्स: 91-11.23702446

7.1. सामान्य निकाय और संचालित निकाय की बैठक

एनआईडीएम की सामान्य निकाय और शासी निकाय की पहली बैठक क्रमशः 18 अप्रैल, 2007 और 20

जून, 2007 को आयोजित की गई थी। तब से एनआईडीएम में आठ अधिशासी निकाय की बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों की एक सूची सारणी 7.2 में दी गई है।

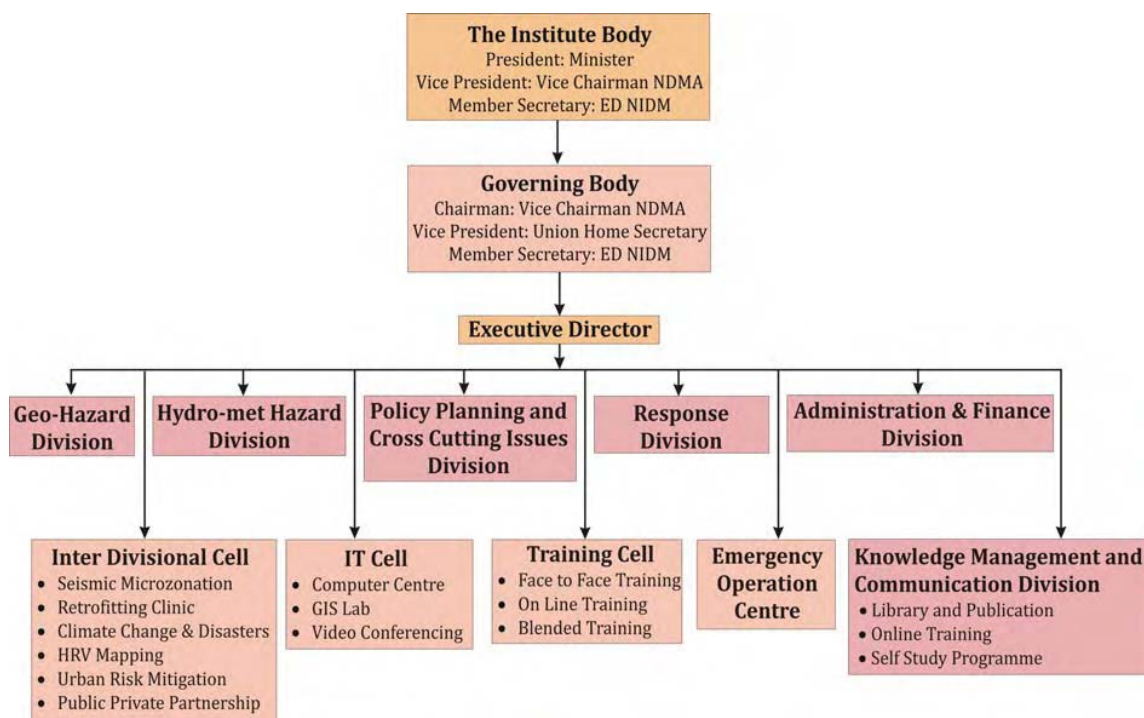
सारणी 7.2: एनआईडीएमके अधिशासी निकाय की बैठकें

क्र.सं	अधिशासी निकाय बैठक	तिथि
1.	अधिशासी निकाय की पहली बैठक	20 जून 2007
2.	अधिशासी निकाय की दूसरी बैठक	23 अप्रैल 2008
3.	अधिशासी निकाय की तीसरी बैठक	27 नवंबर 2008
4.	अधिशासी निकाय की चौथी बैठक	17 मार्च 2009
5.	अधिशासी निकाय की पाँचवीं बैठक	18 मार्च 2010
6.	अधिशासी निकाय की छठी बैठक	11 जुलाई 2012
7.	अधिशासी निकाय की सातवीं बैठक	23 अगस्त 2013
8.	अधिशासी निकाय की आठवीं बैठक	2 जुलाई 2014

7.2. सांस्थानिक संरचना

संस्थान में एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, अंतर्विभागीय कक्ष, आई टी कक्ष और अपातकालीन संचालन केन्द्र के अतिरिक्त

छः प्रभाग हैं (चित्र 7.1) संस्थान के कार्यकारी निदेशक, जो संस्थान निकाय और इसके अधिशासी निकाय के सदस्य सचिव भी हैं, संस्थान के दैनिक प्रशासन को चलाते हैं।



चित्र 7-1: एनआईडीएम का ऑर्गेनोग्राम

7.3. एनआईडीएम संकाय

एनआईडीएम संकाय का संभाग के आधार पर सूची सारणी 7.3 में दिखाया गया है:

सारणी 7.3 : एनआईडीएम के संकाय

क्र सं	नाम	पद
1	डॉ सतेन्द्र	कार्यकारी निदेशक (अगस्त 2011 – दिसंबर 2014)
2	प्रोफेसर संतोष कुमार	कार्यकारी निदेशक (दिसंबर 2014 – वर्तमान)
भूवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन विभाग		
3	डॉ चंदन घोश	प्रोफेसर और अध्यक्ष, भू-जोखिम संकट प्रबंधन प्रभाग और अध्यक्ष, आई टी अनुभाग
4	डॉ. सूर्य प्रकाश	एसोसिएट प्रोफेसर
5	सुश्री श्रीजा एस नायर	सहायक प्रोफेसर, आई टी अनुभाग
6	डॉ. रितु राज	रिसर्च एसोसिएट
नीति नियोजन और क्रॉस कटिंग विषयक विभाग		
7	डॉ. अनिल के गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, नीति नियोजन और अध्यक्ष प्रशिक्षण विभाग
8	सुश्री चंद्राणी बंदोपाध्याय	सहायक प्रोफेसर
9	डॉ. अजिंदर वालिया	सहायक प्रोफेसर
10	श्री शेखर चतुर्वेदी	रिसर्च एसोसिएट
हाइड्रो-मौसमविज्ञानी आपदा प्रबंधन विभाग		
11	डॉ. के जे अनंदा कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, हाइड्रो-मौसमविज्ञान आपदा प्रबंधन विभाग
12	डॉ. आशुतोश देव कौशिक	रिसर्च एसोसिएट
आपदा अनुक्रिया विभाग		
13	लेफ्टिनेंट कर्नल पी के पाठक	परामर्शदाता
14	डॉ. सुषमा गुलेरिया	रिसर्च एसोसिएट

7.4 सामान्य प्रशासन

संस्थान के कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन और शासी निकाय के दिशानिर्देश और मार्गदर्शन में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त निदेशक, लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी निदेशक को सहायता प्रदान करते हैं। संस्थान के प्रशासन में मुख्य रूप से सांवैधानिक

बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, सुरक्षा परिसर समर्थन सेवाएँ तथा कर्मचारियों के कल्याण का समन्वय शामिल है। यह आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके संस्थान में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श गतिविधियों को सुविधा पहुँचाता है। एनआईडीएम के कर्मचारियों की सूची सारणी 7.4 में दी गई है।

सारणी 7.4 : एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.स.	नाम	कर्मचारी
1	श्री हेमंत कुमार	कंप्यूटर प्रोग्रामर
2	श्री एस के तिवारी	लाइब्रेरियन
3	सुश्री रितु सूद	प्रशासनिक सहायक
4	श्री एस एस विष्ट	कनिष्क सहायक सह लेखाकार
5	श्री अविनाश कुमार पांडेय	लेखा सहायक
6	श्री जे एन झा	कनिष्क इंजिनियर
7	सुश्री अमृता गुप्ता	निजी सहायक
8	सुश्री संतोष मिश्रा	डाटा इंट्री ऑपरेटर
9	सुश्री गीता शर्मा	डाटा इंट्री ऑपरेटर
10	श्री राजीव कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर
11	सुश्री मेघा कोहली	डाटा इंट्री ऑपरेटर
12	सुश्री विधि अवस्थी	डाटा इंट्री ऑपरेटर
13	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
14	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी टास्किंग कर्मचारी (एम टी एस)
15	श्री विजय कनोजिया	मल्टी टास्किंग कर्मचारी (एम टी एस)
16	श्री पंकज कुमार	मल्टी टास्किंग कर्मचारी (एम टी एस)
17	सुश्री जया	पुस्तकालय सहायक

7.5. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

एनआईडीएम ने 2011-12 से "हिंदी दिवस" मनाना प्रारंभ किया। 2014 में 15 सितंबर को एनआईडीएम परिसर में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कविता और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें एनआईडीएम के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी भाषा

को प्रोन्नत करने के लिए एनआईडीएम द्वारा पोस्टरों, पुस्तक चिह्नों, पैम्पलेटों इत्यादि के रूप में अनेकों आई इ सी समाग्रियाँ हिंदी में तैयार की गई। अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचने के उद्देश्य से विभिन्न मॉड्यूलों को भी हिंदी में अनुदित की गई।

अध्याय



वित्त और लेखा

संस्थान के वित्त और लेखा विभाग के कार्यों में बजट लेखा, प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंधन, वार्षिक लेखा की तैयारी तथा संकलन, मंत्रालयों में ऑडिट किये हुए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति शामिल है। इसके अलावा विभाग प्रशासन संबंधी विविध मामलों पर तथा प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्तीय सलाह प्रदान करता है।

सामान्य निधि : संस्थान को संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान की जाती है। संस्थान की सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित वजट के अनुसार इस संस्था को निधि प्राप्त होती है।

- गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में एनआईडीएम के लिए 1,95,42,249/- रुपये पिछले

अनुपयुक्त अनुदान शेष के साथ-साथ कुल 10,00,00,000/- रुपये की अनुदान सहायता की मंजूरी दी गई।

- राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम, जिसके लिए इसे मंजूर की गई थी, पर केन्द्रीय क्षेत्र योजना के उद्देश्य से 9,57,65,207/-रुपये की राशी खर्च की गई, और
- 2,37,77,042/- रुपये शेष जो वर्ष के अंत में विना प्रयोग का रहा, वर्ष 2015-16 में भुगतान किये जाने वाले देय अनुदान में समायोजित किया जाएगा। वर्ष 2014-15 का तुलन पत्र अनुलग्नक IV में संलग्न है।

अनुलग्नक

- अनुलग्नक 1. एनआईडीएम द्वारा संपन्न कराये गये फेस-टु-फेस ट्रेनिंग की सूची
- अनुलग्नक 2. राज्य प्रशासनिक इकाई की सूची
- अनुलग्नक 3. संस्थान के सामान्य निकाय की बैठक के सदस्यों की सूची
- अनुलग्नक 4. वित्त और लेखा

अनुलग्नक 1. एनआईडीएम द्वारा संपन्न कराये गये फेस-टु-फेस (प्रत्यक्ष) ट्रेनिंग की सूची 2014-15

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि(याँ)	पाठ्यक्रम संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	विस्तृत भूकंप और भू-स्खलन आपदा जोखिम प्रबंधन (टीओटी)	एटीआई पश्चिम बंगाल	28-30 अप्रैल	सूर्य प्रकाश + परामर्शदाता	24
2.	शीघ्र दृश्य सर्वेक्षण द्वारा मकानों का भूकंपीय सुरक्षा आकलन (टीओटी)	याशदा, महाराष्ट्र	28 अप्रैल - 2 मई	सी घोश + परामर्शदाता	19
3.	हाइड्रो-जलवायु आपदाओं के न्यूनीकरण और प्रबंधन में पारिस्थितिक तंत्रिय पहुँच, डी एम विभाग, झारखंड के सहयोग से।	एसकेआईपीए, झारखंड	28 अप्रैल - 2 मई	अनिल के गुप्ता श्रीजा नायर	48
4.	आपदा स्थिति पर अनुक्रिया पर मौलिक पाठ्यक्रम (आग, पानी विशेष रूप से)	यूपीएएम, लखनऊ	1-3 मई	शेखर चतुर्वेदी पी के पाठक	24
5.	हिमालयी क्षेत्र के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	यू ए ओ ए, उत्तराखंड	20-22 मई	अनिल के गुप्ता परामर्शदाता	17'
6.	आई आर एस भीड़ प्रबंधन के उपकरण के रूप में, याशदा के सहयोग से	नासिक, महाराष्ट्र	20-22 मई	शेखर	43
7.	वन्यजीवन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव और न्यूनीकरण रणनीति	एमिटि विश्वविद्यालय	21-23 मई	ए डी कौशीक + परामर्शदाता	33
8.	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पर एकदिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एएससी गुवाहाटी	23 मई	श्रीजा नायर अनूपमा	16
9.	बड़ी दुर्घटना प्रबंधन	एनआईडीएम	26-27 मई	एस दलाल कनिष्क परामर्शदाता	41
10.	आपदाओं में सिविल प्रशासन और एजेंसी का एकीकरण	बीआईपीएआरडी, बिहार	4-6 जून	पी के पाठक + परामर्शदाता	49
11.	मकानों का आर वी एस रेट्रोफिटिंग	चंडीगढ़	2-6 जून	सी घोश	29
12.	वन्यजीवन और आपदा प्रबंधन (राज्य वन विभाग के कर्मचारियों और राज्य डी एम ए एस के लिए - राष्ट्रीय पाठ्यक्रम	एफआरआई, देहरादून	9-13 जून	ए डी कौशिक	17
13.	स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन पर टी ओ टी	एनआईडीएम	16-20 जून	रितु राज	22
14.	आपदा सुरक्षित पर्वत क्षेत्र विकास	एमएटीआई, मेघालय	23-27 जून	सूर्य प्रकाश	23
15.	नगर आपदा प्रबंधन योजना	एमसीआरएह आरडी संस्थान हैदराबाद	25-27 जून	सी बंदोपाध्याय शेखर चतुर्वेदी	26
16.	तीव्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण (टीओटी)	यूए, उत्तराखंड	2-6 जुलाई	सी घोश श्रीजा नायर अनिल के गुप्ता	22
17.	विस्तृत भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन	एफआरआई, देहरादून	7-11 जुलाई	सूर्य प्रकाश + परामर्शदाता	20
18.	रासायनिक (औद्योगिक) सुरक्षा आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम)	एमडीसी फओर एसएचडि ओडिसा	8-11 जुलाई	श्रीजा नायर	38

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि(याँ)	पाठ्यक्रम संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
19.	मौलिक आपदा प्रबंधन पर टी ओ टी	एमजीएसआईपीड पंजाब	14-18 जुलाई	शेखर चतुर्वेदी सुशमा गुलेरिया	33
20.	शिक्षकों के लिए स्कूल सुरक्षा पर टी ओ टी	एन आई डी एम	14-18 जुलाई	रितु राज	28
21.	विस्तृत भू-स्खलन आपदा जोखिम प्रबंधन	अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु	21-25 जुलाई	सूर्य प्रकाश + परामर्शदाता	35
22.	आ ई आर एस पर टी ओ टी पाठ्यक्रम: मौलिक और माध्यमिक	एनआईडीएम	21-25 जुलाई	पी के पाठक	28
23.	के आर पी पर आपदा प्रबंधन पर मौलिक पाठ्यक्रम, एन एल एम ए, भारत सरकार के सहयोग से	एटीआई मैसूर	22-24 जुलाई	शेखर चतुर्वेदी सी बंदोपाध्याय	30
24.	तत्काल दृश्य सर्वेक्षण द्वारा मकानों का भूकंपीय सुरक्षा आकलन पर टी ओ टी	एनआईडीएम	23-25 जुलाई	सी घोश रितु राज	27
25.	ग्रामीण विकास नीति और कार्यक्रम में आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन लोच का एकीकरण (टीओटी) (एनसीआरएमपी)	एन आई डी एम 4.8 अगस्त	के जे आनंदा + परामर्शदाता	सुशमा गुलेरिया शेखर चतुर्वेदी	8
26.	ग्राम्य आपदा विकास योजना का गठन (टीओटी)	जीइड, ओडिसा 4.8 अगस्त	सुशमा गुलेरिया	शेखर चतुर्वेदी	16
27.	तत्काल दृश्य सर्वेक्षण द्वारा मकानों का भूकंपीय सुरक्षा आकलन (टीओटी)	आईएमपीए, जे और के	5-7 अगस्त	सी घोश + परामर्शदाता	21
28.	शाश्वत विकास-योजना के लिए डी आर आर रणनीति और नीति उपकरण (संयुक्त सचिव/ सलाहकार स्तर के केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए डीओपीटी के साथ)	एन आई डी एम	21-22 अगस्त	अनिल के गुप्ता + परामर्शदाता	20
29.	स्कूल सुरक्षा जोखिम प्रबंधन पर सी बी एस इ दिल्ली के सहयोग से टीओटी	एनआईडीएम	25-29 अगस्त	रितु राज ए डी कौशिक	16
30.	आपदा मनो सामाजिक देखभाल पर टी ओ टी, नीमहंस बंगलोर के सहयोग से	एनआईडीएम	25-29 अगस्त	वरिष्ठ सलाहकार सलाहकार	18
31.	आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका	सी डी टी एस, गाजियाबाद	26-28 अगस्ता	शेखर और सुशमा गुलेरिय	29
32.	बायो- इंजिनियरिंग के साथ आधुनिक तकनीक से भू-स्खलन न्यूनीकरण, बी आर ओ, एनएचआई के लिए	एच आई पी ए, हिमाचल प्रदेश	25-29 अगस्त	सी घोश + सलाहकार	27
33.	एन सी सी और एन वाई के एस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	1-5 सितंबर	वरिष्ठ सलाहकार	34
34.	आई आर एस घटना कमांडर पर टी ओ टी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	8-9 सितंबर	पी के पाठक	13

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि(याँ)	पाठ्यक्रम संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
35.	आई आर एस संचालन अनुभाग मुख्य पर टी ओ टी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	10-12 सितंबर	पी के पाठक	13
36.	आपदा सुरक्षित पर्वतीय क्षेत्र विकास	एटीआई, नागालैण्ड	8-12 सितंबर	सूर्यप्रकाश + सलाहकार	26
37.	जिला आपदा प्रबंधन योजना का गठन	एसडीएमए, उत्तर प्रदेश	15-19 सितंबर	शेखर चतुर्वेदी + सलाहकार	27
38.	फयलिन चक्रवात 2013 का क्षति और प्रभाव आकलन	एनआईटी, राउरकेला	18-22 सितंबर	सी घोश	60'
39.	आपदा, अपातकाल और कलह के संबंध में पर्यावरणीय स्वास्थ्य	एनआईडीएम	24-25 सितंबर	अनिल के गुप्ता + सलाहकार	58
40.	वरिष्ठ स्तर के पत्रकारों के लिए आपदा प्रतिवेदन सिद्धांतों को फिर से जाँचना, पी आई ओ और पी आर ओ (टीओटी) (एनसीआरएमपी)	एनआईडीएम	24-26 सितंबर	के जे अनंदा कुमार सी बंदोपाध्याय	17
41.	स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन योजना (टीओटी)	एनआईडीएम	13-15 अक्टूबर	रितु राज	12
42.	जंगल आग आपदा जोखिम न्यूनीकरण और अनुक्रिया	एफआरआई, देहरादून	13-17 अक्टूबर	ए डी कौशिक + सलाहकार	10
43.	नगर आपदा प्रबंधन योजना	यूपीएएम, उत्तरप्रदेश	15-17 अक्टूबर	सी बंदोपाध्याय शेखर चतुर्वेदी	22
44.	आपदा प्रबंधन पर दिशा निर्धारण कार्यक्रम (गृह सुरक्षा तैयारी) आंतरिक व्हील क्लब औरतों के लिए	एनआईडीएम	27 अक्टूबर	वरिष्ठ परामर्शदाता कनिष्ठ परामर्शदाताए	25
45.	खाद्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एटीआई, पश्चिम बंगाल	27-31 अक्टूबर	डी कौशिक सी बंदोपाध्याय	24
46.	खाद्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	डीडीयूएसआई आर डी, यू पी	27-31 अक्टूबर	सूर्यप्रकाश + सलाहकार	23
47.	सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण	यूपीएएम	27-28 अक्टूबर,	श्रीजा नायर और अनूपमा सेठी	33
48.	नागरिक रक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	10-14 नवंबर,	वरिष्ठ परामर्शदाता	29
49.	ए और एन प्रशासन के सहयोग से स्कूल सुरक्षा	पोर्ट ब्लेयर	13-14 नवंबर,	रितु राज ए डी कौशिक	151'
50.	मौलिक आपदा प्रबंधन पर टी ओ टी	गुरु नानक व वि वि अमृतसर	17-19 नवंबर,	सुषमा गुलेरिया एस चतुर्वेदी अनूपमा सेठी	25
51.	खाद्य जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईएच, रुड़की	19-21 नवंबर,	ए डी कौशिक + सलाहकार	23

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि(याँ)	पाठ्यक्रम संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
52.	राष्ट्रीय प्राणिविज्ञान उद्यान के कर्मचारी के लिए आपदा प्रबंधन (एन जे पी)	एनआईडीएम	21 नवंबर	मेजर जनरल वी के नायक डॉ अमीर अली खान डॉ सुषमा गुलेरिया डॉ सौरभ दलाल	40
53.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	1-5 दिसंबर	अजिंदर बालिया	30
54.	नगर आपदा प्रबंधन योजना	एटीआई, मिजोरम	3-5 दिसंबर	सी बंदोपाध्याय	15
55.	भीड़ प्रबंधन: याशदा पुणे के सहयोग के साथ आई आर एस एक उपकरण के रूप में	नासिक	3-5 दिसंबर	पी के पाठक	54
56.	मौलिक आपदा प्रबंधन में टीओटी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	8-12 दिसंबर	सुशमा गुलेरिया + परामर्शदाता	12
57.	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विधिक संरचना और नीति (एसडीएमए और केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए)	एनआईडीएम	10-12 दिसंबर	श्रीजा नायर अनिल के गुप्ता	20
58.	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम प्रबंधन का एकीकरण (संदर्भ तटीय क्षेत्र प्रबंधन) एम ओ इ एफ के साथ संयुक्त रूप से	एमसीआरएच आर डी संस्थान, हैदराबाद	15-17 दिसंबर अनिल के गुप्ता	श्रीजा नायर	17
59.	जानकारी और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा संस्कृति का सृजन (टीओटी) एनसीआरएमपी	एनआईडीएम	15-19 दिसंबर	के जे अनंदा कुमार	18
60.	तटीय समुदाय लोचता	एटीआई, पश्चिम बंगाल	22-24 दिसंबर	सुशमा गुलेरिया + परामर्शदाता	25
61.	लोक प्रशासन में पेशेवर कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	26 दिसंबर	अजिंदर बालिया श्रीजा नायर एस चतुर्वेदी पी के पाठक	17
62.	आई आर एस योजना प्रमुख पर टी ओ टी पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	12-16 जनवरी	अशोक शर्मा	16
63.	आपदा जोखिम प्रबंधन पर लिंग मुद्दे	एनआईडीएम	19-23 जनवरी	अजिंदर बालिया श्रीजा नायर	23
64.	भीड़ प्रबंधन- इ ओ सी यासदा के सहयोग से	नासिक	20-22 जनवरी	एस चतुर्वेदी पी के पाठक	48
65.	स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन पर टीओटी	एनआईडीएम	28-30 जनवरी	रितु राज	29
66.	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पर टीओटी (आईडीआरएन)	आईएलडीएम, केरल	28 जनवरी 15	श्रीजा नायर और अनूपमा सेठी	35
67.	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पर टी ओ टी (आईडीआरएन)	एटीआई लक्ष्यद्वीप	30 जनवरी 15	श्रीजा नायर और अनूपमा सेठी	20
68.	मौलिक आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम (टीओटी)	एनआईडीएम	9-13 फरवरी	सूर्य प्रकाश	37

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	तिथि(याँ)	पाठ्यक्रम संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
69.	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में वन्यीकरण जीविका के रूप में (उत्तराखंड आपदा 2013 के विशेष संदर्भ में)	एफआरआई, देहरादून	9-13 फरबरी	ए डी कौशिक सी बंदोपाध्याय	13
70.	आई आर एस पर टी ओ टी पाठ्यक्रम: लॉजिस्टिक अनुभाग प्रमुख	एन आई डी एम	16-20 फरबरी	पी के पाठक	27
71.	अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन (टीओटी) (एनसीआरएमपी)	एन आई डी एम	16-20 फरबरी	के जे अनंदा कुमार + परामर्शदाता	29
72.	डीडीएमपी का गठन	एचसीएमआर आईपीए, राजस्थान	18-20 फरबरी	शेखर चतुर्वेदी सुशमा गुलेरिया	26
73.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	ए टी आई, कर्नाटक	23-27 फरबरी	के जे अनंदा कुमार + परामर्शदाता	26
74.	औद्योगिक (रासायनिक) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा अनुक्रिया	एचसीएमआर आईपीए, राजस्थान	23-27 फरबरी	श्रीजा नायर अनिल के गुप्ता	26
75.	बड़े भगदड़ जिखिम न्यूनीकरण का प्रबंधन	एनआईडीएम	16-18 मार्च	शेखर चतुर्वेदी पी के पाठक	22
76.	लिंग और और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	16-20 मार्च	अजिंदर वालिया	20
77.	खाद्य जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन	एनआईडीएम	23-27 मार्च	ए डी कौशिक	43
	कुल				1932 = (2160-228)*

* नोट : तीन कार्यक्रम के प्रतिभागियों की विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं है। सिर्फ भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उपलब्ध है।

अनुलग्नक 2. राज्य प्रशासनिक इकाई की सूची

क्र सं	राज्य	नाम और पता
1.	आंध्र प्रदेश श्रीमती अनीता रामचंद्रन, आई इ एस कमिश्नर ए एम आर आंध्रप्रदेश अकादमी ग्रामीण विकास (ए पी ए आर डी), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, 500 030 आंध्रप्रदेश, भारत वेबसाइट: http://apard.gov.in/center_cmed.html	दूरभाष: 040-24015959, 24014027, 24015337, 24018656, फैक्स: 91 40 24017005
2.	अरुणाचल प्रदेश श्रीमती नंदनी पालिवाल, आई इ एस निदेशक जेनरल (प्रशिक्षण) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान डी-सेक्टर, नहरलागुम, जिला पापुमपारा, अरुणाचल प्रदेश	दूरभाष: 0360-2244383 (O), 2244036 (F) फैक्स: 0360.2243245 इ-मेल: director@agni.erist.ac.in
3.	असम श्री अंजन चक्रवर्ती, आई इ एस निदेशक (प्रशिक्षण) असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, जवाहर नगर, पी ओ खानापारा, गुवाहाटी-781022, असम वेबसाइट: http://aasc.nic.in/	दूरभाष: (O) 0361-2361547, 2362442, 23263325 फैक्स: 0361-2362361 इ-मेल: director@aasc.gov.in
4.	असम प्रोफेसर एम के चतुर्वेदी उप-कुलसचिव 3, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, नापाम, जिला सोनितपुर, असम-784 028. वेबसाइट: http://www.tezu.ernet.in/cdm	दूरभाष: (O) 3712-267007/8/9 फैक्स: 03712.267005 / 6 इ-मेल: admn@tezu.ernet.in
5.	बिहार श्री अमीर सुभानी, आई इ एस निदेशक जेनरल बिहार लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी कम्प्लेक्स, फुलवारी सरीफ, पटना-801505, बिहार वेबसाइट: http://bipard.bih.nic.in	दूरभाष: 0612.2452585 फैक्स: 0612-2452586 इ-मेल: dgbipard@yahoo.in , dg@bipard.in
6.	छत्तीसगढ़ श्री सुनील कुमार, आई इ एस निदेशक जेनरल छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, इंद्रावती खमड मंत्रालय परिसर, रायपुर	दूरभाष: 0771-2221280, 2222844 फैक्स: 0771-4080295, 4281280 दूरभाष: 9424200829 इ-मेल: dg.cgsaa@gmail.com
	श्री एम के त्यागी, आई इ एस निदेशक, सी जी ए ए	दूरभाष: 0771-2221279 फैक्स: 0771- 4080295, 4281280 इ-मेल: mk.tyagi@nic.in
7.	दिल्ली श्री आसुतोश कुमार निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण निदेशक यू टी सिविल सेवा, संस्थानिक क्षेत्र, विश्वास नगर, शहादरा, दिल्ली-110032 वेबसाइट: http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DoIT_ UTCS/utcs/home	दूरभाष: (O) 22304439, 2238556 फैक्स: 22308556 9818803606 (M)

क्र सं	राज्य	नाम और पता
8.	गुजरात श्री वी तिरुपुगज, आई इ एस कार्यकारी निदेशक, जी आई डी एम और अतिरिक्त सी इ ओ, जी एसडीएमए, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, गुजरात सरकार, ब्लॉक संख्या 11, 5 सतह, सेक्टर-11, उद्योग भवन गाँधीनगर, गुजरात वेबसाइट: http://www.gsdma.org/gidm/gidm.aspx	दूरभाष: 079-23259303, 23259246 फैक्स: 079-23259275
9.	हरियाणा श्री रंजीव सिंह दलाद, आई पी एस निदेशक जेनरल हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एच आई पी ए) कंप्लेक्स-76, सेक्टर-18, गुडगाँव-122001, हरियाणा वेबसाइट: http://hipaco.in/	दूरभाष: (O) 0124.2340690, 2340691 फैक्स: 0124-2340463, 2348452 इ-मेल: devendras@hipa.in
10.	हिमाचल प्रदेश श्रीमती मधुबाला शर्मा, आई इ एस निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फुरलॉन, शिमला-171012, हिमाचल प्रदेश वेबसाइट: http://himachal.nic.in/hipa	दूरभाष: (O) 0177-2734777, 2734666 फैक्स: 0177-2734679 इ-मेल: hipa-hp@nic.in
11.	जम्मू और कश्मीर डॉ अंजुम कुमार, आई इ एस निदेशक जेनरल जम्मू और काश्मीर प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान, (आई एम पी ए), 3 मंचिल, विकास भवन, रेल हेड कंप्लेक्स, जम्मू - 180004 वेबसाइट: http://jkimpa.nic.in	दूरभाष: (O) 0194-2472564, 2479616 (Srinagar) फैक्स: 0194-2472825 (Srinagar) दूरभाष: 0191-2474389, 0191.2473307 फैक्स: 0191-2479909, 2473778 (Jammu)
12.	झारखंड श्री सुधीर प्रसाद, आई इ एस डायरेक्टर जेनरल श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, मिउर्स ड, पोस्ट- राँची यूनिवर्सिटी, राँची-834008, झारखंड वेबसाइट: http://skipa.nic.in/disaster.htm	दूरभाष: 0651-2283804 फैक्स: 0651-2283806 इ-मेल: skipa.ranchi-jhr@nic.in , skiparanchi@yahoo.co.in
13.	कर्नाटक श्री एम लक्ष्मीनारायण, आई इ एस निदेशक जेनरल, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान पी ए नं. 2, ललिता महल रोड, मैसूर-570011, कर्नाटक वेबसाइट: http://www.atimysore.gov.in	दूरभाष: (O) 0821-2520906, 0821-2520904 फैक्स: 2523899, 2520906 इ-मेल: dgatimysore@gmail.com
14.	केरल डॉ केषव मोहन निदेशक भू और आपदा संस्थान प्रबंधन पी टी पी नगर, निर्मिथी केन्द्र के पास, त्रिवेन्द्रम-695038, केरल वेबसाइट: http://ildm.kerala.gov.in	दूरभाष: 0471-2362885 (director) (O), 2365559 फैक्स: 0471.2365559
15.	मध्य प्रदेश श्री संजीव, आई ए एस कार्यकारी निदेशक आपदा प्रबंधन संस्थान पर्यावरण परिसर, इ-5, अरेरा काँलोनी, पी बी नं. 563 भोपाल-462016, मध्य प्रदेश (भारत) वेबसाइट: http://www.dmibhopal.nic.in	दूरभाष: (O) 0755-2461538, 2466715, 2464239 फैक्स: 0755.2466653 इ-मेल: dmi@dmibhopal.nic.in

क्र सं	राज्य	नाम और पता
16.	महाराष्ट्र श्री आनंद लिमाये, आई ए एस निदेशक जेनरल यशवंत चव्हाण विकास अकादमी प्रशासन, राज भवन कंप्लेक्स, बनेर रोड, गणेशखिण्ड, पुणे-410017, महाराष्ट्र वेबसाइट: http://www.yashada.org	दूरभाष: 020-25608209 / 296 फैक्स: 020-25608269 / 100 इ-मेल: cdm.yashada@gmail.com , yashada@vsnl.com , ramaniv@gmail.com
17.	मणिपुर डॉ सुहैल अख्तर, आई ए एस राहत और आपदा आयुक्त प्रबंधन और निदेशक, डी एम आइ मणिपुर सरकार, सचिवालय एनेक्स भवन, कमरा संख्या. 115, उत्तरी ब्लॉक, इंफाल-795001	दूरभाष: 0385-2440736- फैक्स: 0385-2450157 Mob: 09402414682 इ-मेल: drsuhelakhtar@gmail.com
18.	मेघालय श्रीमती आर वी सुचंग, आई ए एस निदेशक मेघालय प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान (एम ए टी आई), आई गी पी प्वाइंट, अतिरिक्त सचिवालय भवन के पीछे, सिलॉग-793001, मेघालय वेबसाइट: http://www.mati.gov.in	दूरभाष: (O) 0364-2210132, 2223578, 2224670 फैक्स: 0364-2226039, 2225978 (CS), इ-मेल: rvsddd@gmail.com
19.	मिजोरम श्री के रियाचो, आई ए एस निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नई कैपिटल कंप्लेक्स, खाटला, आइजल, मिजोरम -796 001 वेबसाइट: http://mizoram.nic.in/ATI/About.htm	दूरभाष: (O) 0389-2335830 फैक्स: 0389.2335831
20.	नागालैण्ड श्रीमती लिथरोंगला जी. चिसी, आई ए एस निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पी बाँक्स-162, किमहो, कोहिमा-797003, नागालैण्ड वेबसाइट: http://atingl.nic.in	दूरभाष: (O) 0370-2280063 / 66, फैक्स: 0370-2280067
21.	ओडिसा श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, आई ए एस निदेशक जेनरल-प्रशिक्षक समन्वयक, गोपबंधु प्रशासनिक अकादमी, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर -751023, ओडिसा वेबसाइट: http://www.gopabandhuacademy.gov.in	दूरभाष (O) 0674-2300743, 2300981 फैक्स: 0674-2301530 इ-मेल: atiodisha@gmail.com
22.	पंजाब श्री सर्वेश कुशाल, आई ए एस निदेशक जेनरल महात्मा गाँधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, पंजाब, सेक्टर 26, संत कबीर स्कूल के पास, चंडीगढ़-160019, पंजाब वेबसाइट: http://www.mgsipap.org	दूरभाष: Fax (O) 0172-2792114 फैक्स: 2793588.91 इ-मेल: dg.mgsipa@punjab.gov.in
23.	राजस्थान सुश्री गुरजीत कौर, आई ए एस निदेशक जेनरल एह सी एम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन समस्थान, जवाहर नेहरू मार्ग, जयपुर -302017, राजस्थान वेबसाइट: http://www.hcmripa.gov.in/dmgmt.html	दूरभाष: (O) 2706556, 2704950.56 फैक्स: 0141-2705420, 2702542 दूरभाष: Udaipur -0294-2431355 Email: hcmripa@rajasthan.gov.in

क्र सं	राज्य	नाम और पता
24.	सिक्किम डॉ पी पी ध्यानी निदेशक जी बी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान, सिक्किम इकाई, गंगटोक मुख्यालय- कोशी कटरमल, अलमोरा-263643 उत्तराखंड (सिक्किम इकाई) वेबसाइट: http://gbpihed.gov.in/Sikkim_Unit_details.html	दूरभाष: 05962.241015 फैक्स: 05962.241150 ई-मेल: psdir@gbpihed.nic.in
25.	तमिलनाडु श्री थिरु मोहन वर्गीज चुनकठ, आई ए एस निदेशक ए आई एम और डी जी प्रशिक्षण प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, 163/1, पी एस कुमारस्वाकी, राजा सलाइ, ग्रीनवेज रोड, चेन्नई-600028, तमिलनाडु वेबसाइट: http://www.annainstitute.org	दूरभाष: (O) 044-24938247, 24937062, 24937170 फैक्स: 044.24937062 ई-मेल: diraim@tn.gov.in
26.	त्रिपुरा श्री जी के राव, आई ए एस निदेशक जेनरल राज्य लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (एस आई पी ए आर डी), केम्पर बाजार, ए डी नगर, पी ओ एस डी मिशन, केम्पर बाजार, अगरतल्ला, त्रिपुरा पश्चिम-799003 वेबसाइट: http://www.sipard.nic.in	दूरभाष: (O) 0381-2374048, 2376036 फैक्स: (0381) 2230613 Email: sipard@rediffmail.com
27.	उत्तर प्रदेश श्री किषोर कुमार सिन्हा, आई ए एस निदेशक जेनरल उत्तर प्रदेश प्रशासनिक और प्रबंधन संस्थान सेक्टर 'डी', अलिगंज, लखनऊ -226024, उत्तर प्रदेश वेबसाइट: http://www.upacademy.org/disatermgmt.htm	दूरभाष: 0522-2336292, 2335158 2329082, 2379739 (DG (O) फैक्स: 0522.2386747 ई-मेल: dg@upacademy.org
28.	उत्तराखंड श्री अक्नेन्द्र सिंह नायल, आई ए एस निदेशक जेनरल (प्रभारी) उत्तराखंड प्रशासनिक संस्थान आर्डवेल कैंप, मलितल नैनीताल-263001, उत्तराखंड वेबसाइट: http://uaoa.gov.in/index.php?mod=content&page=79	दूरभाष: (O) 05942-239114, 236149 फैक्स: 05942-239114, 237642 ई-मेल : directoracademy@hotmail.com
29.	उत्तराखंड डॉ पीयूस रौतेला कार्यकारी निदेशक आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केन्द्र, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखंड सचिवालय, राजपुर रोड, देहरादून-248001 उत्तराखंड वेबसाइट वेबसाइट: http://dmmc.uk.gov.in	दूरभाष: (O) 0135-2710232, 2710233 फैक्स: 0135-2710199, 2710334, 2710335, 2710233
30.	पश्चिम बंगाल डॉ सुबेष् कुमार दास, आई ए एस ए सी एस - निदेशक जेनरल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार एफ सी ब्लॉक, सेक्टर 3, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700 106 वेबसाइट: http://atiwb.gov.in/NDM.htm	दूरभाष: (O) 033-23373960, 23596721, 22477727 फैक्स: 033.23373960 ई-मेल: director@wbati.org

अनुलग्नक 3. संस्थान के सामान्य निकाय की बैठक के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	सदस्य	
1.	माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली –110011	अध्यक्ष
2.	माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, एन डी एम ए भवन, ट्राउमा केन्द्र, ए आई आई एम एस, ए-1, सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, एन डी एम ए भवन, ट्राउमा केन्द्र, ए आई आई एम एस, ए-1, सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
4.	केन्द्रीय गृह सचिव, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5.	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सचिव, विदेश मंत्रालय, दक्षिणी ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
8.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
9.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तकनीकी भवन, नई मेहरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
10.	सचिव, आणविक उर्जा विभाग, दक्षिणी ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
11.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
12.	सचिव, भू-विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लावक संख्या. 12, सिजि ओ कंकलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003	सदस्य
13.	सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
14.	अतिरिक्त सचिव और वित्त परामर्शदाता, गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
15.	सचिव/अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, एन डी एम ए भवन ट्राउमा केन्द्र, ए आई आई एम एस, ए-1, सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली,	सदस्य
16.	निदेशक जेनरल, सिविल रक्षा और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, पूर्वी ब्लॉक-7, आर के पुरम, नई दिल्ली –66	सदस्य
17.	समेकित रक्षा स्टाँफ का उपाध्यक्ष, डॉक्ट्रिन संगठन और प्रशिक्षण (डी ओ टी) , आई डी एस, मुख्यालय समेकित रक्षा स्टाँफ, 23 दक्षिण हटमेंट, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001	सदस्य
18.	सचिव (आपदा प्रबंधन), गुजरात सरकार, उत्पाद-शुल्क विभाग ब्लॉक – 11, 3 मंजिल, नई सचिवालय, गांधीनगर – 382010	सदस्य
19.	सचिव (आपदा प्रबंधन), आपदा प्रबंधन विभाग, बहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना – 800 015	सदस्य
20.	उप-कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, कश्मीरी गेट, दिल्ली –110 006	सदस्य
21.	सचिव, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी – 248 179.	सदस्य
22.	निदेशक, सरदार बल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, शीवरामपल्ली, हैदराबाद – 500 052.	सदस्य

क्र. सं.	सदस्य	
23.	निदेशक जेनरल, भारत मौसमविज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
24.	निदेशक, प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, जोका, डी एच रोड कोलकाता -700 104.	सदस्य
25.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड।	सदस्य
26.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
27.	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
28.	निदेशक जेनरल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
29.	निदेशक जेनरल, आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030.	सदस्य
30.	निदेशक जेनरल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वी रामलिंगास्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली -110 029.	सदस्य
31.	अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, 159 श्रद्धा कुंज, बसंत विहार, चक्रता रोड, देहरादून	सदस्य
32.	राष्ट्रीय भूकंप सलाहकार, गृह मंत्रालय, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
33.	सी एम डी, सामान्य बीमा आयोग, सुरक्षा, जे टाटा रोड चर्च गेट, मुंबई -400 020.	सदस्य
34.	सी एम डी, इलाहाबाद बैंक, मुख्यालय, 2, एन एस रोड, कोलकाता- 700 001	सदस्य
35.	अध्यक्ष, भारतीय व्यवसाय और उद्योग चौबेर संघ (फिक्की), संघ हाउस नई दिल्ली	सदस्य
36.	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ (सी एम), कोर 4-ए, 4वीं मंजिल, भारतीय हैबिटेड केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.	सदस्य
37.	निदेशक, अखिल भारत आपदा न्यूनीकरण संस्थान, 411, साकर पाँच, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम रोड अहमदाबाद -9.	सदस्य
38.	सचिव जेनरल, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, 1 रेड क्रॉ रोड, नई दिल्ली	सदस्य
39.	निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, उपाल रोड, हैदराबाद - 500 007.	सदस्य
40.	निदेशक जेनरल, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
41.	प्रोफेसर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आई आई पी ए परिसर, आई पी इस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110002	सदस्य
42.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आई आई पी ए परिसर, आई पी इस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110002	सदस्य सचिव

अनुलग्नक 4: वित्त और लेखा

P. K. Singhal & Co.
Chartered Accountants



E-24, IInd Floor, Jawahar Park,
Laxmi Nagar, Delhi-110092
Ph. : 011-22013773, Fax: 011-22013772
Mob. : 09313088386

To
The governing Body
National Institute of Disaster Management.
New Delhi.

1. We have audited the attached Financial Statements of **National Institute of Disaster Management** which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, the Income & Expenditure Account (Maintained on Cash Basis) and Receipt and Payment Account for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies annexed thereto.

2. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Auditee. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. AUDITORS' RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the auditee's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



B.O. : * Delhi * Noida * Dehradun * Modinagar

P. K. Singhal & Co.
Chartered Accountants



E-24, IInd Floor, Jawahar Park,
Laxmi Nagar, Delhi-110092
Ph. : 011-22013773, Fax : 011-22013772
Mob. : 09313088386

4. Further to our comments given above & comments in the annexure referred to above, we report that :-

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) In our opinion proper books of accounts(maintained on cash basis) as required by the law have been kept by the auditee far as it appears from our examination of the books.
- (iii) The Balance Sheet and Income and Expenditure account dealt with by this report are in agreement with the books of account.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, our report is subject to the following observations:-

The said accounts read together with the Significant Accounting & Management Policies, Contingent Liability and Notes on Accounts in Schedule -11 give the information required by the law in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :-

- i) In the case of the Statement of Affairs of the National Disaster Management as at 31.03.2015; and
- ii) In the case of the Income and Expenditure Account, of the "Excess of the Income over Expenditure" for the year ended on that date.

Place: Delhi

Date: 30/10/2015

For P. K. SINGHAL & CO.

Chartered Accountants

(Partner)

M. No. 073882

Firm Reg. No. 05051C

B.O. : * Delhi * Noida * Dehradun * Modinagar

**PUBLIC LEDGRE ACCOUNT(PLA)
(NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT)
(Ministry of Home Affairs)**

PLA BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(Amount in Rs.)			
PARTICULARS	SCHE- DULE	31.03.2015	31.03.2014
		RS	RS
<u>CORPUS FUND AND LIABILITIES</u>			
CAPITAL AND RESERVE & SURPLUS	'1'	731,560.00	731,560.00
EARMARKED FUNDS	'2'	2,453,782.14	3,106,239.14
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'3'	575,224.00	535,235.00
TOTAL		3,760,566.14	4,373,034.14
<u>ASSETS</u>			
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	'4'	3,760,566.14	4,373,034.14
TOTAL		3,760,566.14	4,373,034.14

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND
NOTES TO THE ACCOUNTS

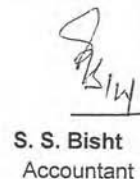
In terms of Our Report on the even date attached.

For P K SINGHAL & CO.
Chartered Accountants
Firm's Reg No. 05051C


CA P K SINGHAL
Partner
M.No. 073882

For National Institute of Disaster Management


Dr. Santosh Kumar
Executive Director


S. S. Bisht
Accountant

Place: New Delhi
Date: 30th October, 2015

P. K. Singhal & Co.
Chartered Accountants



E-24, IInd Floor, Jawahar Park,
Laxmi Nagar, Delhi-110092
Ph. : 011-22013773, Fax : 011-22013772
Mob. : 09313088386

FORM GFR 19-A

[See Govt. of India Decision (1) below Rule 150]

UTILIZATION CERTIFICATE

S.No.	Letter no. And date	Amount (Rs.)	Certified that out of Rs. 10,00,00,000/- of grants-in-aid sanctioned during the tear 2014-15 in favour of National Institute of Disaster Management having its office at IIPA Campus,I.P Estate, New Delhi-110002,under the Ministry of Home Affairs, Letter no. Given in the margin and the unutilized grant balance of Rs. 1,95,42,249/- brought from previous year, an amount of Rs. 9,57,65,207/- has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 2,37,77,042/-remaining unutilized at the end of the year will be adjusted towards grants-in-aid payable during the next year.
1.	45-16/2014-NDM-II Dated 10 th July, 2014	Rs.4,00,00,000/-	
2.	45-16/2014-NDM-II Dated 31 st October, 2014	Rs, 6,00,00,000/-	
	Total	Rs.10,00,00,000/-	
3.	Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid were sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.		



B.O. : * Delhi * Noida * Dehradun * Modinagar

P. K. Singhal & Co.
Chartered Accountants

CA

E-24, IInd Floor, Jawahar Park,
Laxmi Nagar, Delhi-110092
Ph. : 011-22013773, Fax : 011-22013772
Mob. : 09313088386

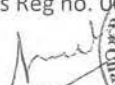
Kinds of checks exercised

Verification of documentary evidence including bills, payment vouchers, Bank statements and examination of the books of account.

For P. K. SINGHAL & CO.,

For, National Institute of Disaster Management

Chartered Accountants
Firm's Reg no. 005051C


Praveen Kumar Singhal
(Partner)
M.No. 073882




Dr. Santosh Kumar
(Executive Director)


S. S. BISHT
(Accountant)

Place: New Delhi
Date: 30/10/2015

B.O. : * Delhi * Noida * Dehradun * Modinagar

NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT
(Ministry of Home Affairs)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	SCHE- DULE	31.03.2015	31.03.2014
		RS.	RS.
INCOME/GRANT FROM(MHA)			
Grant in Aid Received from MHA	6	100,000,000.00	90,000,000.00
Total A		100,000,000.00	90,000,000.00
EXPENDITURE (MHA-Grant)			
Establishment Expenses	7	37,857,896.00	34,756,604.00
Other Administrative Expenses	8	38,471,626.00	38,983,881.00
Expenditure on Training Programmes/Workshops	9	18,006,726.00	14,555,968.00
Depreciation	3	1,557,769.91	21,550,873.09
Total B		95,894,017.91	109,847,326.09
BALANCE BEING THE SURPLUS/DEFICIT FROM MHA FUND (A-B)		4,105,982.09	(19,847,326.09)
INCOME/ EXPENDITURE FROM OTHER SOURCES			
Interest Earned (CPF)	10	2,595,108.00	2,078,938.00
Income/Expenditure from Other sources	10	2,861,541.00	1,814,700.00
Total C		5,456,649.00	3,893,638.00

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND
NOTES TO THE ACCOUNTS

11

As per our report on the Balance Sheet date

For P. K. Singhal & Co.,
Chartered Accountants
Firm's Reg.No. 05051C

Praveen Kumar Singhal
M.No. 073882
Place: New Delhi
Date: 30th October, 2015



For National Institute of Disaster Management

Dr. Santosh Kumar
Executive Director

S. S. Bisht
Accountant




NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.03.2015		31.03.2014	
	RS.	RS.	RS.	RS.
RECEIPTS				
OPENING BALANCE				
Cheque issued but not presented for fixed deposit	2,271,324.00		-	-
Bank Balances (Current Account)	(11,968,795.01)		(5,899,174.01)	
Bank Balances (CPF Fixed Deposits)	25,062,771.00		20,440,381.00	
Bank Balances (Others Fixed Deposits)	37,682,947.00	53,048,246.99	33,305,800.00	47,847,006.99
GRANT RECEIVED FROM				
MHA for Scheme on NDM Programme (Revenue)	100,000,000.00		90,000,000.00	
MHA for Scheme on NDM Programme (Capital)	10,000,000.00		-	
Unutilized fund received in NPCEBERM/NPCBAERM Project	-		226,905.00	
Receipt from NDMA for NDRR Day	-		480,000.00	
Receipt for African Programme	1,700,000.00		-	
Unutilized fund received from ATI's	-		771,492.00	
Receipt from NPCDRR programme	-		92,216.00	
		111,700,000.00		91,570,613.00
Receipt from employee payable to PAO MHA	58,295.00		-	
Bank Interest	2,861,541.00		686,287.00	
Interest on FD capitalised with CPF	2,595,108.00		2,404,197.00	
Stale Cheques	140,400.00			
C. Provident Fund	1,738,911.00		1,670,471.00	
Security Deposit	141,809.00	7,536,064.00	106,850.00	4,867,805.00
Electricity/Water bill received from SAARC/IHD	1,165,121.00		894,817.00	
Misc. Receipt	-		37,800.00	
Loan & Advances (Net)	10,647.00	1,175,768.00	-	932,617.00
TOTAL		173,460,078.99		145,218,041.99



PAYMENTS				
CAPITAL EXPENDITURE/OTHER LIABILITIES				
Machinery and Equipment	589,921.00		1,502,242.00	
Library	390,991.00		384,262.00	
Furniture & Fixture	448,047.00	1,428,959.00	137,969.00	2,024,473.00
Paid to Govt for other Income		4,361,127.00		
REVENUE EXPENDITURE				
Training Programme/workshops	16,595,562.00		13,351,961.00	
Trg Programe for NDMA Fund	-	16,595,562.00	4,390,176.00	17,742,137.00
Loan & Advance (Net)	-		131,202.00	
				131,202.00
Establishment Expenses				
Salary and Allowances	32,266,638.00		29,100,705.00	
Leave Travel Concession/LTA	669,668.00		382,086.00	
Bonus	75,988.00		82,896.00	
LSPC	-		49,020.00	
Medical	171,989.00		537,277.00	
Tution Fees	225,240.00	33,409,523.00	163,447.00	30,315,431.00
Withdrawals/Advances from Provident Fund	868,333.00		150,000.00	
Security Deposit	-		104,980.00	
Expense payable	3,109,033.00	3,977,366.00	1,786,010.00	2,040,990.00
Other Administrative Expenses				
Repair and Maintenance	1,705,480.00		2,295,625.00	
Postage	464,625.00		229,263.00	
Printing and Stationery	732,983.00		601,285.00	
Electricity & Water charges	2,905,537.00		2,802,780.00	
Rent, Rates and Taxes	12,889,854.00		11,586,384.00	
Miscellaneous Expenses	1,314,569.00		587,958.00	
News papers and Periodicals	94,687.00		77,913.00	
Telephone Expenses	618,562.00		549,635.00	
Advertisement Expenses	14,457,401.00		18,423,295.00	
Domestic Travel	1,083,296.00		1,069,841.00	
Foreign Travel	344,052.00		522,353.00	
Professional charges	45,326.00		45,326.00	
Publication	1,619,954.00		264,389.00	
Bank Charges	23,108.00		2,883.00	
Research & Development	888,544.00		796,632.00	
Office Building Survey	-		60,000.00	
Expenditure on Training Programme/Workshop		39,187,978.00		39,915,562.00
South Africa Prog. Expenses		1,700,000.00		
CLOSING BALANCE				
Cheque issued but not presented for fixed deposit	-		2,271,324.00	
Bank Balances (CPF,Fixed Deposits)	32,442,792.00		25,062,771.00	
Bank Balances (Other Fixed Deposits)	49,502,112.00		37,682,947.00	
Bank Balances (Current Account)	(9,145,340.01)	72,799,563.99	(11,968,795.01)	53,048,246.99
TOTAL		173,460,078.99		145,218,041.99

As per Our Report on the Balance Sheet

For P. K. Singhal & Co.

Chartered Accountants

Firm's Reg. No. 050510

Praveen Kumar Singhal

M.No. 073882

Place: New Delhi

Date: 30th October, 2015

For National Institute of Disaster Management

Dr. Santosh Kumar
Executive Director

S. S. Bisht
Accountant

NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT (PLA)		
(Amount in Rs.)		
SCHEDULE -1 : CORPUS/CAPITAL FUND		
	31.03.2015	31.03.2014
	RS.	RS.
Opening Balance	731,560.00	731,560.00
TOTAL	731,560.00	731,560.00
SCHEDULE : '2' EARMARKED FUNDS		
PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
	RS.	RS.
1 Funds Received from New Okhla Industrial Development Authority for preparation of 'Disaster Management Plan'		-
Opening Balance	770,249.00	-
ADD : Received during the year	770,249.00	770,249.00
	770,249.00	770,249.00
2 Funds Received from NDMA for Cyclone Risk Mitigation Project		-
Opening Balance	-	1,681,649.00
Received during the year	-	1,108,465.00
Add : Advance given for Expenses	-	19,250.00
	-	2,807,364.00
Less : utilization during the year	-	1,687,065.00
Less : amount transfer to separate a/c	-	1,120,299.00
	-	-
3 Funds Received from MOST for for Brain storming Climate Change Programme		-
Opening Balance	400,000.00	400,000.00
Received during the year	400,000.00	400,000.00
	400,000.00	400,000.00
4 Funds Received from NDMA for Preparation of NH&CD Plan		-
Opening Balance	689,000.00	689,000.00
Received during the year	-	-
	689,000.00	689,000.00
5 Funds Received from MCD for forensic investigation project		-
Opening Balance	131,892.00	380,211.00
Received during the year	-	-
Unutilised fund received from employee	-	689.00
	131,892.00	380,900.00
LESS : Utilization/Expenditure during the year	131,892.00	249,006.00
	-	131,892.00
6 Funds Received from Online-WBI courses		-
Opening Balance	564,092.14	1,709,285.14
Received during the year	667,752.00	504,448.00
	1,231,844.14	2,213,733.14
LESS : Utilization/Expenditure during the year	1,188,317.00	1,649,641.00
	43,527.14	564,092.14
7 Funds Received from SAARC for SADKN Project		-
Opening Balance	103,780.00	309,264.00
Received during the year	-	-
Savings reversed from Govt. A/c	-	-
	-	309,264.00
LESS : Utilization/Expenditure during the year	-	205,484.00
LESS : savings deposited to Govt. a/c	-	-
	103,780.00	103,780.00
8 Funds Received from MHA for Training Programme for South African Officials		-
Opening Balance	-	276,799.00
Received during the year	-	-
	-	276,799.00
LESS : Utilization/Expenditure during the year	-	276,799.00
LESS : savings deposited to Govt. a/c	-	-
	-	-
9 Funds Received from USAID for Preparation of IRS Module		-
Opening Balance	400,000.00	-
Received during the year	-	600,000.00
LESS : Utilization/Expenditure during the year	-	200,000.00
	400,000.00	400,000.00
10 Funds Received from UNDP-GOI DRR Programme		-
Opening Balance	-	59,000.00
Received during the year	-	-
	-	59,000.00
LESS : Utilization/Expenditure during the year	-	59,000.00
	-	-
11 Funds Received from ICSSR for vulnerability Assessment and mitigation analysis for drought in Bundelkhand		-
Opening Balance	47,226.00	48,919.00
Received during the year	47,226.00	48,919.00
	47,226.00	1,693.00
LESS : Utilization/Expenditure during the year	47,226.00	47,226.00
TOTAL	2,453,782.14	3,106,239.14



SCHEDULE - '4' : INVESTMENT

PARTICULARS	As At 31.03.2015	As At 31.03.2014
	RS.	RS.
Fixed deposits with UCO. Bank (Staff Contributory Provident Fund)	32,442,792.00	25,062,771.00
Total	32,442,792.00	25,062,771.00

SCHEDULE - '5' : CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

PARTICULARS	As At 31.03.2015	As At 31.03.2014
	RS.	RS.
A. <u>CURRENT ASSETS</u>		
<u>Bank Balances with :</u>		
UCO Bank Account No. 1820020000924924	(9,145,340.01)	(11,968,795.01)
Balance in Auto Sweep Account	49,502,112.00	37,682,947.00
Bank Balances	40,356,771.99	25,714,151.99
B. <u>LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</u>		
Staff Advance	2,030.00	2,735.00
Sundry Debtor	1,036,917.00	993,799.00
Security Deposits	15,000.00	13,130.00
Tax Deducted at source recoverable	253,673.65	253,673.65
Advance for Contingent Expenses	150.00	1,000.00
Conveyance Advance	31,038.00	36,186.00
Festival Advance	38,298.00	25,248.00
Receivable From NCRMP Project	-	18,864.00
Receivable from NDMA- NSSP Programme	610,584.00	610,584.00
Cheque Issued but not presented for Fixed deposit	-	2,271,324.00
Total	42,344,462.64	29,940,695.64



SCHEDULE - '6' : GRANTS RECEIVED FROM MHA (DM-Division)

PARTICULARS	2014-15	2013-14
	RS.	RS.
Grant received from Ministry of Home Affairs under the Central Sector Scheme on National Disaster Management programme	100,000,000.00	90,000,000.00
TOTAL	100,000,000.00	90,000,000.00

SCHEDULE - '7': ESTABLISHMENT EXPENSES (MHA-Grant)

PARTICULARS	2014-15	2013-14
	RS.	RS.
Salary and Allowances	31,805,654.00	29,196,423.00
Leave Travel Concession/LTA	669,668.00	382,086.00
Bonus	75,988.00	82,896.00
Contribution to Provident Fund	1,643,011.00	1,528,171.00
Interest Accrued on Balance in Staff provident Fund	2,036,171.00	1,790,351.00
Gratuity	606,108.00	-
Medical	171,989.00	537,277.00
Tuition Fees	438,240.00	363,730.00
LSPC	411,067.00	875,670.00
TOTAL	37,857,896.00	34,756,604.00

SCHEDULE : '8' : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES (MHA-Grant)

PARTICULARS	2014-15	2013-14
	RS.	RS.
Repair and Maintenance	1,695,263.00	2,321,820.00
Postage	492,388.00	399,300.00
Printing and Stationery	732,983.00	609,925.00
Electricity & water charges	1,977,045.00	1,504,775.00
Miscellaneous Expenses	1,325,619.00	670,231.00
News papers and Periodicals	101,375.00	77,913.00
Telephone Expenses	652,590.00	554,779.00
Advertisement & Publicity	14,457,401.00	18,441,372.00
Domestic Travel	1,143,296.00	1,162,841.00
Foreign Travel	344,052.00	522,353.00
Professional charges	51,326.00	51,326.00
Rent, Rate & taxes	12,889,854.00	11,586,384.00
Bank Charges	23,108.00	2,883.00
Publication	1,619,954.00	264,389.00
Research & Development	965,372.00	813,590.00
TOTAL	38,471,626.00	38,983,881.00

SCHEDULE - '9' : EXPENDITURE ON TRAINING PROGRAMME (MHA-Grant)

PARTICULARS	2014-15	2013-14
	RS.	RS.
Training Programmes/Workshop Expenses	18,006,726.00	14,555,968.00
TOTAL	18,006,726.00	14,555,968.00

SCHEDULE - '10' : INTEREST EARNED

PARTICULARS	2014-15	2013-14
	RS.	RS.
Interest on Fixed Deposit (CPF)	2,595,108.00	2,078,938.00
Interest others	2,861,541.00	686,287.00
Fee from NPCDRR Programme	-	92,216.00
Fee from NPCBEERM Programme	-	226,905.00
Upsent Balance from ATI'S received	-	771,492.00
Sales Misc	-	37,800.00
TOTAL	5,456,649.00	3,893,638.00



NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT

SCHEDULE : '3' STATEMENT OF FIXED ASSETS AND DEPRECIATION FOR THE YEAR 2014 - 15

S.No.	Particulars	Rate	WDV as on 01/04/2014		Addition		Deduction	Total	Dep for the Year	WDV as on 31/03/2015
			Rs.		More than 180 Days	Less than 180 Days				
1	BOOKS	60%	408,133.35		279,924.00	111,067.00	-	799,124.35	446,154.35	352,970.00
2	OFFICE EQUIPMENT	15%	886,525.00		-	-	-	886,525.00	132,979.00	753,546.00
3	FURNITURE & FIXTURE	10%	2,434,840.80		264,398.00	183,649.00	-	2,882,887.80	279,106.80	2,603,781.00
4	PLANT & MACHINERY	40%	419,532.06		290,972.00	298,949.00	-	1,009,453.06	343,991.06	665,462.00
5	COMPUTER	60%	590,894.45		-	-	-	590,894.45	354,536.45	236,358.00
6	COMPUTER AND ACCESSORIES	60%	1,670.25		-	-	-	1,670.25	1,002.25	668.00
7	Land	0%	55,518,126.00		-	-	-	55,518,126.00	-	55,518,126.00
	Total		60,259,721.91		835,294.00	593,665.00	-	61,668,680.91	1,557,769.91	60,130,911.00



NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

SCHEDULE : - 11

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Significant Accounting Policies

- (a) The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention on cash basis and are in accordance with generally accepted accounting practices.
- (b) The Fixed Assets register is being maintained for the physical verification and all the fixed assets acquired under the project are capitalized in the books of account of the National Institute of Disaster Management in the respective financial year in which such asset was acquired. Fixed Assets are stated at cost of acquisition including the cost of installation if any reduced by depreciation charged up to the year. The depreciation is being provided on the fixed assets as per the rates specified under Income Tax Act.
- (c) Accounting policies not specifically mentioned are otherwise in consonance with generally accepted accounting practices.
- (d) Grant in Aid is being recorded in the books of account ,when the fund are received.
- (e) All Expenses are being booked in the accounts as and when they are incurred and paid.
- (f) Transaction denominated in foreign currency is accounted at the exchange rate prevailing on the Date of the transaction.
- (g) The management contributes to the Provident funds for its employees and also retains Contributions of the employees towards Provident Fund. However such CPF is neither deposited in statutory provident fund nor in any recognized provident fund. The institute invests the said fund with PSU banks in form of term deposit and the interest earned thereon is being deposited with Government Treasury. However the interest payable on CPF account is being provided in the Books of Account and charged from Annual Grants. This policy is being followed because institute has not received any recognition from central Record keeping agency. As soon as the institute receives the recognition from centre it will Deposit the PF amount with statutory provident funds.

2. Contingent Liabilities

Claim against the institute not acknowledge as debt – NIL



3. In the opinion of the management, the value of realization of current assets, loans and advances in the ordinary course of business would not be less than the amount at which they are stated in the Balance Sheet . Further provisions for all known liabilities have been made in the accounts.
4. As per directions of ministry of Home Affairs (DM Division) vide Letter No. 45-5/2008-NDm-IV/II dated 23rd March,2010 a separate Public Ledger Account(PLA) has been maintained and net savings generated from the projects including the interest earned from the deposits has been credited to the Consolidated Fund of India. Financial Statement for PLA for the financial year 2014-15 has been prepared separately.

For P. K. SINGHAL & CO.,

Chartered Accountants

Firm's Reg. No. 0050516

Praveen Kumar Singhal

(Partner)

M. No. 073882

For National Institute of Disaster Management

Dr. Santosh Kumar

(Executive Director)

S. S. Bisht

(Accountant)

Place: New Delhi

Date: 30th October, 2015

**PUBLIC LEDGRE ACCOUNT(PLA)
(NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT)
(Ministry of Home Affairs)**

PLA BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(Amount in Rs.)			
PARTICULARS	SCHE- DULE	31.03.2015	31.03.2014
		RS	RS
<u>CORPUS FUND AND LIABILITIES</u>			
CAPITAL AND RESERVE & SURPLUS	'1'	731,560.00	731,560.00
EARMARKED FUNDS	'2'	2,453,782.14	3,106,239.14
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'3'	575,224.00	535,235.00
TOTAL		3,760,566.14	4,373,034.14
<u>ASSETS</u>			
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES	'4'	3,760,566.14	4,373,034.14
TOTAL		3,760,566.14	4,373,034.14

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND
NOTES TO THE ACCOUNTS

In terms of Our Report on the even date attached.

For P K SINGHAL & CO.
Chartered Accountants
Firm's Reg No. 05051C



Place: New Delhi
Date: 30th October, 2015

For National Institute of Disaster Management


Dr. Santosh Kumar
Executive Director


S. S. Bisht
Accountant

PUBLIC LEDGRE ACCOUNT (PLA)
(NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT)
(Ministry of Home Affairs)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
	RS	RS
<u>INCOME</u>		
Sale of Journal	1,250.00	6,500.00
Interest Income	176,307.00	245,838.00
Misc. Receipt	95,754.00	122,542.00
TOTAL (A)	273,311.00	374,880.00
<u>EXPENDITURE</u>		
Bank Charges	214.00	294.00
Less: Trf Online Program Expenses a/c	-	294.00
TOTAL (B)	214.00	-
BALANCE BEING THE SURPLUS/DEFICIT (A-B)	273,097.00	374,880.00
Less: Savings transfer to PAO, MHA	273,097.00	374,880.00
BALANCE BEING THE SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO BALANCE SHEET	-	-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND
NOTES TO THE ACCOUNTS

In terms of Our Report on the even date attached.

For P K SINGHAL & CO
Chartered Accountants
Firm's Reg No. 05051C

CA P K SINGHAL
Partner
M.No. 073882

For National Institute of Disaster Management

Dr. Santosh Kumar
Executive Director

S. S. Bisht
Accountant

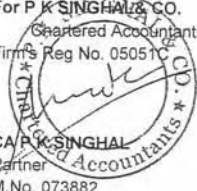
Place: New Delhi
Date: 30th October, 2015

PUBLIC LEDGER ACCOUNT (PLA)
(NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT)
(Ministry of Home Affairs)
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

PARTICULAR	31.03.2015		31.03.2014	
OPENING BALANCE				
UCO Bank (saving a/c)	4,373,034.14	4,373,034.14	7,402,565.14	7,402,565.14
RECEIPTS				
RECEIPTS DURING THE YEAR				
1 Receipt from WBI-online course receipts	667,752.00		504,448.00	
2 Receipt from USAID Project	-		600,000.00	
3 Receipt for Unspent Money received from Meghalaya Govt	272,127.00		-	
6 Receipt for NCRM Project	-		1,106,465.00	
7 Receipt from NIDM Main A/c	-		4,390,176.00	
		939,879.00		6,601,089.00
OTHER RECEIPTS				
1 Misc. receipts	95,754.00		122,542.00	
2 Sale of Journal	1,250.00		6,500.00	
3 Interest received	176,307.00	273,311.00	245,838.00	374,880.00
TOTAL		5,586,224.14		14,378,534.14
PAYMENTS				
PROJECT EXPENSES				
1 Consultancy Charges NCRMP Project	-		1,106,465.00	
2 Meeting Expenses for NCRMP Project	-		127,828.00	
3 PIU Running Cost NCRMP Project	-		19,184.00	
4 Salary for NCRMP Project	-		299,750.00	
5 Travel Expenses NCRMP Project	-		114,588.00	
6 MCD-Forensic investigation project expenses	131,892.00		-	
7 NHCD Plan - NDMA	-		-	
8 USAID Project Expense	-		200,000.00	
9 National Cyclone Risk Mitigation Project expenses-NDMA	-		-	
10 WBI-Online programme expenses	-		-	
11 Training Programme for South African Officials	-		276,799.00	
12 UNDP-GOI DRR Programme expenses	-		59,000.00	
13 SADKN Project	-		205,484.00	
14 Transfer to NCRMP Project	-		1,120,299.00	
15 ICSSR Drought Project	-		1,693.00	
16 Consultancy charges	-	131,892.00	-	3,531,090.00
OTHER EXPENSES				
1 Online Program Expenses	1,188,317.00		1,447,117.00	
2 Advance Given for NCRMP Expenses	-		-	
3 Loan & Advance Net	-		-	
4 Expense Payable	130,355.00		72,169.00	
5 Bank Charges	214.00		-	
6 Project Saving Paid to MHA	374,880.00	1,693,766.00	4,955,124.00	6,474,410.00
CLOSING BALANCE				
UCO Bank (saving a/c)	3,760,566.14	3,760,566.14	4,373,034.14	4,373,034.14
TOTAL		5,586,224.14		14,378,534.14

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND
NOTES TO THE ACCOUNTS

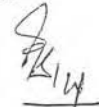
In terms of Our Report on the even date attached.

For P. K. SINGHAL & CO.
Chartered Accountants
Firm's Reg No. 050510

CA P. K. SINGHAL
Partner
M.No. 073882

Place: New Delhi
Date: 30th October, 2015

For National Institute of Disaster Management


Dr. Santosh Kumar
Executive Director


S. S. Bisht
Accountant

NATIONAL INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT (PLA)		
(Amount in Rs.)		
SCHEDULE -1 : CORPUS/CAPITAL FUND		
	31.03.2015	31.03.2014
	RS.	RS.
Opening Balance	731,560.00	731,560.00
TOTAL	731,560.00	731,560.00
SCHEDULE : '2' EARMARKED FUNDS		
PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
	RS.	RS.
1 <u>Funds Received from New Okhla Industrial Development Authority for preparation of 'Disaster Management Plan'</u>		
Opening Balance	770,249.00	-
<u>ADD : Received during the year</u>	-	770,249.00
	770,249.00	770,249.00
	770,249.00	770,249.00
2 <u>Funds Received from NDMA for Cyclone Risk Mitigation Project</u>		
Opening Balance	-	1,681,649.00
Received during the year	-	1,106,465.00
Add Advance given for Expenses	-	19,250.00
	-	2,807,364.00
<u>Less :utilization during the year</u>	-	1,687,065.00
<u>Less: amount transfer to separate a/c</u>	-	1,120,299.00
	-	-
3 <u>Funds Received from MOST for for Brain storming Climate Change Programme</u>		
Opening Balance	400,000.00	400,000.00
Received during the year	-	-
	400,000.00	400,000.00
4 <u>Funds Received from NDMA for Preparation of NH&CD Plan</u>		
Opening Balance	689,000.00	689,000.00
Received during the year	-	-
	689,000.00	689,000.00
5 <u>Funds Received from MCD for forensic investigation project</u>		
Opening Balance	131,892.00	380,211.00
Received during the year	-	-
Unutilised fund received from employee	-	689.00
	131,892.00	380,900.00
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	131,892.00	249,008.00
	-	131,892.00
6 <u>Funds Received from Online-WBI courses</u>		
Opening Balance	564,092.14	1,709,285.14
Received during the year	667,752.00	504,448.00
	1,231,844.14	2,213,733.14
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	1,188,317.00	1,649,641.00
	43,527.14	564,092.14
7 <u>Funds Received from SAARC for SADKN Project</u>		
Opening Balance	103,780.00	309,264.00
Received during the year	-	-
Savings reversed from Govt. A/c	-	-
	-	309,264.00
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	-	205,484.00
<u>LESS : savings deposited to Govt. a/c</u>	-	-
	103,780.00	103,780.00
8 <u>Funds Received from MHA for Training Programme for South African Officials</u>		
Opening Balance	-	276,799.00
Received during the year	-	-
	-	276,799.00
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	-	276,799.00
<u>LESS : savings deposited to Govt. a/c</u>	-	-
	-	-
9 <u>Funds Received from USAID for Preparation of IRS Module</u>		
Opening Balance	400,000.00	-
Received during the year	-	600,000.00
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	-	200,000.00
	400,000.00	400,000.00
10 <u>Funds Received from UNDP-GOI DRR Programme</u>		
Opening Balance	-	59,000.00
Received during the year	-	-
	-	59,000.00
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	-	59,000.00
	-	-
11 <u>Funds Received from ICSSR for vulnerability Assessment and mitigation analysis for drought in Bundelkhand</u>		
Opening Balance	47,226.00	48,919.00
Received during the year	-	-
	47,226.00	48,919.00
<u>LESS : Utilization/Expenditure during the year</u>	-	1,693.00
	47,226.00	47,226.00
TOTAL	2,453,782.14	3,106,239.14



SCHEDULE : '3' : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
	RS.	RS.
Projects savings payable to MHA	545,224.00	374,880.00
Earnest money security deposits	30,000.00	30,000.00
Expenses Payable	-	130,355.00
TOTAL	575,224.00	535,235.00

SCHEDULE : '4' CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
	RS.	RS.
A. <u>CURRENT ASSETS</u>		
Cash in hand	-	-
<u>Bank Balances with :</u>		
UCO Bank Account No. 6139	3,760,566.14	4,373,034.14
TOTAL	3,760,566.14	4,373,034.14





nidm

Towards a disaster free India

राष्ट्रीय अपदा प्रबंधन संस्थान

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

5बी आईआईपीए केम्पस, आई.पी. इस्टेट, महात्मा गांधी रोड़
नई दिल्ली-110002

Website: www.nidm.gov.in